सम्पादकीय

हरियाणा में बिछ गई चुनावी बिसात

पिछली बार 'किंगमेकर' रही जजपा के आजाद समाज पार्टी (आसपा) से गठबंधन के साथ ही हरियाणा में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। इनैलो और बसपा के बीच पहले ही गठबंधन हो चुका है। इनैलो-बसपा में 53-37 का सीट बंटवारा हुआ तो जजपा-आसपा में 70-20 का हुआ है। जाहिर है, यह देवीलाल परिवार में शक्ति-प्रदर्शन भी है, पर अब 'आप' के पास अकेले चुनाव मैदान में उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं। वैसे हरियाणा में सत्ता की जंग दरअसल 'हैट्रिक' करने और उससे बचने की जंग ही होगी। दूसरा शासनकाल पूरा कर रही भाजपा सत्ता की 'हैट्रिक' करना चाहेगी, जबकि 10 साल से सत्ता से वनवास झेल रही कांग्रेस अपनी परंपरा को 'हैट्रिक' से बचना चाहेगी। बाकी दलों की भूमिका एक-दो सीट जीत कर या 2-4 प्रतिशत वोट काट कर इस जंग को दिलचस्प बनाने की रहेगी। हरियाणा की राजनीति दशकों तक 3 चर्चित लालों बंसीलाल, देवीलाल और भजनलाल के इर्द-गिर्द घूमती रही। देवीलाल और बंसीलाल के दलों से गठबंधन में भाजपा जिस हरियाणा में राजनीति करती रही, उसी में दस साल से सत्ता पर काबिज होना छोटी उपलब्धि नहीं। आज तीनों चर्चित लाल-परिवार के कुछ सदस्य भी भाजपा का झंडा उठाए हुए हैं। 2014 में इनैलो ने 19 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी दल का दर्जा हासिल किया था, जबकि 10 सांसद से सशक्त कांग्रेस तीसरे स्थान पर फिसल गई थी, लेकिन 2019 आते-आते सब कुछ बदल गया।

देवीलाल परिवार में विभाजन से जजपा जन्मी और इनैलो में ऐसी भगदड़ मची कि कांग्रेस को मुख्य विपक्षी दल का दर्जा मिल गया। अब 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले जजपा में भी वैसी ही भगदड़ है। 10 में 6 विधायक उसे अलविदा कह चुके हैं। कभी भी यह संख्या 7 हो सकती है। हाल के लोकसभा चुनाव में जजपा उम्मीदवार जमानत तक नहीं बचा पाए, जबकि 10 में से 5 लोकसभा सीटें जीत कर कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया। विधानसभा क्षेत्रों की दृष्टि से देखें तो कांग्रेस ने कुल 90 में से 46 में बढ़त हासिल की, जबकि भाजपा ने 44 में। फिर भी हर चुनाव और उसके मुद्दे अलग होते हैं। 2019 में ही भाजपा ने लोकसभा की सभी 10 सीटें जीतीं, लेकिन चंद महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में 46 सीटों का बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाई और 10 सीटें जीतने वाली नई-नवेली जजपा की सत्ता में भागीदारी की लॉटरी खुल गई। इसलिए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 46 विधानसभा क्षेत्रों में मिली बढ़त को ज्यादा भाव नहीं दिया जाना चाहिए। चुनाव से पहले होने वाले दलबदल का लाभ भाजपा और कांग्रेस, दोनों को हुआ है, लेकिन 10 साल पहले जिस अंतर्कलह के चलते कांग्रेस की दुर्गति हुई थी, उससे वह आज भी मुक्त नहीं। 10 साल मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष और उन्हीं की पसंद से उदयभान को प्रदेश अध्यक्ष बना कर आलाकमान ने उन्हें 'फ्री हैंड' का ही संदेश दिया है। परिणामस्वरूप हुड्डा विरोधियों के समक्ष कमला थामने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की फेहरिस्त लंबी है, लेकिन अभी भी कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुर्जेवाला के रूप में 2 दिग्गज ऐसे मौजूद हैं, जिनकी आलाकमान तक सीधी पहुंच है। दोनों ही राष्ट्रीय महासचिव हैं।

ममता का विरोध इसी प्रकार जारी रहा तो उसकी आंच पश्चिम बंगाल से देश के हर कोने में पहुचेंगी!

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आरजी कर की घटना के खिलाफ उमड़ा आक्रोश अब ममता बनर्जी सरकार के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है। एक विश्लेषक विश्वनाथ घोष कहते हैं, दरअसल, शुरुआती गलतियों के कारण आम लोगों में यह संदेश गया है कि ममता बनर्जी सरकार इस मामले की लीपापोती का प्रयास करना चाहती है। इस विरोध प्रदर्शन में सियासत का रंग भी गाढ़ा होने लगा है। सीपीएम और कांग्रेस के अलावा बीजेपी और आरएसएस के लोग भी इसमें शामिल हो गए हैं। ऐसे में इस मामले के लंबा खिंचने के आसार हैं। सीबीआई को इस घटना की जांच सौंपने के बावजूद सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही है।

अशोक भाटिया

कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और फिर उनकी हत्या के बाद देशभर में विरोध की जो चिंगारी सुलगी है, कोलकाता उसका एपि सेंटर है। 9 अगस्त को सामने आई घटना के बाद से जारी विरोध प्रदर्शन अब तक थमा नहीं है, बल्कि इसका दायरा और लोगों के बीच आक्रोश लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पहले कोलकाता सहित देशभर में डॉक्टरों का प्रदर्शन, फिर इस मामले में छात्र संगठनों के विरोध प्रदर्शन ने लोगों के गुस्से को आंदोलन की शक्ल दे दी है, उसके बाद बुधवार को भाजपा बंद के बाद यह आंदोलन लाठी और गोली व बड़े तकरार तक पहुँच गया। ममता व भाजपा के बीच 'वाक् -युद्ध'की जंग छिड़ गई । कोलकाता से आए, कुछ जानकार लोग बताते है कि कोलकाता में ममता बनर्जी के खिलाफ लोगों का ऐसा गुस्सा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। लोग ममता से बेहद नाराज हैं। नाराज़गी की सबसे बड़ी वजह लेडी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के बाद प्रिंसिपल को बचाने की कोशिश, आधी रात में सबूतों को मिटाने की कोशिश और फिर पुलिस कमिश्नर की दादागिरी। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होती गईं कि लोगों का गुस्सा बढ़ता गया और अब ये नाराजगी सड़कों पर दिखाई दी। इस प्रोटेस्ट को संयम के साथ कंट्रोल करने की बजाय कोलकाता पुलिस ने बर्बरता का रास्ता चुना जिससे लोगों में आक्रोश और बढ़ गया। आज भी इस बात के संकेत मिले कि ममता बनर्जी नरम होने को तैयार नहीं हैं। उनकी पार्टी के लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर छात्रों के मार्च व भाजपा के बंद को फेल करवाने में पूरा जोर लगा दिया था । कोलकाता रेप-मर्डर केस को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी बयान आया है । उन्होंने कहा कि मैं घटना को लेकर निराश और डरी हुई हूं। ऐसी घटनाओं को भूल जाना समाज की खराब आदत है। उन्होंने आगे कहा कि जब स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स और नागरिक कोलकाता में प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो अपराधी दूसरी जगहों पर शिकार खोज रहे थे। कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों पर इस तरह के अत्याचारों की इजाजत नहीं दे सकता। देश के लोगों का गुस्सा जायज है, मैं भी गुस्से में हूं।

गौरतलब है कि रेप और हत्या की घटना की आंच अब पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े त्योहार दुर्गा पूजा तक भी पहुंचने लगी है। कोलकाता में यौनकर्मियों के सबसे प्रमुख संगठन दुर्बार महिला समन्वय समिति ने जहां दुर्गा प्रतिमा के लिए सोनागाछी इलाके की मिट्टी देने से मना कर दिया है वहीं कई पूजा आयोजन समितियों ने इस घटना के विरोध में सरकार की ओर से मिलने वाली अनुदान की रकम ठुकरा दी है। ज्ञात हो कि कोलकाता में यौनकर्मियों के सबसे बड़े मोहल्ले सोनागाछी की मिट्टी के बिना दुर्गा प्रतिमा का निर्माण नहीं किया जा सकता। आखिर इतने पवित्र आयोजन के लिए समाज में उपेक्षित समझे जाने वाले रेड लाइट इलाके की मिट्टी क्यों ली जाती है? एक वेहद पौराणिक मान्यता के मुताबिक बहुत पहले एक यौनकर्मी देवी दुर्गा की बहुत बड़ी उपासक थी। लेकिन समाज से बहिष्कृत उस यौनकर्मी को तरह-तरह की यातनाओं का सामना करना पड़ता था। माना जाता है कि अपनी भक्त को इसी तिरस्कार से बचाने के लिए दुर्गा ने स्वयं आदेश देकर उसके आंगन की मिट्टी से अपनी मूर्ति स्थापित करवाने की परंपरा शुरू करवाई थी। साथ ही देवी ने उसे वरदान भी दिया था कि उसके यहां की मिट्टी के उपयोग के बिना प्रतिमाएं पूरी नहीं होंगी। लेकिन यौनकर्मियों के सबसे प्रमुख संगठन दुर्बार महिला समन्वय समिति ने इस बार अपने इलाके की मिट्टी देने से इंकार कर दिया है। संगठन ने कहा है कि आर.जी. कर की घटना में न्याय नहीं मिलने तक वो अपने इलाके की मिट्टी किसी भी मूर्तिकार को नहीं देगा। संगठन की अध्यक्ष विशाखा लस्कर ने डीडब्ल्यू से कहा, दुर्गा शक्ति का प्रतीक हैं। लेकिन राज्य में जब महिला के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है तो हम आखिर दुर्गा प्रतिमा के निर्माण के लिए मिट्टी क्यों दें? वह कहती हैं कि बंगाल में पूरे साल महिलाओं के साथ अत्याचार और यौन उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं। आर.जी. कर की घटना हमारे सामने है। ऐसे में चार दिनों तक मां दुर्गा की आराधना करना बेमतलब है। वह भी महिला शक्ति का ही स्वरूप हैं। विशाखा कहती हैं कि मूर्ति के लिए मिट्टी देने से मना करने का आरजी कर की घटना में त्वरित न्याय के साथ ही हम रेड लाइट इलाके में रहने वाली यौनकर्मियों को सम्मान की निगाह से देखने की भी मांग कर रहे हैं। अमूमन सिर्फ मिट्टी लेने के दौरान ही हमें सम्मान की निगाह से देखा जाता है। बाकी पूरे साल हम उपेक्षा झेलने पर मजबूर हैं। मांग पूरी नहीं होने तक किसी को मिट्टी नहीं दी जाएगी। राज्य की ममता बनर्जी सरकार हर साल तमाम दुर्गा पूजा समितियों को आर्थिक मदद करती है। ममता बनर्जी सरकार ने वर्ष 2017-18 में दुर्गा पूजा का आयोजन करने वाली करीब 43 हजार समितियों को सरकारी अनुदान देने के लिए दुर्गा भंडार योजना शुरू की थी। पहली बार वह रकम 10-10 हजार थी। बीते साल यह 70 हजार थी। जो अब बढ़ कर 85 हजार हो गई है।

इससे सरकारी खजाने पर करीब 363 करोड़ का बोझ पड़ता है लेकिन आरजी कर की घटना के विरोध में हुगली जिले की आधा दर्जन से ज्यादा आयोजन समितियों ने सरकारी अनुदान लेने से इंकार कर दिया है। हुगली की तीन आयोजन समितियों - उत्तरपाड़ा महिला पूजा आयोजन संघ, उत्तरपाड़ा शक्ति संघ और आपनादेर दुर्गापूजा - ने तो पहले ही मना कर दिया था। अब उसी जिले की कोन्नगर सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति के अलावा तीन अन्य समितियों ने भी सरकारी सहायता का चेकबुक करने का फैसला किया है।इस आयोजन समिति की सदस्या सोमा चक्रवर्ती डीडब्ल्यू से कहती हैं, महिलाओं का सम्मान उत्सव से ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन अब यह सम्मान सुरक्षित नहीं है। हम राज्य की तमाम महिलाओं की सुरक्षा चाहती हैं। आरजी कर मामले में न्याय नहीं मिलने तक हम सरकारी सहायता का चेकबुक जारी रखेंगे। इन समितियों ने जिला प्रशासन को भी अपने फैसले की लिखित सूचना दे दी है। उसके बाद अब सबसे इलाकों के नगर पालिका अध्यक्ष ने अनुदान लेने के इच्छुक समितियों से आवेदन करने को कहा है। यहां इस बात का जिक्र प्रासंगिक है कि ममता बनर्जी हर साल एक सौ से ज्यादा पूजा पंडालों का उद्घाटन करती रही है। दरअसल इस समय जब सभी दलों को शांति बनाए रखने की जरूरत है, लेकिन कोलकाता में बुधवार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए धमकी दे दी कि अगर बंगाल में आग लगाई गई, तो दिल्ली, यूपी, बिहार, ओडिशा, नॉर्थ-ईस्ट सब जलेंगे। इस पर दिल्ली, यूपी, बिहार, ओडिशा, नॉर्थ-ईस्ट के लोग ममता पर और भड़क गए है । अब पता नहीं यह आग कब बुझेगी।

शख्सियत

सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं,बीते हुए कल के दौर को भूल जाना ही व्यक्ति को आने वाले कल के लिए रोशनी पैदा करता है। इस जीवन पथ पर सभी को चलना होता है कोई थक के हार जाता है कोई हार के भी जीत जाता है.....

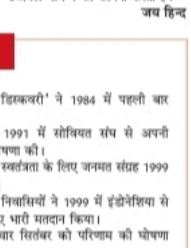

दिनेश एम.एन
(वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी)

नमस्कार दोस्तों हमारे आज के शख्सियत कॉलम के स्टार हैं दबंग आईपीएस अधिकारी दिनेश एमएन। जोकि फिलहाल अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,अपराध शाखा,राजस्थान जयपुर के पद को सुशोभित कर रहे हैं। 6 सितंबर सन 1971 को कर्नाटक में जन्में दिनेश एमएन ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेली कम्युनिकेशन से बीई की हुई है। ट्रेनिंग के दौरान एएसपी दौसा, एएसपी गांधी नगर, जयपुर लगे। इसके बाद पुलिस अधीक्षक, करौली। पुलिस अधीक्षक, सवाई माधोपुर। पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर। पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं। पुलिस अधीक्षक उप निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, राजस्थान, जयपुर। पुलिस अधीक्षक, उदयपुर। पुलिस अधीक्षक, अलवर लगे। एक मामले में तत्कालीन सरकारों से संघर्ष करते हुए हारे नहीं और अपने जीवन के सर्वोत्तम साल साल जेल में बिताए। ये टूटे नहीं ना ही परेशान हुए बल्कि और भी मजबूत बने और जब सत्य जीता तो एक बार फिर सरकार को इस जाँबाज अधिकारी के नेतृत्व की आवश्यकता हुई। इनके जज्बे की पूरी पुलिस कौम कायल है। सच में संघर्ष करते करते ईसान या तो थक जाता है या फिर हार मान लेता है लेकिन इस अधिकार के हौसलें इतने बुलंद थे कि निहत्थे सत्य के आगे हथियारबंद असत्य हार गया। आखिर अंते ही बड़े पदों पर इन्हें तैनात किया गया। जहां बड़े-बड़े बदमाशों को इन्होंने उनके सही ठिकाने पहुँचाया। प्रबंध निदेशक, राजसिको, जयपुर। पुलिस महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। पुलिस महानिरीक्षक, एसओजी जयपुर। पुलिस महानिरीक्षक, बीकानेर रेंज, बीकानेर। पुलिस महानिरीक्षक, आसूचना, जयपुर। पुलिस महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,द्वितीय, जयपुर। जैसे पदों को सुशोभित किया और फिलहाल अपराधियों को नाक में नकेल डालने के लिए एडिशनल डीजी क्राईम लगे हुए हैं। जहां इनके आने के बाद राजस्थान में गैंगवार व सयुक्त अपराध के काफी कमी आई है। दैनिक बढ़ता राजस्थान की टीम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है।

जय हिन्द

आज का इतिहास

30 अगस्त की महत्वपूर्ण घटनाएँ

- दारा शिकोह को 1659 में औरंगजेब द्वारा फाँसी दी गयी।
- थिलियम पेन इंग्लैंड से रवाना हुए और बाद में 1682 को उन्होंने अमेरिका में पेनसिल्वेनिया कॉलोनी की स्थापना की।
- जनरल बेनेडिक्ट अर्नोल्ड ने 1780 को वेस्ट प्वाइंट फोर्ट में ब्रिटिश सेना के सामने आत्मसमर्पण करने का वादा किया।
- न्यूयॉर्क शहर का दूसरा दैनिक समाचार पत्र 'डेली एडवर्टाइजर' 1806 में आखिरी बार प्रकाशित किया गया।
- उत्तर-पूर्वी टर्क और केको के उष्णकटीबंधीय आँधी के साथ तूफान का मौसम 1923 में शुरू हुआ।
- द इंडिपेंडेंस ऑफ़ इंडिया लीग की भारत में 1928 को स्थापना।
- जर्मनी पर मित्र राष्ट्रों के सैन्य नियंत्रण वाली नियंत्रण परिषद की स्थापना 1945 में हुई।
- भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉ भीमराव आम्बेडकर के नेतृत्व में एक समिति का गठन 1947 में किया गया।
- फिलीपींस और अमेरिका ने 1951 में एक रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किये।
- नॉटिंग हिल कार्निवल में 1976 को भड़के दंगे में दो सौ से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हो गए थे।
- फलस्तीनी मुक्ति संगठन के नेता यासिर अराफात ने 1982 में बेरुत स्थित मुख्यालय को एक दशक के बाद छोड़ दिया था।
- अंतरिक्ष यान 'डिस्कवरी' ने 1984 में पहली बार उड़ान भरी।
- अंजरबैजान ने 1991 में सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की।
- पूर्वी तिमोर की स्वतंत्रता के लिए जनमत संग्रह 1999 में सम्पन्न हुआ।
- पूर्वी तिमोर के निवासियों ने 1999 में इंडोनेशिया से आजादी के लिए भारी मतदान किया।
- संयुक्त राष्ट्र ने चार सितंबर को परिणाम की घोषणा की।
- युगोस्लाविया के पूर्व राष्ट्रपति स्लोबदान मिलोसेविच के खिलाफ 2001 को युद्ध अपराधों के मामले में आरोप तय किए गए।
- ताइवान में 2002 को भूकम्प के झटके महसूस किये गए।
- कोनोको इंक और फिलिप्पा पेट्रोलियम ने 2002 में विलय कर कोनोकोफिलिप्पा बनायी।
- यह अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा कंपनी और दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनिंग कंपनी थी।
- आस्ट्रेलिया ने विश्व नौकायन में स्वर्ण पदक जीता।
- समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव 2003 में तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने।
- बांग्लादेश सरकार ने 2007 में नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुस के सम्मान में डाक टिकट जारी किया।
- जर्मनी के दो वैज्ञानिक गुंटर निमिज्ज और आल्फ्रोंस स्टालहोफेन ने 2007 में अल्बर्ट आईंसटीन के सापेक्षता के सिद्धान्त को गलत ठहराने का दावा किया।

विशेष आलेख

भूख नैसर्गिक,प्राकृतिक सच। कैसे रुके अन्न की बर्बादी।

संजीव ठाकुर

मनुष्य,जानवर,पशु-पक्षी यहां तक पेड़ पौधों और जलचर भूख की नैसर्गिक प्राकृतिक प्रक्रिया के सच से गुजर रहे हैं। दुनिया का संघर्ष ही इस भूख को मिटाने हेतु ही कायम है। प्राकृति की संरचना ही इस कदर की निरंतर पूर्ति के लिए प्रयासरत है। संयुक्त राष्ट्र संघ की फूड वेस्ट इंडेक्स सर्वे के अनुसार 2024 में हर एक नौ में से एक व्यक्ति पर्याप्त भोजन तथा आवश्यक पोषक तत्वों से वंचित रह जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार पूरी दुनिया में एड्स, मलेरिया ,टीबी और करोना 2023 में जितने व्यक्ति की मृत्यु हुई है उससे कहीं ज्यादा लोग भुखमरी से ग्रस्त होकर भगवान को प्यारे हो गए है । संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों के अनुसार ही पूरी दुनिया में गरीबों की संख्या लगभग 140 करोड़ है और दूसरी तरफ दुनिया में सर्वाधिक प्रभावित गरीब व्यक्ति भारत में निवासरत हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत फूड वेस्ट इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 93 करोड़ लाख टन खाना कूड़े करकट के रूप में बर्बाद हुआ है। जिनमें घरों से निकला हुआ भोज्य पदार्थ का कूड़ा करकट लगभग 55प्रतिशत, होटल रेस्टोरेंट एवं अन्य बाजार के भोजन बेचने वालों 24प्रतिशत तथा अन्य क्षेत्र में लगभग 22 से 24प्रतिशत भोजन बर्बाद हुआ है। पूरे विश्व में भोजन के बर्बाद होने से भुखमरी के आंकड़े और भी बढ़ गए हैं। बड़ी हैरानी और हैरतअंगेज बात यह है कि पूरे विश्व में प्रति व्यक्ति 1 साल में लगभग 122 से 124 किलोग्राम भोजन बर्बाद कर देता है। भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष 50 किलो ,अफगानिस्तान 82 किलो, नेपाल 79 किलो ,श्रीलंका 76 किलो, पाकिस्तान 74 किलो और भूटान जैसा छोटा देश 79 किलो भोजन बर्बाद करता है। भोजन बर्बाद करने की एवं भोजन को कूड़ा करकट बनाकर फेंकने की कुसंस्कृति ही लगातार कई देशों को गरीब से गरीबतर बनाते जा रही है। पूरे विश्व स्तर पर विकसित विकासशील एवं गरीब देश भोजन की निर्मम बर्बादी करते आ रहे हैं। एक तरफ संयुक्त राष्ट्र संघ भुखमरी उन्मूलन के लिए अभियान छेड़ कर रखा है जिसका नाम दिया गया है जीरो हंगर यानी कि भुखमरी शून्य स्तर पर लाने का प्रयास जारी है पर इस अभियान में विकासशील ,गरीब तथा विकसित देश अपने देशों में खाद्य पदार्थ के अपशिष्ट को फेंक कर अबरोध पैदा करने में कोई कमी बेसी नहीं छोड़ रहे हैं। वर्तमान परिदृश्य में कुछ विकासशील देशों में बढ़ती जनसंख्या और लगातार गिरते अनाज के उत्पादन के साथ-साथ अन्न की निर्मम बर्बादी की वजह से दुनिया भर में भूख और भुखमरी से पीड़ित होने वाली समस्याओं तथा भुखमरी से मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यह भारत देश का दुर्भाग्य है की कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार कि भारत में करीब 50 हजार करोड़ की कीमत का हर साल अपशिष्ट के रूप में अन्न बर्बाद होता है, शायद आपको अंदाजा ना हो कि इतना अनाज बिहार जैसे बड़े राज्य की जनसंख्या को 1 वर्ष तक अन्य की आपूर्ति कर सकता है। भोजन की बर्बादी एक सामाजिक अपसंस्कृति एवं कुसंस्कृति की तरह व्याप्त होती जा रही है, । भोजन की इस तरह बर्बादी एक तरह से कुसंस्कृति को बढ़ावा देकर एक सामाजिक बुराई के रूप में सामने आ रही है। अनाज को थाली या कूड़ेदान में फेंक देने से उससे केवल अनाज की बर्बादी नहीं होती बल्कि ऊर्जा, जल ,पोषक तत्वों की बर्बादी होती है। अलावा इसको पैदा करने वाले किसानों को भी एक तरह निराशा का सामना करना पड़ता है अनाज उत्पादन के लिए जितनी मेहनत मशक्कत किसान करता है उसके अलावा खेती की जमीन बढ़ाने के लिए वनों का विनाश भी बड़ी तेजी से हो रहा है एवं उस जमीन की उर्वरा शक्ति का भी निरंतर क्षरण हो रहा है ,लगातार रसायनिक खादों रासायनिक तत्वों के उपयोग के कारण मिट्टी की गुणवत्ता तो खराब हो ही रही है। इसके अलावा पर्यावरण एवं वातावरण भी खराब होता जा रहा है एवं खाद्य पदार्थ के अपशिष्ट छोड़ने से जानवरों की खाने से जानवरों को भी जीवन का खतरा बनते जा रहा है। इससे अन्य संक्रामक बीमारियां भी फैलने का खतरा बढ़ने लगा है। अनाज को अपशिष्ट के रूप में बर्बाद करने से न सिर्फ अनाज बर्बाद होता है बल्कि किसान की मेहनत जमीन का क्षरण उसमें लगने वाली सिंचाई के लिए पानी की बर्बादी एवं समय का दुरुपयोग भी माना जाता है। हमारे द्वारा जो भोजन का अपशिष्ट पदार्थ कूड़ेदान में छोड़ दिया जाता है उसकी वजह से वैश्विक अनुसंधान से यह बताया गया है की ग्रीन हाउस गैस ने 10 से 15त्न तक का इजाफा होता है खराब पदार्थों से गैस उत्सर्जन के कारण वैश्विक स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग का भी खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। पदार्थ को छोड़ने से वातावरण दूषित होता है एवं संक्रामक बीमारियां न सिर्फ जानवरों में बल्कि इंसानों में भी तेजी से फैलने लगती है एवं इंसान की मौत तक होने लगी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की ताजा रिपोर्ट के अनुसार यदि भोजन के अपशिष्ट पदार्थ इसी तरह थोड़े जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा बढ़ सकता है एवं मनुष्य घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर हो सकता है।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई दिनों तक्रारों को दूर करेंगे। यह आप पर लक्ष्मी की कृपा बनी रहने के लिये आपको लोहान के दीये जलाने होंगे है, अगर आपके सितारे बुलंद होंगे और दुकानें तरक्की, आपको दिल खोल के लक्ष्मीजी लक्ष्मी देंगी। तब ही किसी बच्चों एवम में और अधिक खुशी को खुशखबरी तथा स्वास्थ्यलाभ आपके घर में समस्या करेंगे, अधिक परेशानियां लगेंगे में भी, आप एक लक्ष्मीजी की कृपा और कमाती में लक्ष्य प्रदान करेंगे

मेष

स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। प्रभु स्मरण से मन हल्का होगा। आज का दिन मनोरंजन और मौज-मस्ती में व्यतीत होगा। परिजनों या मित्रों के साथ घूमने या फिल्म देखने जाने की संभावना है। आप अच्छा भोजन ग्रहण करेंगे।

वृष

आज आपको कोई महत्त्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना चाहिए। गलत जगह खर्च करके या अत्यधिक काम के कारण मन में बेचैनी का अनुभव होगा। ऑफिस में आपका प्रभाव बढ़ेगा। मित्रों और खेलीजनों से मिलकर आनंद का अनुभव करेंगे।

मिथुन

सुंदर वस्त्रालंकार या नए वाहन खरीदने का योग है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। व्यापार में भागीदारी से लाभ प्राप्त कर सकेंगे। किसी नए व्यक्ति के प्रति आकर्षण का अनुभव होगा। आपके घर में आनंद का वातावरण रहेगा।

कर्क

आज आप पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलकर घरेलू मामलों के संबंध में विचार विमर्श करेंगे। घर को नए सिरे से योजनाबद्ध करके आप उसे एक नया स्वरूप देंगे। महिलाओं तथा माता की तरफ से लाभ होने की संभावना है। पारिवारिक जीवन में आनंद छाया रहेगा।

सिंह

कार्यभार के कारण आपके चिंतित होने की संभावना है। आज आप विदेश में बसने वाले मित्रों या खेलीजनों के अच्छे समाचार पाकर आनंद अनुभव कर सकेंगे। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा समय है।

कन्या

प्रवास या धार्मिक स्थान पर जाने का योग है। ऑफिस में काम की अधिकता रहेगी। आपको अपने मिजाज को काबू में रखना पड़ेगा, ताकि कोई समस्या न हो। बीमार व्यक्ति आज कोई नई उपचार पद्धति न अजमाएं। ऑपरेशन न कराएं।

तुला

आपको बीमारी से राहत मिलेगी। नतिहाल से अच्छे समाचार मिलेंगे। इससे लाभ होगा। आप विरोधियों को परास्त कर सकेंगे। आज संतान सम्बन्धी मामलों को लेकर चिंता रहेगी। विद्याध्ययन के लिए समय अनुकूल नहीं है।

वृश्चिक

पारिवारिक सदस्यों के साथ आपका समय आनंद और उत्साह में व्यतीत होगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपको मान-सम्मान प्राप्त होगा। उसके कारण खुशी का अनुभव होगा। ऑफिस में सहकर्मी आपकी मदद करेंगे।

धनु

आज आपको बौद्धिक वाद-विवाद से दूर रहना चाहिए। प्रेमीजनों को प्रणय में सफलता मिलेगी। प्रिय व्यक्तियों के साथ की मुलाकात से आनंद का अहसास होगा। आज अत्यधिक भावुकता आपके मन को आहें बनाएगी।

मकर

महिला और माताजी से संबंधित चिंताएं रहा करेंगी। प्रवास के लिए उचित समय नहीं है। इसलिए आज प्रवास का विचार बदलने की सलाह दी जाती है। छतों में पीड़ा का अनुभव होगा। जमीन या संपत्ति के मामले में सावधान रहें।

कुंभ

विरोधी अपनी चाल में सफल नहीं हो पाएंगे और आपको लोकप्रियता में वृद्धि होगी। आज आपका मनोबल दृढ़ न होने के कारण निर्णय लेने में तकलीफ होगी। सुस्विपूर्ण भोजन का आनंद ले सकेंगे तथा अच्छे वस्त्रालंकार पहनने का अवसर प्राप्त होगा।

मीन

विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता की कमी महसूस होगी। आपका आज का दिन आनंद और खुशी के पलों में व्यतीत होगा। आप नया कार्य शुरू कर सकेंगे। सहोदरों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। भाग्य में वृद्धि हो सकती है। आप तन-मन से स्वस्थ रहेंगे।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कमलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,इण्डस्ट्रीयल एरिया खण्डका,जिला कोटा (राज.) से मुद्रित एवं 188/ 116 "ज्योति" सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-तनुजा चतुर्वेद* । प्रधान संपादक-राव विनास विजयवर्गीय मो. 9414248258, 9214048888,जयपुर फोन नं.0141-2796794,795 ठौक कार्यालय-साईपास सिवाई, टोंक फोन नं.01432-244881 सिवाई 01438-222201,202,203 अलवर कार्यालय-पेहलाद सिंह का नोहर,अलवर मो. 7733000123,कोटा कार्यालय-छावनी मेन रोड,कोटा मो.9414823448 । ई मेल-badhatarajasthan@yahoo.com *पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार

चिंतन

कांग्रेसी सीएम का शीर्ष कोर्ट पर आक्षेप निंदनीय

सियासत में सुप्रीम कोर्ट को घसीटना उचित नहीं है। इससे न्याय के मंदिर की साख पर आंच आएगी। उच्चतम न्यायालय के किसी भी फैसले को राजनीतिक चश्मे से देखना राजनीतिक अपरिपक्वता है। जब इंसाफ के सभी द्वार बंद हो जाते हैं तो लोग सर्वोच्च अदालत की दर पर जाते हैं। देश के आवाम की आस्था सुप्रीम कोर्ट पर है, हमारे नेताओं को इस आस्था को बरकरार रखने में मदद करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के एक बयान पर उन्हें जमकर फटकार लगाई है। दिल्ली शराब नीति घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के. कविता को जमानत दे दी। कांग्रेसी सीएम रेवंत ने इसे बीआरएस और बीजेपी की डील बताया था। इस पर जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने रेवंत रेड्डी के वकील मुकुल रोहतगी से पूछा- 'क्या आपने अखबार में पढ़ा कि उन्होंने (रेवंत) क्या कहा? उसे पढ़िए।' कोर्ट ने कहा- सियासी लड़ाई में कोर्ट को घसीटना ठीक नहीं है। कोर्ट नेताओं से पूछकर फैसले नहीं सुनाती। ऐसे बयान लोगों के मन में आशंका पैदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट 2015 के कैश-फॉर-वोट घोटाले से जुड़े केस को भोपाल ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी एक आरोपी हैं। याचिका बीआरएस विधायक गुटकंडला जगदीश रेड्डी ने लगाई है। मई 2015 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने रेवंत रेड्डी को विधान परिषद चुनावों में टीडीपी उम्मीदवार को समर्थन करने के बदले 50 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। रेवंत, तब तेलुगु देशम पार्टी में थे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति घोटाले में 5 महीने से जेल में बंद के. कविता को 27 अगस्त को जमानत दे दी थी। कविता की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- महिलाओं के प्रति संवेदनशील रहें अदालतें। कांग्रेस नेता सीएम रवंत रेड्डी तेलंगाना की राजनीति कर सकते हैं, बीआरएस व भाजपा पर राजनीतिक आरोप लगा सकते हैं, लेकिन इस सब में सुप्रीम कोर्ट की छवि खराब करना एक सीएम को शोभा नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कई बार कहा है कि उनके फैसले की समालोचना से उसे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन शीर्ष अदालत के फैसले के पीछे की नीयत पर शक करना एक संवैधानिक संस्था की प्रतिष्ठा को धूमिल करना है। देश में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से कई बार नजीर पेश की है, तो कई बार देश को दिशा दी है। जो काम हमारी विधायिका नहीं कर सकी है, वह सुप्रीम अदालत ने किया है। सरकार किसी भी दल की रही हो, सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा संविधान की रक्षा की है, न्याय की गरिमा की रक्षा की है। सुप्रीम कोर्ट के अनगिनत फैसले हैं, जिसने देश को नई दिशा दी है। कोई भी दल हो, कोई भी राजनेता हो, उन्हें सुप्रीम कोर्ट को लेकर अनर्गल टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। खासकर कांग्रेस नेता सीएम रेवंत रेड्डी को तो खुद शर्मसार होना चाहिए कि उन पर ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, उन्हीं के मामले में सुनवाई हो रही है और वे खुद शीर्ष अदालत के फैसले को लेकर राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं। सीएम रेवंत रेड्डी को अपने ऊपर लगे करप्शन के आरोपों पर शर्मिंदा होना चाहिए। कांग्रेस सरकार पर पूर्व में आदर्श, टूजी, कोल ब्लॉक, स्पेक्ट्रम, राष्ट्रमंडल खेल आदि अनेक घोटालों के आरोप आयद हो चुके हैं। देश के राजनेताओं व सरकार में आसीन नेताओं को अपनी राजनीति के लिए अदालत की निष्ठा पर आक्षेप नहीं लगाना चाहिए, यह निंदनीय है।

दो टूक
डा. विशेष गुप्ता

महिला उत्पीड़न पर राष्ट्रपति की पीड़ा

राष्ट्रपति महोदया की महिला उत्पीड़न को लेकर यह पीड़ा अनायास ही नहीं है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की हालिया रिपोर्ट भी बताती है कि यहां 16 मिनट में एक यौन दुष्कर्म घटना होती है। साथ ही प्रत्येक घण्टे महिलाओं के विरुद्ध 50 अपराध घटित होते हैं। इनमें 10 फीसदी से भी अधिक यौन दुष्कर्म की घटनाएं 18 साल से कम उम्र के नाबालिगों के साथ घटित होती हैं। कहना न होगा कि आज देश व प्रदेशों के मुख्तलिफ हिस्सों में मासूम लड़कियों व महिलाओं के साथ घटने वाली यौन उत्पीड़न की वारदातों ने देश व समाज को झकझोर कर रख दिया है। लगता है कि निर्भया यौन उत्पीड़न की घटना के बाद समाज की सोच में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है।

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या पर राष्ट्रपति की पीड़ा ध्यान देने योग्य है। उन्होंने बहुत दर्द भरे शब्दों में कहा कि मैं निराश और भयभीत हूं। नौ अगस्त को कोलकाता में घटित इस दर्दनाक घटना के बाद उनका यह पहला बयान है। उन्होंने स्पष्ट लिखा कि कोई भी सभ्य समाज बेटियों और बहनों पर इस तरह के अत्याचार की अनुमति नहीं देता। देश के साथ-साथ उन्होंने भी आक्रोशित होते हुए कहा कि जिस समय छात्र, डॉक्टर और नागरिक कोलकाता में प्रदर्शन कर रहे थे, ऐसे समय में भी ऐसे अपराधी अन्यत्र शिकार की तलाश में घात लगाए हुए थे। उन्होंने दिसम्बर 2012 में दिल्ली में निर्भया के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या की चर्चा करते हुए कहा कि कुछ बच्चों ने मुझसे बड़ी मासूमियत से इस घटना के बारे में पूछा, मगर क्या उन्हें ऐसी घटना आगे घटित न होने का भरोसा दिया जा सकता है। निश्चित ही इस समय महिला उत्पीड़न के मुद्दे पर समाज को ईमानदार और निष्पक्ष रहकर आत्म मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रपति महोदया के बयान के आलोक में यदि महिला उत्पीड़न से जुड़ी घटनाओं का मूल्यांकन करें तो ज्ञात होता है कि अभी हाल ही में कोलकाता में डॉक्टर से किए गए यौन व्यभिचार से देशभर में फैले आक्रोश और प्रदर्शनों के बीच विधायिका की एक बदरंग तस्वीर भी सामने आई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म्स, एडीआर की ओर से जारी हालिया रिपोर्ट में 16 वर्तमान सांसदों और 135 विधायकों पर महिलाओं के विरुद्ध अपराध में मुकदमें दर्ज हैं। इतना ही नहीं, बल्कि दो सांसदों और 14 विधायकों पर दुष्कर्म के मामले चल रहे हैं। खास बात यह है कि बंगाल के सबसे अधिक जनप्रतिनिधि ऐसे मामलों का सामना कर रहे हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रपति महोदया की महिला उत्पीड़न को लेकर यह पीड़ा अनायास ही नहीं है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की हालिया रिपोर्ट भी बताती है कि यहां 16 मिनट में एक यौन दुष्कर्म घटना होती है। साथ ही प्रत्येक घण्टे महिलाओं के विरुद्ध 50 अपराध घटित होते हैं। इनमें 10 फीसदी से भी अधिक यौन दुष्कर्म की घटनाएं 18 साल से कम उम्र के नाबालिगों के साथ घटित होती हैं। कहना न होगा कि आज देश व प्रदेशों के मुख्तलिफ हिस्सों में मासूम लड़कियों व महिलाओं के साथ घटने वाली यौन उत्पीड़न की वारदातों ने देश व समाज को झकझोर कर रख दिया है। लगता है कि निर्भया यौन उत्पीड़न की घटना के बाद समाज की सोच में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। देश में ऐसी घटनाओं को रोकने के सभी उपाय भी निष्फल हो रहे हैं। यौन उत्पीड़न की अधिकांश घटनाएं आज कानूनविदों व समाजशास्त्रियों को नए सिरे से सोचने को मजबूर कर रही हैं। इस संदर्भ से जुड़े कुछ और आंकड़े खुलासा करते हैं कि भारत में यौन उत्पीड़न के मामले में लगभग 93 फीसदी दोषी पीड़िता के ही परिचित होते हैं। इन आंकड़ों की तकलीफदेय तस्वीर यह है कि 31 फीसदी यौन हिंसा व छेड़खानी में पीड़ित लड़कियों की उम्र 14 साल से भी कम रही।

दरअसल, मामला चाहे महिला छेड़छाड़ का हो

अथवा यौन हिंसा का, इन सभी घटनाओं को अब किसी एक सामाजिक पैमाने से नहीं मापा जा सकता। आज इसके गहन अध्ययन के लिए एक बहुआयामी वस्तुनिष्ठ उपागम की जरूरत महसूस की जा रही है। लेकिन फिर भी लगातार बढ़ती यौन हिंसाओं की इन घटनाओं पर कम से कम एक हालिया समाज-मनोवैज्ञानिक दृष्टिपात जरूरी हो जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि सूचना तकनीक ने आज की दुनिया में एक खलबली मचा दी है। गांवों से लेकर महानगरों तक मोबाइल व इंटरनेट ने बच्चों, युवाओं व महिलाओं के बीच अपना पूरा दखल बना लिया है। असल स्थिति यह है कि आप सड़क के किनारे तक से दस-बीस रुपयों का इंटरनेट सिम खरीदकर पूरी दुनिया की सैर कर सकते हैं। यहां तक कि पोर्न साहित्य तक भी इन्हीं सिम में कैद है।

संयुक्त परिवार के टूटने और छोटे परिवारों में मां-बाप और बच्चों के बीच बढ़ती दूरी व संवादहीनता ने टीनेजर्स के बीच सोशल मीडिया के रूप में संवाद का एक नया नेटीजन पीयर ग्रुप पैदा कर दिया है। ध्यान रहे कि यह नेटीजन समूह ही उनके हर तरीके के सुख-दुख में पूरी तरह हमसाज है। मां-बाप को इस सच्चाई को समझने की फुर्सत ही नहीं है कि पोर्न उनके बच्चों के बेडरूम तक पहुंच गया है। सच तो यह है कि पोर्न का प्रभाव ही यौन संबंधों के ढांचे को नई यौन प्रयोगशाला में रूपान्तरित कर रहा है। बढ़ते यौन आवेग के पीछे कहीं न कहीं इस मुद्दे को भी समाहित करना समीचीन होगा। दूसरी ओर, इस संदर्भ में यह भी देखने में आ रहा है कि आज सबसे अधिक हिंसा उन लड़के-लड़कियों पर हो रही है जो या तो वे घर से बाहर रह रहे हैं अथवा वे समाज के कमजोर सामाजिक-आर्थिक वर्ग से आते हैं।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि निर्भया कांण्ड के पश्चात बलात्कार के दोषियों के प्रति कानून की सख्ती हुई है। मगर इसके बाद भी बालिग के साथ कहीं-कहीं नाबालिग अपराधी तक अब बलात्कार के बाद पीड़िता की हत्या करके सबूत मिटाने पर आमादा हैं। सबसे दुखद तो यह है कि यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों में राजनीति और कानून से जुड़े पुरोधाओं के गैरजिम्मेदाराना बयानों ने भी इन व्यभिचारियों के हौसले बुलंद किए हुए हैं। कड़वा सच यह है कि यौन दुष्कर्मों से जुड़ी इन सभी घटनाओं के पीछे छिपा वह सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण भी है जिसे हमने अपनी खुली बाजारू अर्थव्यवस्था तथा जाति व धर्म पर आधारित सामाजिक वैमनस्य और दकियानूसी राजनीति से तैयार किया है। विचारहीन व्यवहार से जुड़ी इस संक्रमित संस्कृति में आज सामाजिक संवेदना, दूसरे के प्रति सम्मान, करुणा व सहानुभूति जैसे मूल्यों के साथ में बहन व बेटी जैसे रिश्तों के सम्मान की कोई जगह बची नहीं है। ऐसे में विषैली मानसिकता का प्रस्फुटित होना स्वाभाविक ही है। इसलिए हमें समय रहते उन सामाजिक व मनोवैज्ञानिक दशाओं का विश्लेषण भी करना चाहिए जो लोगों को बलात्कारी बनाती हैं। साथ ही कड़ा व पुरुष देह से जुड़ी उन सामाजिक मान्यताओं और पुलिस कानून की कमजोर व्यवस्थाओं का भी मूल्यांकन करना पड़ेगा, जो आज खुद बलात्कारी की रक्षक बनकर न्याय का गला घोंट रही हैं। साथ ही एक स्वस्थ व स्त्री सशक्तता से जुड़े समाज की पुनः स्थापना भी करनी होगी, तभी महिला की देह को सुरक्षा कवच मिल पाएगा।

कहना न होगा कि देश में प्रत्येक नारी के सम्मान के साथ-साथ करुणा व दया भाव से जुड़े मूल्यों को आत्मसात करके और व्यवहार में उनका प्रदर्शन करके ऐसी यौन दुष्कृतियों पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकती है। इसलिए समय रहते हमें राष्ट्रपति महोदया की सामयिक पीड़ा को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है।

(लेखक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रवीण वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं। व्यक्त विचार निजी हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

महिला अपराध
डा. ज्योत्सना शर्मा

कब तक होते रहेंगे जुल्म

समय-समय पर देशभर से महिलाओं के साथ होने वाले जघन्य अपराधों की खबरें आती रहती हैं। दिन प्रतिदिन स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम अपने संस्कार, संवेदनशीलता और मूल्यों की हत्या करके मानव विकास की अंधी दौड़ में बहुत आगे निकल गए हैं, तभी तो आज इंसान -इंसान में फर्क करना मुश्किल हो गया है। कोई किसी पर भरोसा करने से कतराता है। मदद के लिए अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाते। धैर्य के बांध टूट गए हैं। सारे संसार में अलग-अलग देशों में युद्ध की भयावह स्थितियों ने प्रकृति को नष्ट कर दिया है, जिसका खामियाजा आने वाली तमाम पुश्तें भुगतेंगी। यतीम बच्चे, बेवा, दिव्यांग और बुजुर्ग कहां अपनी जमीन तलाशें। क्या कोई ऐसी शिक्षा है जो इंसान को इंसान बनने की शिक्षा दे सके? ऐसी शिक्षा जो नैतिकता की बात करे?

ऐसी शिक्षा जो शांति, सौहार्द और भाईचारे की बात करे? हाल ही में देश के दो अहम राज्यों महाराष्ट्र और बंगाल से घिनौनी करतूत के परिणाम सारे देश के सामने आए। किस मजहब में स्त्री की अस्मत से खिलवाड़ करना सिखाया गया। किसने यह इजाजत दी कि किसी भी स्त्री की अस्मिता को तार-तार करने का हक पुरुषों को है। यहां तक कि मासूम बच्चियों तक को अपनी हवस का शिकार बनाने का दुस्साहस कर रहे हैं। क्या यही पौरुष शेष है। सदियों से महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया। उनके अधिकारों से वंचित रखा गया और तो उन्हें कम उम्र में विवाह के बाद जनसंख्या बढ़ाने की मशीन तक बना डाला। समाज में कैसी मानसिकता का विकास होता जा रहा है कि संभ्रांत परिवारों में भी महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे की रही। कभी घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं, कभी यौन उत्पीड़न, कभी दहेज के लिए हत्या, कभी डायन करार देना, कभी बांझ होने का दंश और कभी पुत्र चाह में लगातार गर्भपात। कितनी ही महिलाएं हर दिन अपनी जान गंवा देती हैं। आखिर किस प्रकार के समाज को सभ्य समाज कहते हैं जो आज तक इतनी भी समझ विकसित नहीं हुई कि एक महिला भी महिला होने से पहले इंसान है। हमारी शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से असफल है क्योंकि हम बच्चों में चारित्रिक गुणों का विकास करने में बुरी तरह से असफल रहे हैं। अफसोस की बात है कि इस प्रकार की घटनाओं की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। मात्र मोमबत्ती जलाकर अपना विरोध दर्ज करना क्या काफी है या जगह-जगह तोड़-फोड़ करना किसी नतीजे पर पहुंचने में मददगार है। यह अति गंभीर और संवेदनशील विषय है कि विकास और सभ्यता की सीढ़ी चढ़ता समाज हिंसा और घृणा में लिप्त होता जा रहा है।

नृशंस हत्याएं करने से बाज नहीं आ रहा। ऐसी सभी स्थितियों में महिलाओं के हिस्से सिर्फ शोषण आया है। क्या इसे कुंठित और मनोरोग से ग्रस्त मानसिकता का पर्याय कहना ज्यादा उचित प्रतीत नहीं होता। मनुष्य स्व केंद्रित होता जा रहा है। लोभ, ईर्ष्या, कुत्सित विचारों ने बुद्धि को ऐसा हर लिया है कि अब मनुष्य का पतन निश्चित है। मनुष्यत्व विलुप्त होता जा रहा है। क्या माता-पिता अपने बच्चों को ऊंची शिक्षा प्राप्त करने हेतु भविष्य में अकेले भेजने से कतराएंगे? लड़कियां अपने पहनावे में कुछ बदलाव करें। इतनी रात को ऑफिस से क्यों लौटी, यही होगा। इस प्रकार की अनाप-शनाप बयानबाजी बहुत हो चुकी। महिलाओं को अपने फैसले स्वयं लेने होंगे। किसी पर निर्भर रहने से अच्छा है कि आत्मनिर्भर बनें।

अपने हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हों। कम उम्र की बच्चियों को लगातार परामर्श दिए जाएं जिससे वह अपने आसपास के स्थान और वातावरण से परिचित हो सकें। दुर्गा वाहिनी जैसी कार्यशालाएं संचालित हों। दिल्ली पुलिस द्वारा समय-समय पर स्व रक्षा अभियान चलाया गया था जो काबिले तारीफ रहा। इस प्रकार के अभियान और कार्यशालाएं लगातार स्कूलों में संचालित की जानी चाहिए। जिस दिन कोई भी बच्ची अपनी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करके इस भरे-पूरे संसार में पैर रखे, उस दिन वह बिना किसी हथियार भी अपनी रक्षा करने में समर्थ हो। ऐसा लक्ष्य सभी माता-पिता निर्धारित करें। अध्यापक अपने छात्र-छात्राओं से खुलकर उनकी समस्याओं पर बात करें। माता-पिता अपने पुत्र और पुत्री को एक समान शिक्षा-दीक्षा दें और मित्रवत व्यवहार रखें। नागरिक अपना कर्तव्य समझते हुए स्थानीय पुलिस थानों में जाकर पुलिस को अवगत कार्यों की अमुक स्थान सुनसान है और कहां प्रकाश की व्यवस्था की जानी अपेक्षित है। अब समय आ चुका है जब सरकार को सख्त कानून बनाने होंगे और अदालतों को इस प्रकार के जघन्य अपराध करने वालों के खिलाफ बड़े फैसले लेने होंगे, तभी हम महिलाओं को सुरक्षित जीवन प्रदान कर पाएंगे जो उनका हक है।

(लेखिका स्वतंत्र स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

संकलित
दर्शन

चरित्र गठन की विशाल व्यायामशाला है संसार

संसार न तो अच्छा है, ना बुरा। प्रत्येक मनुष्य अपने लिए अपना-अपना संसार बना लेता है। हमारी मानसिक अवस्था के अनुसार ही हमें यह संसार भला या बुरा प्रतीत होता है। अग्नि स्वयं में अच्छी है न बुरी। जब यह हमें गर्म रखती है, तो हम कहते हैं यह कितनी अच्छी है, जब हमारी अंगुली जल जाती है, तो हम इसे दोष देते हैं। यही हाल संसार का है। संसार स्वयं पूर्ण है। पूर्ण का अर्थ यह है कि इसमें अपने सभी प्रयोजन पूर्ण करने की क्षमता है। हमें जान लेना चाहिए कि हमारे बिना भी यह संसार बड़े मजे से चलता जाएगा। हमें उसकी सहायता करने के लिए माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं। परंतु फिर भी हमें सदैव परोपकार करते ही रहना चाहिए। यदि हम सदैव यह ध्यान रखें कि दूसरों की सहायता करना एक सौभाग्य है, तो परोपकार करने की इच्छा एक सर्वोत्तम प्रेरणा शक्ति है। एक दाता के ऊंचे आसन पर खड़े होकर और अपने हाथ में दो पैसे लेकर यह मत कहो, 'ऐ भिखारी, ले, मैं तुझे यह देता हूं।' तुम स्वयं इस बात के लिए कृतज्ञ हो जाओ कि इस संसार में तुम्हें अपनी दयालुता का प्रयोग करने और इस प्रकार पूर्ण होने का अवसर प्राप्त हुआ। धन पाने वाला नहीं, देने वाला होता है। भलाई के सभी कार्य हमें शुद्ध और पूर्ण बनाने में सहायता करते हैं। यह संसार न तो तुम्हारी सहायता का भूखा है और ना मेरी। परंतु फिर भी हमें निरंतर कार्य करते रहना चाहिए, परोपकार करते रहना चाहिए। क्योंकि इससे हमारा ही भला है।

हृदय से जो जाओगे सबल समझूंगा तोहे

एक बार सूरदास जी चलते-चलते मार्ग में एक गहरे गड्ढे में गिर गए और निकलने के सारे प्रयास असफल हो गये। अपने कान्हा को ही पुकारने लगे, एक भक्त अपने जीवन में विपत्ति काल में प्रभु को ही तो पुकारता है। जैसे ही सूरदास जी ने कान्हा को याद किया, प्रभु भी उसकी पुकार सुने बिना नहीं रह पाए। सच है जब एक भक्त दिल से पुकारता है तो यह टीस प्रभु के दिल में भी उठा करती है। उसी समय एक बाल गोपाल के रूप में वहाँ प्रकट हो गए, और प्रभु के पांव की नन्ही-नन्ही सी पैजनिया की छन-छन की आवाज सुनते ही सूरदास जी को समझते देर न लगी। कान्हा उनके समीप आये और बोले अरे बाबा नीचे क्या कर रहे हो, लो मेरा हाथ पकड़ो और जल्दी से ऊपर चले आओ। जैसे ही सूरदास जी ने इतनी प्यारी सी मिश्री सी घुली हुई वाणी सुनी तो जान गए की मेरा कान्हा आ गया, और बहुत प्रसन्न हो गए, और कहने लगे की अच्छा कान्हा, बाल गोपाल के रूप में आ गए, कन्हाई तुम आ ही गए न? बाल गोपाल कहने लगे अरे कौन कान्हा ? किसका नाम लेते जा रहे हो,जल्दी से हाथ पकड़ो और ऊपर आ जाओ, ज्यादा बातें न बनाओ। सूरदास जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे: सच में कान्हा तेरी बांसुरी के भीतर भी वो मधुरता नहीं, माना कि तेरी बांसुरी सारे संसार को नचा दिया करती है लेकिन तेरे भक्तों का दुःख तुझे नचा देता है। क्यों कान्हा सच है न? तभी तो तू दौड़ा चला आया। जैसे ही उन्होंने इतना कहा सूरदास जी ने झट से कान्हा का हाथ पकड़ लिया और उस मंगलमय ब्रह्मसंस्पर्श से वे रोमांचित हो उठे।

संकलित
प्रेरणा

अंतर्मन

आज की पाती

उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए

देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश की आर्थिक व्यवस्था की मजबूती के लिए देश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना जरूरी माना था। देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए जब जवाहरलाल नेहरू के समक्ष तीन प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें मुख्यतः पहला गांधीवादी विचारधारा का, दूसरा एमएन राय का, और तीसरा देश के मुख्य पूंजीपतियों की विचारधारा का था, तो जवाहरलाल नेहरू ने देश के उस समय के सबसे बड़े उद्योगपतियों टाटा-बिड़ला के प्लान को ही स्वीकार किया था। देश के विकास में उद्योग जगत की भूमिका हमेशा रही है। नेहरू यह मानते थे कि उद्योगों को बढ़ावा देने से ही देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो सकती है। इसलिए आज भी जरूरत है कि उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। - निर्मल सोनी, बलौदा बाजार

ट्रेंड

हार्दिक शुभकामनाएं

भारतीय टीम को पेरिस पैरालंपिक के लिए हार्दिक शुभकामनाएं! लोग दृढ़ विश्वास है कि वे रास्ते में आने वाली हर चुनौती को पार करते हुए, भारत की अटूली छवाना साबित करेंगे। साथ उनके लिए जबरदस्त करता है! -अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री

बधाई हो

बधाई हो, चैंपीय गृह मंत्री! आपका बेटा हताशेत नहीं बना है, लेकिन आईसीसी चैंपरशिप बन गया है - यह एक अविश्वसनीय हताशेओं से उबरी अविश्व महत्वपूर्ण है!! आपका बेटा ताकत से बहुत शक्तिशाली हो गया है और मैं आपसे उत्कर्ष इस सर्वोच्च उपलब्धि पर बधाई देती हूं! -ममता बनर्जी, सीएम, प. बंगाल

खेल की शक्ति

खेल हमें टीम वर्क, लचीलापन और सौहार्द के मूल्य सिखाते हैं। जीवन को बदलने और उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने की खेल की शक्ति का गहन जनमने में हमारे साथ शामिल हो। -सचिन तेंदुलकर, पूर्व क्रिकेटर

महिलाओं के खिलाफ हिंसा

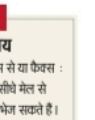

इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बलात्कार और मनोरंजन के लिए महिलाओं के खिलाफ हिंसा, इस शिशुतालाय राष्ट्र के लाखों से इतनी नहीं जड़े जाना चूर्ण है कि इसका इस्तेमाल लाचारों से छिड़ने के लिए किया जाता है। - कंगना रनौत, अभिनेत्री व सांसद

करंट अफेयर

भारत का रुख अमेरिका के साथ सहयोग वाला

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एच आर मैकमास्टर ने अपनी नई पुस्तक में दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार मुख्य रूप से चीनी आक्रामकता के कारण अमेरिका के साथ 'अभूतपूर्व' सहयोग करने की इच्छुक है, लेकिन साथ ही वह 'फंसने और त्यागे जाने' को लेकर भी 'भयभीत' है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) के रूप में अपने कार्यकाल का विवरण देते हुए मैकमास्टर ने अपनी पुस्तक 'ऐट वॉर विद अवरसेल्वस' में लिखा है कि ट्रंप द्वारा बर्खास्त किए जाने से एक दिन पहले उन्होंने अपने भारतीय समकक्ष अजीत के. डोभाल से मुलाकात की थी। यह पुस्तक मंगलवार से दुकानों पर उपलब्ध हो गई है। मैकमास्टर ने कहा, 'बर्खास्त किए जाने से एक दिन पहले मैं अपने भारतीय समकक्ष अजीत डोभाल से वाशंटन 13, फोर्ट मैकेनेयर में रात्रि भोज के लिए मिला था। यह यूएस वैशिटन के दक्षिण में एनाकोस्टिया और पोटोमैक नदियों के संगम पर स्थित एक शांत जगह है। डोभाल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने पद के अनुरूप व्यवहार करते हैं।'

ऑफ बीट

माइक्रोप्लास्टिक हमारे दिमाग में हैं, बढ़ी चिंता

प्लास्टिक हमारे कपड़ों, कारों, मोबाइल फोन, पानी की बोतलों और खाद्य कंटेनरों में है। लेकिन हाल के शोध से हमारे स्वास्थ्य पर प्लास्टिक के छोटे टुकड़ों के प्रभाव के बारे में पहले से मौजूद चिंताएँ और बढ़ गई हैं। अमेरिका के एक अध्ययन में पहली बार मानव मस्तिष्क में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। अध्ययन, जिसे अभी तक अन्य वैज्ञानिकों द्वारा स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया गया है, को मीडिया में डरावना, चौंकाने वाला और चेतावनक बताया गया है। हम अक्सर प्लास्टिक की वस्तुओं को अविनाशी मानते हैं। लेकिन प्लास्टिक छोटे-छोटे कणों में टूट जाता है। परिभाषाएँ अलग-अलग होती हैं लेकिन आम तौर पर माइक्रोप्लास्टिक पाँच मिलीमीटर से छोटे होते हैं। इससे कुछ चीजें इतनी छोटी हो जाती हैं कि उन्हें नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता। इसलिए, माइक्रोप्लास्टिक्स के बारे में लेखों को चित्रित करने के लिए मीडिया द्वारा उपयोग की जाने वाली कई छवियां भ्रामक हैं, क्योंकि कुछ बहुत बड़े, स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले टुकड़े दिखाती हैं। पीने के पानी और रोजमर्रा के खाद्य पदार्थों के कई स्रोतों में माइक्रोप्लास्टिक होने की सूचना मिली है। इसका मतलब है कि हम अपने आहार के जरिए लगातार उनके संपर्क में रहते हैं।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

20 से अधिक राज्यों और 120 से अधिक शहरों तक अलकायदा और आइएसआइएस जैसे आतंकी संगठनों की पहुंच बढ़ चुकी है, जो भारत में अपना नेटवर्क विस्तार करने की साजिश में जुटे हुए हैं।

आजकल

भारत में सिर उठाता जिहादी आतंकवाद

संजय श्रीवास्तव
वरिष्ठ पत्रकार

देश में जिहादी आतंक धीरे-धीरे पैठ बनाता जा रहा है। महज एक पखवाड़े के भीतर ही दो सुबूत मिले हैं। पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आइएसआइएस से जुड़े एक आरोपी को गिरफ्तार किया और फिर उसने झारखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सक्रिय रहे अलकायदा के आतंकवादी माड्यूल पर शिकंजा कसा। इस नेटवर्क के मुख्य सूत्रधार समेत 14 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने से पता चला कि कई राज्यों में भिन्न-भिन्न आतंकी संगठन सक्रिय हैं। ऐसे में इस ओर केंद्र सरकार समेत सभी राज्यों को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है

देश में आतंक का नेटवर्क फैलाने वाले अनेक संदिग्धों को बीते दिनों सुरक्षा एजेंसी ने किया गिरफ्तार। फाइल

पापुलर फ्रंट आफ इंडिया यानी पीएफआइ और सिमी पर बीते वर्षों में आतंक की कई घटनाओं में शामिल होने के आरोप लगे, साक्ष्यों के बाद अब पाबंदी है। लेकिन दूसरे नामों से ये अब भी सक्रिय हैं, खासतौर पर मध्य प्रदेश में यह निर्मूल नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, केरल और महाराष्ट्र समेत अनेक राज्यों की अदालतें इस्लामिक स्टेट से संबद्ध कई आतंकियों को पिछले कुछ वर्षों में सजा सुना चुकी हैं और अलकायदा यहां जड़ जमाने की कोशिश में है।

सूत्र बताते हैं कि भारत में बड़े पैमाने पर हमले करने में अक्षम आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट इन ईराक एंड द लेवेंट खुरासान यानी आइएसआइएलके यहां के ऐसे नौजवानों को भर्ती करना चाहता है जो अकेले बड़ी घटना को अंजाम देने की हैसियत रखते हों। इसके लिए वह भटके नौजवानों को लुभाने में लगा है। उधर तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल के लिए पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी संगठन आइएसपीके यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान ने धमकी दी है कि जल्द ही दुनिया के हर कोने में मुसलमानों पर किए गए अत्याचारों की कीमत चुकानी पड़ेगी।

देश में गहराती जड़ें : इधर पाकिस्तानी सेना आइएसआइएस के कई ट्रेनिंग कैंप संचालित करती है। वह अपने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों को आइएसआइएस में भर्ती करवा कर भारत विरोधी बातों को और हवा देना व इस्लामिक स्टेट का रुख इधर मोड़ना चाहती है। कुछ बरस पहले तक यह माना जाता था कि देश में आतंकवाद सीमा पार से पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित और उसके संगठनों द्वारा अंजाम दिया गया कृत्य है, पर अब यह अंतरराष्ट्रीय हो चुका है। अब इसमें कई देशों के आतंकी संगठन शामिल हैं। दुनिया के जो देश इन्हें खाद पानी दे रहे हैं, उनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्किए, सीरिया वगैरह शामिल हैं, लेकिन अब इसकी जड़ें देश में ही हैं।

अमूमन इस तरह के समाचारों को हम भिन्न स्रोतों से और एकसाथ नहीं देख पाते हैं, अन्यथा यह पता चलता कि देश में इस्लामी आतंकी संगठन हर ओर पांव पसारता जा रहा है। 20 से ज्यादा राज्यों और 120 से ज्यादा शहरों में इनकी पहुंच बन चुकी है। न केवल अलकायदा और आइएसआइएस जैसे आतंकी संगठन देश के तमाम राज्यों में अपना नेटवर्क फैला रहे हैं, बल्कि कई दूसरे अनुषंगिक आतंकी संगठन के अलावा भी छिपे तौरपर काम करने वाले इस्लामी आतंकी अथवा चरमपंथी संगठन देश के तमाम क्षेत्रों में सक्रिय हैं जो सघन पुलिसिया अभियानों और खुफिया निगरानी के बाद सामने आ सकते हैं। विशालकाय देश, सघन आबादी और सतर्क गृह मंत्रालय के चलते अभी ये स्पष्ट रूप से नहीं दिखते, लेकिन आतंक के बीज अंकुरित हो चुके हैं, ये विषवृक्ष अनुकूल वातावरण मिलने पर तेजी से फले-फूलेंगे। यह चिंतनीय है।

वैश्विक जिहाद : इस्लामिक स्टेट के उभार के बाद लगता था कि अलकायदा डूब गया और आइएस के प्रति भारतीय मुसलमान उदासीन हैं, पर पुलिस के लगातार छापे और राज्यवार इकाइयों का खुफिया तंत्र बताते हैं कि परिस्थितियां बदल गई हैं। अलकायदा यहां अपने को मजबूत बनाने में लगा है और देश के कुछ मुसलमान आज इस्लामिक स्टेट की ओर आकर्षित दिखते हैं। इंडियन मुजाहिदीन, सिमी और पीएफआइ भारत केंद्रित थे, लेकिन आइएस और अलकायदा मौजूदा मुस्लिम कट्टरता को वैश्विक जिहाद का हिस्सा बना देगा। यह बहुत चिंताजनक है। खास तौरपर तब जब आइएस देश में जिहाद छेड़ने के अलावा भारतीय मुसलमानों को ईराक और सीरिया में लड़ने को मजबूर करेगा जिससे उनका कोई वास्ता नहीं। इनमें से कुछ गजवा-ए-हिंद की बात करते हैं यानी अधिक से अधिक काफिरों को मारना, तो कुछ लोकतांत्रिक तरीके से भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने की। ये चाहते हैं कि वर्ष 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मना रहा हो, तब तक भारत को इस्लामिक देश घोषित करवा लें।

आतंक पर प्रहार : बीमारी के बिगड़ने से पहले इसका तत्काल ईलाज जरूरी है। यह समझना होगा कि आतंकी संगठनों का समर्थक मुस्लिम युवा मदरसों से दीनी तालीम लेकर नहीं, देश के सामान्य स्कूल-कालेजों से पढ़कर निकला है। तथ्य और आंकड़े उस स्थापित मिथक को नकारते हैं कि इस्लामी कट्टरवाद अशिक्षा और दीनी पढ़ाई से फैला है। पकड़े गए आरोपियों में से कई ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियर, गोल्ड मेडलिस्ट, डाक्टर आदि हैं, 70 प्रतिशत मध्यम या उच्च आय वर्ग से संबंध रखते हैं। हमें आने वाले समय में आतंकवाद की पारंपरिक चुनौतियों से परे जाना होगा, फिलहाल देश की मौजूदा सुरक्षा ढांचे में आतंक की नई चुनौती से निपटने की क्षमता और कार्यकुशलता कम लगती है। आतंकवाद की आगामी चुनौतियों के प्रति हमें जानकारी और सुरक्षा उन्नत करनी होगी। हमें स्थानीय आतंकवाद और सीमा पार से प्रायोजित आतंक से समान रूप से निपटने का तंत्र विकसित करना होगा। आनलाइन आतंकवाद से निपटने के लिए सक्षम लोगों को साथ लेकर सुरक्षा का पुख्ता इकोसिस्टम तैयार करना होगा। यह ऐसी क्षमता विकसित करने का रास्ता बनाएगा जिसके तहत हम आतंकवादी हमलों के खतरों को पहले से पहचान कर उन्हें नाकाम कर सकेंगे।

बहुसंख्यकवाद की राजनीति सत्ता तो दिला सकती है, लेकिन इस सांसत में भी फंसा सकती है। अल्पसंख्यकों में सुरक्षा भाव नहीं बढ़ाया गया तो इस्लामिक आतंकवादी संगठनों को मुस्लिम नौजवानों को रिझाने का मौका मिल जाएगा। भारतीय मुसलमानों ने इस्लामिक आतंकवादी संगठनों को हमेशा खारिज किया है। इस्लामिक स्टेट का समर्थन अब तक तकरीबन दो सौ भारतीयों ने किया है, जबकि फ्रांस, बेल्जियम जैसे कुछ देशों में इनकी संख्या इससे कई गुनी है, जबकि उनकी मुस्लिम आबादी हम से बहुत कम। सरकार भेदभाव न बरते साथ ही इंटरनेट मीडिया पर अल्पसंख्यकों को हाशिये पर धकेलने, उन्हें दोयम दर्जे के नागरिक बताए जाने की कवायद, हेटस्पीच आदि का सिलसिला सरकार ने सख्ती से नहीं रोका तो निस्संदेह स्थितियां भविष्य में विद्रूप हो सकती हैं। हमें हजारों बेगुनाहों की मौत की वजह बनने वाली आतंकी घटनाओं के प्रति अभी से सचेत हो जाना चाहिए। (ईआरसी)

समान नागरिक संहिता पर आगे बढ़े देश

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से प्रधानमंत्री ने सेक्युलर सिविल कोड की आवश्यकता पर बल दिया। इसके पहले देश में आम सहमति बनाने के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन कर दिया गया। यह समिति इस दिशा में आम सहमति के लिए शीघ्र रास्ता तलाशेगी। विश्व के कई ऐसे देश हैं, जहां समान नागरिक संहिता जैसी संहिता बहुत पहले से लागू की गई है। समान नागरिक संहिता लागू होने पर शादी, तलाक तथा जमीन-जायदाद के बंटवारे आदि में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होता है। अभी देश में जो स्थिति है, उसमें धर्मों-मतों के लिए अलग-अलग नियम हैं। इसका समाधान नागरिक संहिता के लागू होने से ही होगा।

इस समय देश में ईसाई, मुस्लिम और पारसी मत के लोग विवाह, संपत्ति और गोद लेने आदि में अपने पर्सनल ला का पालन करते हैं। मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय का अपना-अपना पर्सनल ला है, जबकि हिंदू सिविल ला के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने के विरोध में यह तर्क लागू किया जाता है कि सैकड़ों पुराने जैसे इस्लाम के 1400 और ईसाइयों के दो हजार पुराने कानूनों का हवाला दिया जाता है कि इतने पुराने निजी आस्था वाले कानूनों को कैसे बदला जा सकता है? कई हजार साल पुराने हिंदू धर्म में हजारों साल पुरानी प्रचलित बहुविवाह की कुप्रथा को 1955-56 में हिंदू बिल कोड के द्वारा परिवर्तन कर दिया गया था। एक ही झटके में सदियों पुरानी प्रचलित बहुविवाह को समाप्त कर एक विवाह अथवा एक पत्नी, उत्तराधिकार कानून को कानूनी मान्यता प्रदान की गई। ऐसा नहीं था कि इसका विरोध नहीं हुआ हो, नेहरू और आंबेडकर को इसके लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा था। इस अधिनियम का तीखा विरोध रामराज्य परिषद जैसी कट्टरपंथी संस्थाओं के अलावा तत्कालीन संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद समेत कई अन्य दिग्गज नेताओं ने किया था। वस्तुतः आंबेडकर और नेहरू दोनों ही भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने के पक्षधर थे। परंतु इनका मानना था कि हिंदू धर्म में सुधारवादी तत्व मौजूद हैं, परंतु इस्लाम में नहीं। यह सच भी था, उस दौरान और कुछ पहले हिंदू धर्म के अंदर से आर्यसमाज, ब्रह्म समाज सहित कई सुधारवादी संगठनों, लोगों ने हिंदू धर्म में पुरानी कुप्रथाओं के खिलाफ सफलतापूर्वक आंदोलन चलाए थे, परंतु इस्लाम में कमोबेश अपवाद के अलावा इस प्रकार के सुधारवादी कृत्य देखने को नहीं मिले थे।

अब जब वर्तमान सरकार इसे लागू करने के लिए संसद के द्वारा कानून बनाना चाहती है तो इसका विरोध वोटबैंक के लिए उचित नहीं है। भारत के गोआ जैसे ईसाई बाहुल्य राज्य में लंबे अरसे से समान नागरिक संहिता बिना विवाद के लागू है तो फिर संपूर्ण भारत में भी इसे लागू क्यों नहीं किया जा सकता है? उत्तराखंड यूसीसी को लागू करने की दिशा में बहुत आगे बढ़ चुका है। संविधान के अनुच्छेद 44 में लिखा गया है कि समान नागरिक संहिता बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए। एक ही मसले पर बार बार सुप्रीम कोर्ट की अनदेखी भी ठीक नहीं है। समान नागरिक संहिता के निर्माण का कार्य संविधान की भावना के अनुरूप विधिसम्मत तो है ही, साथ ही एक बड़े समुदाय के भीतर की कुरीतियां मिटाने वाला हो और जब यह समाज, राष्ट्र के हित में हो तो फिर इस कार्य में देरी नहीं की जानी चाहिए।

(लेखक इतिहास के जानकार हैं)

खरी-खरी

हार्न और उसका सौंदर्य बोध

अलंकार रस्तोगी

उनको दो लाख रुपये की बाइक हाल ही में दिलवाई गई है। बाइक पर बैठने से भी ज्यादा उन्हें प्रेशर वाला हार्न बजाने में परम आनंद की अनुभूति होती है। हार्न बजाते ही उनके अंदर किसी दिव्य पुरुष की आत्मा के वास का आभास सा प्रतीत होता है। हार्न बजाते ही वह किसी स्वयंभू सम्राट की तरह बर्ताव करने लग जाते हैं। वह अपने खतरनाक हार्न की खूंखार आवाज से अपनी उस दमित इच्छा की पूर्ति करते हैं, जो वह चक्रवर्ती सम्राट न बन पाने के कारण नहीं कर पाए थे। वह हार्न से ही लोगों को पटखनी देने का दंभ भरने लगे हैं।

हार्न बजाना अब उनका मौलिक अधिकार बन चुका है। उनकी सुबह हार्न के वंदन से, सांझ हार्न के कीर्तन से और रात हार्न के क्रंदन से गुंजायमान रहती है। हार्न उनके जीवन का अभिन्न अंग सा बन गया है। कहा जा सकता है कि उनका व्यक्तित्व अब हार्न ही है। उनका स्वयं का कुछ भी नहीं है। उनका हर अर्जित और परमार्जित बस हार्न से ही। लड़कियों के कालेज जैसे स्थान विशेष पर हार्न को बजाने जैसे कार्य को वह किसी क्रांतिकारी आंदोलन से कम नहीं मानते हैं। उनके इस साहसिक कार्य के लिए वह अपने मित्र मंडली द्वारा 'मजनू श्री' की उपाधि से भी अलंकृत किए जा चुके हैं।

ट्रैफिक जाम और जन्नत उनके लिए एक समान ही है। जहां गाड़ियों के लिए हिलने की भी जगह संभव नहीं हो, वहां भी जनाब के हार्न का 'नान स्टाप' संगीत जारी रहता है। यह संगीत का 'कंसर्ट' तब तक जारी रहता है, जब तक अगल-बगल के लोग बहरे होने की कगार पर आकर रहम की भीख नहीं मांगने लग जाएं या फिर कोई उनके पास आकर उनके इस पुनीत कार्य के लिए उनकी माता और बहन का स्तुति वंदन न करने लग जाएं।

दरअसल हार्न में ही उनका आत्मा है। हार्न ही उनका परमात्मा है। हार्न ही उनकी कुंठा निकालने का तरीका है। हार्न ही उनकी ईर्ष्या प्रदर्शन का मंच है। अब हार्न ही है उनके लिए, सब कुछ है उनके लिए, बस हार्न मोह के कारण वही नहीं बचे हैं एक सभ्य समाज के लिए।

पोस्ट

चुप रह जाती तो दोस्तों के दोहरे रूप नहीं समझ पाती। अपनों ने मारा तब जाना कि अच्छाई का ढोंग करने वाले तो बुरे लोगों से कई लाख गुना बुरे होते हैं।
स्वाति मालीवाल@SwatiJaiHind

पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस के चक्कर में उलझी हिमाचल की कांग्रेस सरकार अब गहरे आर्थिक संकट में फंस गई है। मुख्यमंत्री, सभी मंत्री और मुख्य संसदीय सचिव दो महीने तक वेतन और भत्ते नहीं लेंगे। सभी विधायकों से भी दो महीने तक वेतन-भत्ते न लेने की अपील की गई है।
अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

राहुल गांधी के 'खटाखट माडल' से हिमाचल प्रदेश के सरकारी खजाने की हालत इतनी पतली हो गई है कि वहां तरह-तरह की अपील करनी पड़ रही है।
अजी हां@AjiHaaan

केंद्र की कांग्रेस सरकार ने 1992 में जब बिना कारण मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकारों को बर्खास्त किया, तब ममता बनर्जी केंद्र सरकार में मानव संसाधन विकास, युवा मामले और खेल और महिला एवं बाल विकास से जुड़े मंत्रालय देखती थीं। बस यूं ही, बता रहा हूं।
दिलीप मंडल@Profdilipmandal

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या जनधन योजना वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पाने में सफल रही?

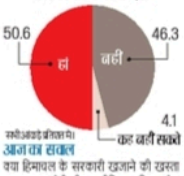

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या हिमाचल के सरकारी खजाने की खस्ता हालत मुफ्तखोरी की राजनीति का परिणाम है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

ममता जी है चाहती भारत में गृहयुद्ध,
चिल्लाकर वे धमकियां देती दिखे विशुद्ध।
देती दिखे विशुद्ध अराजकता फैलाए,
फिर पीएम को आपची ख करके धमकाए।
जब हाथों से आज निकलती दिखती बाजी,
तो खंभे को नोच रही दिखती ममता जी!
- ओमप्रकाश तिवारी

झारखंड डायरी

मुखर और आक्रामक होती भाजपा

शशि शेखर
संपादकीय प्रभारी, रांची

लंबे समय बाद झारखंड में भारतीय जनता पार्टी मुखर और आक्रामक दिखने लगी है। इससे पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का उत्साह बढ़ा है। भाजपा का शीर्ष केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य जून में शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को झारखंड का प्रभारी बनाया। तब तक लोकसभा चुनाव का परिणाम आ चुका था और झारखंड की सभी पांचों अनुसूचित जनजातीय सीट पर भाजपा को मुंह की खानी पड़ी थी। पंजा छोड़ कमल पर चुनाव लड़ीं गीता कोड़ा भी अपनी सीट नहीं बचा सकीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) से भाजपा में आई सीता सोरेन का भी यही हाल रहा। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। जून से अब तक इन दोनों प्रभारी नेताओं ने झारखंड के भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार कर दिया है। उनसे मिलना, उनकी बातों को सुनना, उनके घर जाकर उनके साथ भोजन करना, इन सब छोटी-छोटी बातों का असर अभी से ही दिख रहा है। कार्यकर्ता ही नहीं, विधायकों में भी एक नई ऊर्जा आ गई है। इसी का परिणाम था कि कई मुद्दों को लेकर विधानसभा में रातभर भाजपा विधायकों ने धरना प्रदर्शन किया।

झारखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष देर रात तक सदन में धरने पर बैठा। रात में मार्शल आउट किया गया, इसके बाद भी वे विधानसभा परिसर में डटे रहे। युवाओं के रोजगार, अनुबंध और संविदाकर्मियों के नियमितीकरण के मुद्दे ने हवा दी। अभी कुछ दिनों पहले भाजपा युवा मोर्चा के आक्रोश मार्च में भी युवाओं का जबरदस्त उत्साह दिखा। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अश्रु गैस के गोले दागे गए। इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन दोनों नेताओं ने यहां अपने स्तर से अभी से ही चुनावी जमीन तैयार कर दी है।

कार्यकर्ताओं में नया उत्साह पैदा कर रहे शिवराज सिंह चौहान (बाएं) और हिमंत बिस्वा सरमा। फाइल

ताजा घटनाक्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने भी भाजपा का दामन थाम लिया और अंततः झामुमो और मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। भाजपा को उम्मीद है कि उनके आने से कोल्हान प्रमंडल मजबूत होगा और आगामी विधानसभा चुनाव में अधिक सीटें जीतने का अवसर मिलेगा। चम्पाई के भाजपा में आने का हिमंत बिस्वा सरमा ने स्वागत करते हुए कहा कि इससे भाजपा को मजबूती मिलेगी, तो साथ ही यह भी कह दिया कि 'हम तो चाहते हैं कि हेमंत सोरेन भी भाजपा में शामिल हो जाएं।' झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम तो पहले से ही पार्टी के खिलाफ झंडा बुलंद किए हुए हैं, अब स्टीफन मरांडी भी उन्हीं की राह चल पड़े हैं। झामुमो से नेताओं का टूटना और इनका भाजपा से जुड़ना भी एक अलग संकेत दे रहा है।

भाजपा की इस सधी चाल का निहितार्थ झामुमो को भी समझ में आ रहा है, यही कारण है कि झामुमो भी तीव्र गति से विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गया है। अभी झारखंड में भाजपा ने 'मिला क्या' अभियान की शुरुआत की है। सवाल जनता से है, पिछले साढ़े चार साल में आपको मिला क्या? पांच लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, महिलाओं को आधार कार्ड पर 50 हजार रुपये का लोन, विधवा माताओं-बहनों को वित्तीय सहायता, नवविवाहित महिलाओं को सोने का सिक्का आदि-आदि। यह सीधे-सीधे हेमंत सोरेन सरकार पर हमला है। इतनी आक्रामकता विपक्ष में रहते भाजपा ने नहीं दिखाई थी। हालांकि झामुमो भी पीछे नहीं है। राज्यभर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का तूफानी दौरा, झामुमो की मंइयां योजना हो या फिर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह, यह सब पार्टी अपने को मजबूत करने को कर रही है।

भाजपा के लिए बेहतर यह भी है कि चम्पाई सोरेन मुख्यमंत्री रहते जिस बड़े मुद्दे बांग्लादेशियों के घुसपैठ को नकारते रहे, इस्तीफा देने के बाद सबसे पहले उन्होंने इसी मुद्दे को उठाया। उन्होंने साफ-साफ कहा, 'घुसपैठ के मुद्दे पर भाजपा ही गंभीर दिखती है और बाकी राजनीतिक दल वोटों की खातिर इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। इसलिए, आदिवासी अस्मिता एवं अस्तित्व बचाने के इस संघर्ष में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में आस्था जताते हुए भाजपा से जुड़ने का फैसला लिया है।' यह अलग बात है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चम्पाई सोरेन पर तंज कसते हुए कहा कि झामुमो में किसी के रहने या नहीं रहने से फर्क नहीं पड़ता है। वैसे, फर्क कितना पड़ेगा, यह अब चुनाव में ही पता चलेगा। बहरहाल, झारखंड की राजनीतिक चाय के प्याले में तूफान तो उठ ही गया है।

मंथन

महिला अपराध और इंटरनेट

ब्र. सौरभ जैन
अध्येता, सामाजिक व्यवहार

इंटरनेट मीडिया पर घटित होने वाली घटनाओं को देखकर ऐसा लग रहा है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने वालों में साइबर क्राइम का या तो डर नहीं है या फिर वे इससे अनभिज्ञ हैं

हाल ही में बाम्बे उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए कहा कि किसी महिला के खिलाफ ई-मेल या इंटरनेट मीडिया पर लिखित शब्द, जो किसी महिला की गरिमा को कम कर सकते हैं, वह एक अपराध है। जिसके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 509 (महिला का अपमान) के तहत किसी के खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने एक पुरुष के खिलाफ मामला रद करने से इन्कार कर दिया है। इंटरनेट मीडिया पर महिला अपराध की घटनाओं को लेकर मुखर अभिव्यक्ति होती है, तो वहीं दूसरी ओर वही इंटरनेट मीडिया महिला अपराध का एक प्रमुख कारण भी बन रहा है।

महिलाओं के साथ घटित घटनाओं का स्पष्ट दुष्प्रभाव इंटरनेट मीडिया पर देखने को मिलता है। देश के किसी भी हिस्से में जब कभी कोई घटना होती है तो परिणामस्वरूप घटना के प्रति आक्रोश व्यक्त करने के क्रम में कविताओं को पोस्ट करने से लेकर डीपी के रंग को काला कर लेने तक का कार्य किया जाता है, किंतु इसी का एक दूसरा पक्ष यह भी है कि इंटरनेट मीडिया पर ही एक अन्य वर्ग ऐसी घटनाओं के प्रति असंवेदनशीलता का प्रदर्शन करने पर आतुर हो रहा होता है। जिन प्लेटफार्म्स पर हम न्याय की मांग के लिए आवाज मुखर कर रहे होते हैं, वे ही मंच अपराध का माध्यम भी बन रहे हैं।

वास्तविक चिंता इसी बात को लेकर है कि जिस पीड़िता के साथ घिनौना अपराध हुआ हो, इंटरनेट मीडिया पर उसकी निजता को सार्वजनिक कर देना, उसकी तस्वीर को अग्रेषित करना, यह कहां की समझदारी है? कोलकाता में घटित घटना के संदर्भ में न्यायालय को तस्वीरों को हटाने के निर्देश देने पड़े, परंतु तब तक पहचान उजागर हो चुकी थी। यह बात यह बताती है कि साक्षर होना और डिजिटल साक्षर होना, दो पृथक बातें हैं। अब आवश्यकता दूसरी बात पर अधिक ध्यान देने की है।

तस्वीर के सामने आने पर समाज का एक ऐसा रूप भी सामने आता है जो बहुत ही डरावना होता है। इंटरनेट मीडिया पर पीड़िता की तस्वीर पर दुख और शोक के स्थान पर हंसने वाली इमोजी का होना समाज को किस दिशा में लेकर जाने के संकेत है? तस्वीर पर आई टिप्पणी के बारे में चर्चा की जाए तो यह तो और भी शर्मसार कर देने वाली होती है, समाज उसके रंग रूप के बारे में चर्चा कर रहा होता है, बजाय न्याय और व्यवस्था के प्रति आक्रोशित होने के। सभ्य समाज में सभ्य होने की परिभाषा साफ तौर पर परिवर्तित हो चुकी है जिसका परिणाम ही इस रूप में देखने को मिलता है।

संविधान के अनुच्छेद-15 में समानता का अधिकार दिया गया है। इस अधिकार के सैद्धांतिक पक्ष से तो हम परिचित हैं, किंतु व्यवहार में इसका उपयोग हम कितना कर पाए हैं, यह सोचने वाली बात है। 'वायलेंस आनलाइन इन इंडिया' रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हर सेकेंड एक महिला साइबर क्राइम की शिकार होती है। इस रिपोर्ट के अनुसार, शहरी क्षेत्र की लगभग 50 प्रतिशत महिलाएं आनलाइन एब्यूज झेलने को मजबूर होती हैं। ये आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। पहले जो काम राह चलते सड़कों पर होता था, अब वह इंटरनेट मीडिया पर धड़ल्ले से होने लगा है।

मानसिक उत्पीड़न : महिलाओं और पुरुषों की संख्या के आंकड़ों के आधार पर यदि हम तुलनात्मक रूप से आकलन करें तो पाएंगे कि माइक्रो ब्लागिंग साइट एक्स (पहले ट्विटर) पर 63 प्रतिशत से अधिक पुरुष हैं, जबकि इंस्टाग्राम पर 53 प्रतिशत पुरुष हैं। फेसबुक पर भी 40 प्रतिशत ही महिलाएं हैं। कोविड से पहले तक तो इंटरनेट मीडिया साइट पर महिलाओं की भागीदारी काफी कम थी। साइबर क्राइम से जुड़े एक सर्वेक्षण के अनुसार 15 प्रतिशत महिलाओं ने इंटरनेट पर लोगों द्वारा सेक्सुअल फेवर की मांग करने की बात स्वीकार की है। लगभग 8.5 प्रतिशत महिलाओं को बिना उनकी सहमति के अश्लील कंटेंट दिखाया गया है। इतना ही नहीं, 13 प्रतिशत महिलाओं को तो इंटरनेट मीडिया पर यौन शोषण की बातें भी कही गई हैं। वहीं आठ प्रतिशत महिलाओं को आनलाइन पोस्ट करने पर मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है।

कई महिलाओं को आनलाइन पोस्ट करने पर मानसिक उत्पीड़न तक झेलना पड़ता है। फाइल

ये आंकड़े यहीं खत्म नहीं होने वाले, बदला लेने के क्रम में महिलाओं की तस्वीरों से छेड़छाड़ कर उन्हें अश्लील साइट्स पर अपलोड करने तक का कार्य किया गया है। छह प्रतिशत महिलाओं ने अपनी तस्वीरें और वीडियो ऐसे साइट पर पाए हैं तो वहीं आठ प्रतिशत महिलाओं ने इंटरनेट मीडिया पर अपलोड की गई अपनी तस्वीरों में एडिटिंग करके दूसरी जगह उपयोग करने की बात कही है। सर्वेक्षण के ये आंकड़े आंख खोलने वाले हैं। जब कभी महिला अपराध की कोई घटना सामने आती है तो हम इंटरनेट मीडिया पर विरोध दर्ज करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन जब यही मंच महिला अपराध का कारण बन जाएं, तब सोचने वाली बात हो जाती है। इस विषय में समाज को समझने और इंटरनेट मीडिया व्यवहार सीखने की जरूरत है।

****

दैनिक जागरण

परिणाम सदैव प्रयास के अनुपात में ही प्राप्त होता है

रेवड़ी संस्कृति का नतीजा

लोकलुभावन वादों के साथ हिमाचल प्रदेश की सत्ता में आई कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दो माह तक वेतन न लेने की जो घोषणा की, उससे यह तो पता चल रहा है कि राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, लेकिन यह समझना कठिन है कि आखिर उनके और साथ ही मंत्रियों के दो महीने तक वेतन न लेने से आर्थिक हालात कैसे सुधर जाएंगे? यह प्रश्न इसलिए, क्योंकि उन्होंने यह नहीं कहा कि वह और उनके सहयोगी दो माह का अपना वेतन सदैव के लिए छोड़ रहे हैं। वैसे यदि वह ऐसा करते भी तो यह ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं होता। मुख्यमंत्री ने विधायकों से भी आग्रह किया है कि वे भी उनका अनुसरण करें। क्या इसके बाद वह सरकारी कर्मचारियों से भी ऐसी कोई अपील करने वाले हैं? जो भी हो, अच्छा यह होगा कि वह त्याग करने का संदेश देने के स्थान पर राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाएं। ऐसा करते हुए उन्हें इस पर भी आत्ममंथन करना चाहिए कि राजनीतिक लाभ के लिए रेवड़ियां बांटने के चुनावी वादे करना कहां तक उचित था? कांग्रेस को कम से कम अब तो यह समझ आ ही जाना चाहिए कि आर्थिक नियमों और वित्तीय स्थिति की अनदेखी कर लोकलुभावन वादे करना तो आसान होता है, लेकिन उन्हें पूरा करना कठिन।

यह किसी से छिपा नहीं कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपने कई चुनावी वादों को अब तक पूरा नहीं कर सकी है। उसके कुछ वादे ऐसे भी रहे, जो आधे-अधूरे ढंग से ही पूरे किए जा सके हैं। चुनावी वादों को खटाखट पूरा करने का आश्वासन देने वाले कांग्रेस के नीति-नियंताओं के साथ ही आम जनता को भी आत्ममंथन करने की जरूरत है। उसे यह आभास होना चाहिए कि लोकलुभावन वादे करने वाले उसे केवल गुमराह ही नहीं करते, बल्कि उसके भविष्य से खिलवाड़ भी करते हैं। यह आभास केवल हिमाचल प्रदेश ही नहीं, अन्य राज्यों की जनता को भी होना चाहिए, क्योंकि रेवड़ी संस्कृति अपनाने वाले राजनीतिक दल बढ़ते जा रहे हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि जैसे हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट से दो-चार है, वैसे ही कर्नाटक और कुछ अन्य राज्य भी। कुछ राजनीतिक दल तो ऐसे हैं, जो मुफ्तखोरी वाली योजनाओं का बढ़ा करके सत्ता में आ जाते हैं और फिर उन्हें लागू करने के लिए केंद्र सरकार से अतिरिक्त धन की मांग करते हैं। जब केंद्र सरकार उनकी मांग पूरा करने के लिए तैयार नहीं होती तो वे उस पर खुद की अनदेखी करने का आरोप मढ़ते हैं। क्या यह किसी से छिपा है कि कुछ राज्यों ने किस तरह यह मालूम करवाया कि अमुक कालट में गैर भाजपा शासित राज्यों की उपेक्षा की गई है? इसी तरह दक्षिण के राज्य यह आरोप लगा चुके हैं कि केंद्र सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है।

प्रश्न सही मंच का

आज के दौर में इंटरनेट मीडिया अभिव्यक्ति का एक बड़ा मंच है, लेकिन सर्वाधिक अविश्वसनीय भी और झूठ को सच प्रचारित करने का माध्यम भी। इंटरनेट मीडिया के प्लेटफार्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम व यूट्यूब आदि ऐसे जाने कितनी सतही बातों से भरे पड़े होते हैं, जिनका कोई आधार नहीं होता और विडंबना यह कि फालोअर्स बढ़ाने की होड़ में इन्हें जमकर प्रसारित भी किया जाता है। यह तो लोगों को बाद में पता लगता है कि अमुक सूचना झूठी थी और बेसिर-पैर की थी। आश्चर्य की बात है कि सरकार इसे अपनी डिजिटल मीडिया नीति में ऐसे क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने का प्रविधान किया है। प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि इस नीति को बनाने से पहले अधिकारियों ने होमवर्क नहीं किया, अन्यथा उन्हें इस बात का अहसास अवश्य होता कि जिन्हें लाभ पहुंचाने की बात की जा रही है, उनकी विश्वसनीयता सर्वाधिक संदिग्ध है। सब्सक्राइबर और फालोअर्स बढ़ाने के लिए इंटरनेट मीडिया पर तरह-तरह के तिकड़म किए जाते हैं और अक्सर वे प्रायोजित भी होते हैं। सरकार की ओर से उन्हें विज्ञापन मिलेगा तो इसे और बढ़ावा ही मिलेगा।

अपनी योजनाओं और उनसे जनता को मिल रहे लाभ का प्रचार करना सरकार का अधिकार है, लेकिन उसके लिए ऐसा मंच होना चाहिए जिसे लोग विश्वसनीय मानें और जो सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन करे। किसलाल ले जनता के बीच इंटरनेट मीडिया की छवि ऐसी नहीं है। अपनी भावनाओं को साझा करना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन इंटरनेट मीडिया पर यह एक होड़ में बदलती दिखाई देती है। यही वजह है कि जाने कितनी बार समाज को कड़ी फटकार लगाने के बाद भी इंटरनेट मीडिया पर ऐसी सामग्री की भरमार है और सरकार को कड़ा कदम उठाना पड़ा है। इन्फ्लुएंसर्स की संख्या असंख्य है। इंटरनेट मीडिया पर शोर अधिक है, विश्वसनीयता कम। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि सरकार की डिजिटल मीडिया नीति का लाभ सही लोगों तक पहुंच सकेगा।

पेंशन क्षेत्र में बड़ा सुधार

गौरव वल्लभ

सरकारी खजाने पर यूपीएस के प्रभाव को कम करने के लिए सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने और सरकारी क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गत 24 अगस्त को एकीकृत पेंशन योजना यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को मंजूरी प्रदान कर दी। यह योजना सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सुरक्षित और सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। एक अप्रैल, 2025 से प्रभावी होने वाली यह योजना न केवल सरकारी कर्मचारियों की भविष्य की चिंताओं से मुक्त करती है, बल्कि सेवानिवृत्ति के बाद उनकी वित्तीय सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है। पिछले कुछ वर्षों में विपक्षी दलों ने राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस को एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में भुनाने का प्रयास किया। इसे आम तौर पर नई पेंशन योजना के रूप में भी जाना जाता है। एनपीएस की आलोचना मुख्य रूप से इस कारण होती थी कि बाजार में उतार-चढ़ाव के चलते पेंशन में अनिश्चितता बनी रहती है और एक निश्चित पेंशन के अभाव में सरकारी कर्मचारी अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त नहीं रह पाता। इसी आधार पर पुरानी पेंशन योजना की मांग होती थी। यूपीएस ने पेंशन संबंधी सभी प्रश्नों को संबोधित किया है। यूपीएस सुनिश्चित करती है कि सेवानिवृत्त लोगों को एक स्थिर और निश्चित पेंशन मिले, जो एनपीएस से उतना संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि यह बाजार से जुड़ी योजना है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों का योगदान तय होता है, लेकिन रिटर्न बाजार पर निर्भर करता है। चूंकि एनपीएस में पैसा बाजार में लगाया जाता है, इसलिए पेंशन की राशि निश्चित नहीं होती और बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर रहती है। यह एनपीएस की आलोचना का एक उल्लेखनीय बिंदु था।

यूपीएस की तीन प्रमुख विशेषताएं हैं। एक है सुनिश्चित पेंशन। यह 25 वर्षों की न्यूनतम सेवा के बाद सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 12 महीनों में कर्मचारी के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत होगी। यूपीएस के तहत अगर कोई कर्मचारी 10 वर्षों की सेवा के बाद रिटायर होता है, तो उसे न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। एनपीएस के तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10 प्रतिशत योगदान देता है, जबकि सरकार 14 प्रतिशत का योगदान देती है। यूपीएस में सरकारी योगदान बढ़कर 18.5 प्रतिशत हो गया है, जबकि कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान ही देंगे। यूपीएस की दूसरी विशेषता है मुद्रास्फीति सूचकांक। सभी प्रकार की पेंशन पर महंगाई राहत उपलब्ध होगी। इसकी तीसरी विशेषता है सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान। यह ग्रेच्युटी के अतिरिक्त होगा और इसकी गणना सेवानिवृत्ति की तिथि पर प्रत्येक छह माह की सेवा के लिए मासिक पारिश्रमिक (वेतन तथा महंगाई भत्ता) के 1/10वें भाग के रूप में की जाएगी।

प्रतीक रंगवाल

कई राज्य 2003 से पहले की पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस पर लौटने की घोषणा कर चुके हैं। यह निर्णय इन राज्यों की गैर-भाजपा सरकारों ने लिया था। ओपीएस गैर-अंशदायी और वित्तपोषित है। इसमें राज्य सरकार को तत्काल पेंशन फंड में अपने हिस्से का पैसा नहीं देना पड़ता। इससे पैसे की बचत होती है। हालांकि इससे सरकारों की बड़ी मात्रा में पैसा देन होगा। इससे इन राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा। आरबीआइ के अनुसार 2023-24 में पेंशन के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का कुल बजट अनुमान 5.22 लाख करोड़ रुपये है, जो बिते वर्ष 2020-21 के लिए 3.69 लाख करोड़ रुपये था। स्पष्ट है कि केवल तीन वर्षों में 41 प्रतिशत की उछाल आई।

अमेरिका में सेवानिवृत्ति आयु 67 वर्ष है। वहां कुल कार्यबल में सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों का प्रतिशत 13.4 है और जीवन प्रत्याशा 79.46 वर्ष है। जर्मनी में सेवानिवृत्ति आयु 67 वर्ष, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों का प्रतिशत 12.9 और जीवन प्रत्याशा 81.54 वर्ष है। जापान में सेवानिवृत्ति आयु 64 वर्ष, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों का प्रतिशत 7.7 और जीवन प्रत्याशा 84.85 वर्ष है। ब्रिटेन में सेवानिवृत्ति आयु 66 वर्ष, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों का प्रतिशत 22.5 और जीवन प्रत्याशा 81.45 वर्ष है। भारत में सेवानिवृत्ति आयु 60, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों का प्रतिशत 3.8 और जीवन प्रत्याशा 72.24 वर्ष है। पांच उन्नत देशों के मुकाबले अपने देश में सरकारी कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु सबसे कम है। दुनिया भर में बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता और नागरिकों के बीच स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता के कारण जीवन प्रत्याशा धीरे-धीरे बढ़ रही है। 1998 में सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष की गई थी। हालांकि तब भारतीय नगरिकों की जीवन प्रत्याशा केवल 61.4 वर्ष थी। 2024 तक जीवन प्रत्याशा तेजी से बढ़कर 72.24 वर्ष हो गई। पिछले 26 वर्षों में जीवन प्रत्याशा में 11 वर्षों की वृद्धि यह संकेत करती है कि इस वृद्धि को सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि द्वारा समायोजित किया जाए। इस विचार के खिलाफ एक तर्क यह है कि इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, खासकर सरकारी नौकरियों के लिए नई भर्ती संख्या में कमी आएगी, लेकिन यह ध्यान रहे कि हमारे देश में कुल कार्यबल के मुकाबले सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की संख्या दुनिया की छह बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे कम है। यह मात्र 3.8 प्रतिशत है। चीन में यह 7.89 प्रतिशत है। अन्य विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में यह 7 से 15 प्रतिशत के बीच है। हमें सरकारी क्षेत्र में नई नौकरियों की संख्या बढ़ानी चाहिए। इससे शासन और सार्वजनिक सेवाओं की दक्षता में सुधार होगा और सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि के कारण नई नौकरियों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।

यूपीएस पूर्वानुमानित पेंशन प्रदान करके उन सरकारी कर्मचारियों को लाभ पहुंचाएगी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्रसेवा के लिए समर्पित कर दिया है। यह सरकार के लिए भी लाभकारी है। यूपीएस में सरकार और कर्मचारी अपने वेतन का एक निश्चित प्रतिशत योगदान देंगे। यह पेंशन फंड सरकार के वित्तपोषित के ढांचे को बनाए रखने में मदद करेगा। सरकारी खजाने पर यूपीएस के प्रभाव को कम करने के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने और सरकारी क्षेत्र में अधिक नए रोजगार के अवसर पैदा करने के बारे में गंभीरता से सोचा जाना चाहिए।

(लेखक वित्त के प्रोफेसर एवं भाजपा नेता हैं, परंतु यहां व्यक्त विचार निजी हैं)

response@jagran.com

नए अध्यक्ष की प्रतीक्षा करती भाजपा

उमेश चतुर्वेदी

बदली परिस्थितियों में भाजपा के लिए अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन एक चुनौती बन गया है

जेपी नड्डा जी का उत्तराधिकारी। प्रेट

भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर इस समय खूब अटकलें लगाई जा रही हैं। मौजूद अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हुए दो महीने बीत चुके हैं। इस समय वह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का दायित्व भी संभाल रहे हैं। चूंकि भाजपा में एक व्यक्ति-एक पद का सिद्धांत स्वीकार्य है, अतः नए अध्यक्ष की खोज स्वाभाविक है। कई नामों की चर्चा भी है, लेकिन पिछले कुछ समय से पार्टी की कार्यसंस्कृति को देखते हुए कुछ भी कहना कठिन है कि अंतिम मुहर किस नाम पर लगेगी। छह महीने पहले तक जिसे पार्टी की अंतिम समझा जा रहा था, उसकी स्थिति आम चुनाव के बाद बदली है। यह पहलू नए अध्यक्ष के चयन में भी प्रभावी होता दिख रहा है। पार्टी ने जिन वर्गों में अपनी पैठ बढ़ाई थी, वह कुछ कमजोर होती दिख रही है। अति पिछड़े और दलितों में गैर-जाटव मतदाता पहले की भांति मंडल की राजनीति के इर्दगिर्द एक बार फिर गोलबंद होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में पार्टी के समक्ष दलित या पिछड़े बेट बैंक में बिसात के लिए इसी वर्ग से नया अध्यक्ष चुनने का दबाव हो सकता है। हालांकि पार्टी औपचारिक रूप से ऐसे किसी दबाव से इन्कार करती है। पार्टी में दलबदलुओं को तवज्जो मिलने से कोर बेट बैंक में भी निराशा दिख रही है। ऐसे में नए अध्यक्ष के लिए तमाम चुनौतियां प्रतीक्षा कर रही हैं।

फिलहाल अध्यक्ष पद के लिए जिन नामों की चर्चा है, उनमें केंद्रीय संगठन में सक्रिय महाराष्ट्र के बिनोद तावड़े के अलावा उनके ही राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम प्रमुख हैं। नए अध्यक्ष के मामले में भाजपा के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पसंद का भी खासा रुझान महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मौजूद अध्यक्ष नड्डा की आम चुनाव के दौरान संघ को लेकर की गई एक टिप्पणी ने दोनों पक्षों के बीच खटास बढ़ाने का काम किया था। नड्डा ने कहा था कि 'अब भाजपा को संघ की जरूरत नहीं पड़ती।' इन्हीं वजहों से माना जा रहा है कि मौजूदा माहौल में ऐसा व्यक्ति ही भाजपा की कमान संभाल सकता है, जो संघ और पार्टी में बेहतर तालमेल बिठा सके और जमीनी स्तर पर संतुलन बनाए रखते हुए संगठन को आगे ले बढ़ाए हो, अपने आधार बेट बैंक को फिर से आश्वस्त करे। इस लिहाज से देखा जाए तो फडणवीस और शिवराज सिंह चौहान दोनों ही संघ के नजदीकी हैं। दोनों का संघ के नेतृत्व से सहज संबंध है। इनमें शिवराज का पलड़ा भारी दिख रहा है। मध्य प्रदेश इन दिनों संघ और भाजपा की सफल प्रयोगशाला बन चुका है। जब तमाम राज्यों में भाजपा की सीटें घटीं, तब मध्य प्रदेश की सभी सीटें भाजपा के खाते में आईं। खुद शिवराज आठ लाख से ज्यादा मतों के अंतर से प्रचंड जीत हासिल करने में कामयाब रहे। हाल के दिनों में जिस तरह शिवराज सिंह चौहान ने कृषि मंत्री का दायित्व निभाया है, फिर चाहे संसद में एमएसपी पर विपक्ष के बोलती बंद करने हो या राहुल गांधी की गलत बयानी का जवाब देना, उससे उनकी नई छवि उभरी है। वह जमीनी नेता हैं और कार्यकर्ताओं से उनका सीधा संवाद भी है।

पखवाड़े भर पहले दिल्ली का दौरा करने वाले फडणवीस के बारे में चर्चा चली कि उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान खुद को संगठन में भेजने की खुली मांग रखी। इसके बाद उनके भाजपा अध्यक्ष बनने की चर्चा ने जोर पकड़ लिया। संघ से नजदीकी और उनकी कम उम्र भी मुफीद बैठती है। हालांकि महाराष्ट्र की राजनीति की जो हालत है, उसमें पार्टी शायद ही उन्हें अध्यक्ष बनाए। इसके बजाय उन्हें राज्य में महायुति के नेता के रूप में पेश किया जा सकता है। कुछ महीनों में ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य की राजनीति की दृष्टि से भी फडणवीस की बड़ी उपयोगिता है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना (शिंदे गुट), भाजपा और एनसीपी (अजीत पवार गुट) को कड़ी चुनौती देने के लिए विपक्षे महाविकास आघाड़ी (एमवीए) ने सामाजिक न्याय के त्रिकस्त देने के लिए हरसंभव प्रयास आरंभ कर दिए हैं। उद्धव ठाकरे ने साफ किया है कि भाजपा और शिंदे को रोकने के लिए वह सीएम पद की आकांक्षा छोड़ने को भी तैयार हैं। मौजूद लड़ाई को उद्धव राज्य के स्वाभिमान की रक्षा की लड़ाई भी बता चुके हैं। चूंकि राजनीतिक दृष्टि से महाराष्ट्र महत्वपूर्ण राज्य है और वहां पार्टी का बहुत कुछ दांव पर लगा है, इसलिए उसके लिए फडणवीस से बेहतर शायद कोई दूसरा विकल्प नहीं। अपने शासनकाल की उपलब्धियों के चलते फडणवीस की छवि अलग है। अपने शासनकाल में उन्होंने पारदर्शिता, जवाबदेही और बुनियादी ढांचे पर जोर दिया था। फडणवीस की हालिया पहल 'माझी लाड़की बहिन योजना' भी सफल मानी जा रही है, जिसमें आर्थिक स्वतंत्रता के साथ ही स्वास्थ्य और पोषण सुधार के लिए महाराष्ट्र में 21 से 65 वर्ष वाली महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपये की पेशकश की गई है। इन्हीं वजहों से भाजपा शायद ही फडणवीस को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए। इसके बजाय उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति की पूरी कमान सौंपी जा सकती है।

ऐसे में शिवराज सिंह चौहान की लेकर उम्मीद बढ़ जाती हैं। हालांकि तब केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनका कारगर विकल्प खोजने की चुनौती भी कम बड़ी नहीं होगी। यह समय बताएगा कि बिनोद तावड़े, देवेंद्र फडणवीस और शिवराज सिंह चौहान में से ही कोई अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालता है या फिर पार्टी किसी और नाम पर विधानसभा चुनाव निपटने के बाद ही मुहर लगने के आसार हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

सुख और दुख

मनुष्य की प्रायः यही शिकायत होती है कि सुख का समय बहुत जल्दी बीत जाता है और दुख का दौर धीरे-धीरे सरकता है। यह हमें बताता है कि समय की माप भी सापेक्ष और मन पर निर्भर है। इसी तरह सुख और दुख भी सापेक्ष हैं। स्वादिष्ट भोजन करना सुखद है, लेकिन उसे भी अत्यधिक मात्रा में खाना दुखद्ई हो जाता है। इसलिए, भोजन कितना भी प्रिय क्यों न हो उसके उपभोग का उचित अनुपात ही श्रेयस्कर होता है। वस्तुतः, पूरा जीवन ही सुख-दुख का एक मिश्रण है। अगर कोई हमारी प्रशंसा करे तो सुख मिलता है। उस सुख के साथ हमारे अंदर अहंकार का भाव भी बढ़ जाती है। यह अहंकार दुख का कारण बनता है। स्मरण रहे कि सुख की तो दुख की जन्म होता है। यदि हमने कभी जीतना ही नहीं चाहा तो हमें हराया भी नहीं जा सकता। जीवन एक बाद चक्र की तरह है, जिसमें सारे रंग बनाए जा सकते हैं। यह हम पर निर्भर है कि हम किस धुन और कौन से राग के साथ जीवन का आनंद लेना चाहते हैं।

प्रकृति हमें दो वरदान प्रदान करती है-शरीर और बुद्धि। ये दोनों समय के साथ बढ़ते रहते हैं। अपनी बुद्धि के विकास और शारीरिक बल को बढ़ौतल हमने अपने सुविधा के साधन जुटा लिए हैं। यदि यहीं से जुटाए गए इन सुख-साधनों में कहीं कोई कमी होती है या कुछ कुछ रुक जाता है तो फिर दुख देखा। उस पर रोना किसी काम का। जो हमारा था ही नहीं, यहीं से मिला उसके यहीं पर खेने का अहसास ही हमारे दुखों की जड़ है। जब तक हम भौतिक चीजों को ही जीवन में सब कुछ मानते रहेंगे, तब तक हम वास्तविक आनंद को अनुभव नहीं कर पाएंगे। हमने यहां जो भी पाय है, उनमें न तो शाश्वत सुख है और न ही परम आनंद। ये तो बस सुगमता से रहने के साधन मात्र हैं। उन्हें केवल साधनों के रूप में देखा जाए न कि संपत्ति के रूप में। यदि उन्हें संपत्ति समझते रहेंगे तो उन्हें गंवाने में विपत्ति की सी अनुभूति होती रहेगी।

डा. निर्मल जैन

पोषण व्यवस्था को प्रोत्साहन

ठोंढ़ठड सुधार

ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के मंचेश्वर में हाल ही में देश के पहले अनाज एटीएम (ग्रेन एटीएम) का उद्घाटन किया गया। इस पहल के साथ ओडिशा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लाभार्थियों को 24 घंटे सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह पहल ओडिशा सरकार और विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच एक सहयोग है, जिसका उद्देश्य राज्य में पोषण सुरक्षा को बढ़ाना है।

यह एटीएम चौबीसों घंटे चावल या गेहूं वितरित करता है। मशीन से अनाज प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल है, इसके लिए केवल आधार या राशन कार्ड नंबर और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। प्रमाणीकरण के बाद लाभार्थियों की उनका आवंटित अनाज मिल जाता है। ज्ञात हो कि अन्नपूर्णा प्रणाली सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करती है, जिससे वैध पीडीएस राशन कार्ड वाले किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का क्यों न हो, अपने हक का अनाज प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। यह मशीन केवल पांच मिनट में 50 किलोग्रम तक अनाज वितरित कर सकती है, और प्रतीक्षा समय को व्यापक रूप से कम कर सकती है। इसका मादवृतर डिजाइन विभिन्न स्थानों में आसान असेंबली की अनुमति देता है और यह ऊर्जा-कुशल है, जो प्रति एटीएम केवल 0.6 जट की खपत करता है।

यह नवाचार न केवल तकनीकी उन्नति का उदाहरण है, बल्कि सामाजिक कल्याण और पोषण सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है। हालांकि जैसा कि किसी भी नई तकनीक के साथ होता है, अनाज एटीएम के कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां भी हैं। इस तकनीक को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित करन और उसका रखरखाव करन एक बड़ी चुनौती हो सकती है। दूसरा, डिजिटल साक्षरता की कमी कुछ लाभार्थियों के लिए इस प्रणाली का उपयोग करना मुश्किल बना सकती है। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पर निर्भरता कभी-कभी समस्याएं पैदा कर सकती है, खासकर बुजुर्गों के लिए, जिनके फिंगरप्रिंट स्पष्ट नहीं होते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए वैकल्पिक प्रमाणीकरण विधियों पर विचार किया जाना चाहिए।

अनाज एटीएम इन बाधाओं को लाभार्थियों को अपना राशन प्राप्त करने के लिए लंबी कतारों में खड़े होने या दुकान खुलने का इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। यह सुविधा उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो दिहाड़ी मजदूर हैं। यह तकनीक परदर्शी भी है, जो भ्रष्टाचार और गबन की संभावना को कम करती है। यदि इसे सफलतापूर्वक क्रियान्वित और विस्तारित किया जाता है, तो यह माडल देश के अन्य हिस्सों के लिए उदाहरण बन सकता है, जो भारत की खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति में सुधार ला सकता है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

अनाज एटीएम की शुरुआत स्वागत योग्य है जो तकनीकी नवाचार और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन बनाता है

मेलबाक्स

सहयोगियों से मंत्रणा आवश्यक

'संकट के दौर से गुजरती भाजपा' शीर्षक से लिखे आलेख में राजीव सचान ने विपक्ष के झूठे बिमर्श से मात खाती भाजपा और यू टर्न लेती मोदी सरकार के विषय में जो कुछ भी कहा है, उससे असहमत नहीं हुआ जा सकता। हाल के लोकसभा चुनाव में भाजपा को अपेक्षित बहुमत न मिल पाने के कारण मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल थोड़ा कंटकाकीर्ण हो गया है। अब समर्थन देने वाले दलों को बिखरू में लेकर निर्णय लेने मोदी सरकार को मजबूरी बन गई है। ऐसे में कोई जरूरी नहीं कि समर्थन देने वाले प्रमुख दलों के मुखिया किसी एक मुद्दे पर एकमत हो ही जाएं। मतभिन्नता की स्थिति में मोदी सरकार को यू टर्न भी लेना पड़ सकता है। इसमें न केवल विपक्ष की सत्ता पक्ष पर हमलावर होने का अवसर मिलेगा, अपितु सरकार की भी अपने सफाई देने पड़ेगी। इन विषमताओं में मौजूद सरकार के लिए कड़े निर्णय ले पाना मुश्किल हो रहा है। चक्र विशेषक इसका उदहरण है जिसे मोदी सरकार को जेपीसी में भेजने के लिए विवश होन पड़ा। अब आगे इस विधेयक की क्या स्थिति बनती है, यह भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इस पर विपक्षे दल अब भी सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। इन स्थितियों में अब भाजपा के सहयोगी दलों को राष्ट्रहितैषी मुद्दों पर दृढ़तापूर्वक मोदी सरकार के साथ खड़ा होने की जरूरत है, ताकि विपक्षे दल केवल विरोध के लिए विरोध की नकारात्मक राजनीति करने और मोदी सरकार के विरुद्ध जनभावना की भड़काने के लिए सरासर झूठा बिमर्श खड़ा करने में कामयाब न हो सकें। बहुमत से दूर रहने का खमियाजा उठाती भाजपा को भी अब नीतिगत निर्णय से पहले अपने सहयोगी दलों के साथ पर्याप्त विचार-विमर्श करने की जरूरत है ताकि हास्यास्पद यू टर्न की स्थिति न बने।

डा. वीरे पाण्डेय, अलीगढ़ (उ.प्र.)

ममता की हताशा

बंगाल में प्रशिक्षु डाक्टर के साथ दुष्कर्म और नृशंस हत्या से देश में उबाल है। बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति भयावह है। महिला डाक्टर को न्याय दिलाने के नाम पर छात्रों का आंदोलन बंगाल सहित पूरे देश का समर्थन हासिल करता नजर आता है। देश की राष्ट्रपति का यह कहना कि बहुत हो चुका अब भय लगने लग है, निश्चित ही राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े करता है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह कहना कि अगर बंगाल जला तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, असम व देश के उनसे पूर्व खेलें में भी आग लग जाएगी। इसमें निश्चित ही राष्ट्र विरोधी बयान के साथ मुख्यमंत्री की राजनीतिक हताश नजर आती है। क्या एक राज्य में बार-बार बाहरी आदमी घुसकर सुरक्षा और कानून व्यवस्था के सवाल खिलवाड़ कर सकते हैं? इसका मतलब यह है कि राज्य के शासन-प्रशासन का हाल पूरी तरह लचर है। बंगाल में चुनावों के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा, आगजनी, दंगा-फसाद की घटनाएं क्यों होती हैं?

दीपक गौतम, सोनीपत, हरियाणा

जातपात की राजनीति

जगमोहन सिंह राजपूत के आलेख ''सीकोर्न स्वार्थों के लिए जाति का सहारा'' का केंद्र बिंदु चुनावों में जातिगत राजनीति है। एक समय कांग्रेस का नारा था- जात पर न पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर। समय और परिस्थितियों में बदलाव आया और स्थिति यह हो गई है- जातियों ही चुनाव की छड़ी बन गईं, मुक्किलें इसीलिए खड़ी हो गईं, लोकतंत्र का बटल रहा स्वरूप, जब कुर्सियों ही देश से बड़ी हो गईं। वस्तुतः हमारे देश का संविधान जाति प्रथा को पूरी तरह अस्वीकार करता है। जिस समय संविधान बना, उस समय जाति प्रथा उन्मूलन को आवश्यक समझा गया। स्वतंत्रता संग्राम लोगों को जातियों में बांटकर नहीं लड़ा गया। जो लत या लोग निजी या दलगत स्वार्थ के लिए और जाति को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं, वे इसके दूरगामी परिणाम नहीं देख पा रहे हैं। यह देश के भविष्य से खिलवाड़ है। कहने को तो सभी संविधान में आस्था रखते हैं, पर संविधान के आत्मा पर गहरी चोट कर रहे हैं।

कैलाश मेहरा, गुरुग्राम

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:

दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संपादक- एम. पुष्पेश पंत, पूर्व प्रधान संपादक- एम. सेंगर मोहन, चीफ एग्जीक्यूटिव एडिटर एंड पब्लिशर- ओनर मोहन पुरुष, प्रधान संपादक- संजय पुरुष, जगरण प्रकाशन लि. के लिए; सेक्टर 59 ऑद्योगिक क्षेत्र इला 501, आई.एस.एस. बिल्डिंग, तमी धर्म, नई दिल्ली से प्रकाशित और उसी के इला डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, नोएडा (उ.प्र.) संस्करण। *वैधानिक प्रसारणजिम्मेदारी*
मुख्यालय: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43166300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त सामग्री के पूर्ण एवं एकमात्र कॉपीराइट दैनिक जागरण के अधीन हैं। सामग्री का किसी भी रूप में पुनर्प्रकाशन, पुनर्प्रसारण या पुनर्प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। कानूनी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र नोएडा होगा।

पेरिस पैरालिम्पिक

भारतीय सहभागिता

पेरिस 2024 पैरालिम्पिक खेलों में भारत ने 84 पैरा-एथलीट का अब तक का सबसे बड़ा समूह भेजा है। बुधवार से शुरू पेरिस 2024 पैरालिम्पिक खेलों में 164 देशों के दिव्यांग एथलीट भाग ले रहे हैं। भारत ने इसमें अब तक की सबसे अधिक 84 एथलीटों की टीम भेजी है। इस वर्ष के आयोजन एथलीटों की अदम्य इच्छाशक्ति का प्रदर्शन करेंगे जो दुनिया को अपनी असाधारण दृढ़ता तथा विपरीत स्थितियों पर विजय की भावना से लगातार प्रेरित करते हैं। 2024 पेरिस पैरालिम्पिक में भारत की सहभागिता देश के लिए उल्लेखनीय क्षण है। विभिन्न खेलों के 84 एथलीटों के साथ भारत ने अपना सबसे बड़ा और सर्वाधिक विविधतापूर्ण समूह पेश किया है। इससे भारत में पैरालिम्पिक खेलों की बढ़ती पहचान व उनको मिलने वाले समर्थन का पता चलता है। इसके साथ ही पूर्व-धारणाओं को चुनौती देने तथा श्रेष्ठता को पुन: परिभाषित करने वाले एथलीटों की संख्या भी बढ़ रही है। पैरालिम्पिक खेलों का समृद्ध इतिहास है जिसकी शुरुआत 1948 में हुई थी। उस समय सर लुडविग गटमैन ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग ले चुके ऐसे लोगों की खेल प्रतियोगिता इंग्लैंड के स्टोक मिडविले में आयोजित की थी जो रीढ़ की हड्डी में चोट के शिकार थे। पिछले दशकों में पैरालिम्पिक्स का असाधारण विस्तार हुआ है और यह दिव्यांग एथलीटों के लिए वैश्विक मंच बन गया है। वे यहां अपनी असाधारण प्रतिभा तथा 'संभावनाओं' की सीमायें तोड़ने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं।

भारतीय एथलीटों में युवा तीरंदाज शीतल देवी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है जिन्होंने सारी बाधाओं को पार करते हुए बिना हाथों के उच्चतम स्तर प्राप्त किया है। शीतल की यात्रा पूर्णत: असाधारण है। धनुष और बाण का प्रयोग करने के लिए वे अपने पैरों का इस्तेमाल करती हैं। उन्होंने एक विशेष तकनीक विकसित की है जिसने उनको दुनिया का सर्वाधिक प्रतिभाशाली तीरंदाज बना दिया है। उनकी यात्रा हमें बताती है कि अक्सर सीमायें दिमाग में होती हैं और प्रतिबद्धता व खोज से उनको पार किया जा सकता है। 2024 पैरालिम्पिक में शीतल देवी की सहभागिता एक व्यक्तिगत उपलब्धि से आगे जाती है। यह दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए उम्मीद और दृढ़ता का प्रतीक है। अपनी सीमाओं को पार करने की उनकी क्षमता ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है और वे मानवीय भावना की सच्ची खिलाड़ी बन कर उभरी हैं। 2024 पैरालिम्पिक्स एथलीटों और दिव्यांगों की असाधारण क्षमताओं के पारंपरिक प्रदर्शन का उत्सव मनाता है। इन खेलों का संबंध केवल मैडल जीतने से न होकर बाधायें तोड़ने, सामाजिक अवधारणाओं को चुनौती देने तथा भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने से भी है। ज्यादा खेलों को शामिल करने तथा भारत जैसे देशों की बढ़ती सहभागिता से पैरा-खेलों को दुनिया भर में व्यापक स्वीकार्यता और प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है। पेरिस में प्रतियोगिता कर रहे एथलीटों के साथ शीतल देवी जैसे लोगों की साहसी गाथायें जुड़ी हैं। इससे हमें उत्कृष्टता की खोज में भौतिक सीमाओं को पार करने तथा लोगों को एकसाथ लाने में खेलों की शक्ति का भी पता चलता है। पैरालिम्पिक खेल एक वैश्विक मंच प्रदान करते हैं जहां एथलीट अपनी दृढ़ता प्रदर्शित करते हुए दिखाते हैं कि कुछ भी संभव है। भारत की अब तक की सबसे बड़ी टीम तथा शीतल देवी की प्रेरणादायक गाथा पैरालिम्पिक आंदोलन की भावना प्रकट करती है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी एथलीट लाखों लोगों को प्रेरित करते हुए यह सिद्ध करेंगे कि प्रतिबद्धता और पूरी एकाग्रता से सामना करने पर कोई भी बाधा अलंघ्य नहीं होती है।

अफगानिस्तान में हिंसा व गद्दारी

काबुल लंबे समय से अफगानिस्तान में दृढ़ता का प्रतीक रहा है, पर हफीजुल्ला अमीन जैसे उसके अनेक नेताओं के कारनामे रहस्य और विवादों में घिरे रहे हैं।

नीलांत इलांगमुवा
(लेखक, वरिष्ठ पत्रकार हैं)

समुद्र तल से एक मील ऊपर स्थित काबुल पश्चिम में पगमान पहाड़ियों से घिरा है जो परंपरागत रूप से काबुल के विशिष्ट लोगों का विश्राम स्थल रही हैं। पगमान का आनन्ददायक मौसम तथा ऐतिहासिक महत्व उल्लेखनीय घटनाओं का स्थल भी है। इसमें स्वतंत्रता के लिए राजा अमानुल्ला का संघर्ष तथा 1920 में बुखारा के अमीर का शरण लेना शामिल है। यह शहर विदेशी प्रभुत्व के खिलाफ अफगानिस्तान के प्रतिरोध का प्रतीक भी है। 1929 में पगमान में जन्मे हफीजुल्ला अमीन महाशक्तियों के प्रभुत्व के खिलाफ कट्टर विरोधी के रूप में उभरे। नेता के रूप में उनका कार्यकाल केवल 104 दिन का था जो 1979 में उनकी हत्या से समाप्त हुआ। यह अफगानिस्तान की राजनीति में परिवर्तन का समय था। अमीन की प्रारंभिक शिक्षा काबुल में हुई और बाद में वे कोलम्बिया विश्वविद्यालय के छात्र रहे। राजनीतिक उथलपुथल के कारण उनकी राजनीति में सहभागिता हुई। नूर मुहम्मद तराकी से उनके संबंध तथा मास्को होकर अफगानिस्तान में उनकी वापसी ने उनकी चरमपंथी सोच और राजनीति मार्ग को निर्धारित किया।

लेकिन आरोप था कि अमीन सीआईए एजेंट हैं, जबकि उनको वामपंथियों का भी समर्थन प्राप्त था। बबराक करमाल ने उनको अपने शासन को वैध ठहराने के लिए गले लगा लिया। कमाल का दावा था कि वे अमीन के कथित सीआईए संबंधों को 1950 के दशक से ही जानते थे और वे इसके दस्तावेजी सबूतों का अपने पास होने का दावा भी करते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसका कोई विश्वसनीय प्रमाण कभी नहीं दिया। कुछ विदेशी समाजवादी निजी रूप से इस दावे का खंडन करते हुए संकेत करते थे कि नई सरकार का इरादा अमीन का खासकर अफगान किसानों में सीआईए एजेंट बता कर सम्मान गिराना था। करमाल के हमदर्दों का कहना था कि अफगान जनता अमीन की नीतियों से नाराज थी जिनको क्रांति के लिए हानिकारक माना जाता था, इसीलिए उनको सीआईए एजेंट बताया गया। हालांकि, सोवियत संघ ने 1980 के दशकारंभ में इस विमर्श को अफगानिस्तान पर एक फिल्म के माध्यम से प्रचारित किया था, पर ये अपने अंतरराष्ट्रीय संपर्कों के बारे में बहुत सावधान रहते थे।

अंतरराष्ट्रीय मामलों पर प्रकाशित 'थर्ड वर्ल्ड' में सीआईए संबंधी एक लेख में अमीन का कोई संदर्भ नहीं था। एक टिप्पणीकार का कहना था, 'रूसियों और अमेरिकनों के लिए असहज करने वाला यथार्थ यह था कि अमीन ने दोनों पक्षों की ओर से उठाए षड्यंत्रकारी कदमों का विरोध किया था।' यदि अमीन को एक नरसंहार करने वाले तानाशाह, सोवियत मुहरे या सीआईए एजेंट के तौर पर पेश करने वाला विमर्श बिना प्रमाण के है तो सच्चाई क्या है? वास्तव में अफगानिस्तान की क्रांति में अमीन की भूमिका क्या थी और सोवियत संघ ने उनका सफाया करना क्यों ठीक समझा? अगस्त, 1978 में नूर मुहम्मद तराकी ने इस्लामी विरोध आंदोलन को संबोधित करते हुए पूंजीवादी और प्रतिक्रियावादी शक्तियों की आलोचना की थी जो इस क्षेत्र का प्रयोग प्रगतिशील एजेंडे को पराजित करने के लिए कर रही थीं। उनका विश्वास था कि साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित ये ताकतें पुरानी हो गई थीं और उनका विफल होना अवश्यंभावी था।

लेकिन अपने इस विश्वास के बावजूद तराकी को अनेक आंतरिक विद्रोहों का सामना करना पड़ा। इनमें हफीजुल्ला अमीन का विद्रोह महत्वपूर्ण है जिनकी महत्वाकांक्षायें उनके नेतृत्व को खतरा पैदा कर रही थीं। सोवियत समर्थन पर तराकी की निर्भरता नाकाफी सिद्ध हुई क्योंकि इसका कारण उनमें राजनीतिक दूरदर्शिता का अभाव तथा सामाजिक यथार्थ को अस्वीकार करना था जिसने अतिवादी समूहों को सुनहरा अवसर प्रदान कर दिया। पुरानी गलतियां ठीक करने तथा बबराक के नेतृत्व में नई सरकार बनाने की योजना अमीन की त्वरित कार्रवाई से विफल हो गई।

तराकी द्वारा अमीन को गिरफ्तार करने तथा बबराक के साथ राष्ट्रीय सहमति स्थापित करने के प्रयासों के बावजूद अफगानिस्तान में बिगड़ती सुरक्षा स्थितियों ने बाहरी सैनिक हस्तक्षेप की अपरिहार्य बना दिया था। अमीन द्वारा तेजी से सत्ता को मजबूत करने तथा बाद में तराकी के राजनीतिक संघर्षों ने अफगान राजनीति की अस्थिर व खतरनाक स्थिति उजागर कर दी जिसके परिणामस्वरूप अस्थिरता और बढ़ी। हफीजुल्ला अमीन पर शक था कि वे उसके सिद्धान्तों को मानने के बजाय मार्क्सवाद का प्रयोग राजनीतिक औजार के रूप में कर रहे थे, जबकि सार्वजनिक रूप से वे स्वयं को कट्टर धार्मिक व्यक्ति के रूप में पेश करते थे। उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति के बावजूद उनको खासकर 'परचम' समूह से काफी विरोध का सामना करना पड़ता था। इस आंतरिक टकराव के कारण वे पीडीपीए की राजनीतिक समिति के पूर्ण सदस्य जल्दी नहीं बन पाए। हालांकि, अमीन इन चुनौतियों से निपटने व अफगान राजनीति की प्रमुख शक्ति बनने में सक्षम थे।

मास्को के साथ मित्रता संधि करने से उनकी क्षमता स्पष्ट होती है जिससे वे उथलपुथल वाली स्थिति में सफल हुए थे। इस संबंध में सितंबर, 1979 में तराकी की क्यूबा यात्रा और इसके बाद मास्को में अपने प्रतिद्वंद्वी बबराक करमाल के साथ बैठक महत्वपूर्ण थी। अनुमान था कि तराकी बबराक करमाल से संबंध सुधार कर अमीन को सत्ता से हटाना चाहते थे और सत्ता में शक्तियों का विभाजन करना चाहते थे। इन बातों में सोवियत प्रभाव ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तराकी और बबराक के बीच शत्रुता से संकेत मिलता है कि किसी प्रकार के राजनीतिक समझौते के लिए सोवियत प्रभाव जरूरी था। यह खासकर इसलिए महत्वपूर्ण था कि तराकी लंबे समय से बबराक से घृणा करते थे और अमीन की भूमिका उनकी सत्ता में बाधा थी। 'खल्क' और 'परचम' समूहों के बीच राजनीतिक अस्थिरता ने अफगानिस्तान प्रशासन को कमजोर किया और उसे अतिवादी समर्थन के लिए खतरा बना दिया। सुरक्षा की स्थिति खराब होने तथा अफगान सेना के संघर्ष करने के कारण तराकी ने व्यवस्था संभालने के लिए सोवियत हस्तक्षेप को जरूरी माना। अमीन को गिरफ्तार कर बबराक के साथ नई सरकार बनाने के तराकी के प्रयास विफल हो गए और अमीन ने तेजी से राजनीतिक समस्या सुलझा ली। उस कालखंड की जटिलतायें और चुनौतियां अफगान राजनीति की परिवर्तनशीलता तथा उसे निर्धारित करने में बाहरी हस्तक्षेपों की स्थिति स्पष्ट करती हैं।

दिसंबर, 1979 के प्रारंभ में यूरी आंद्रोपोव ने लियोनिद ब्रेझनेव को अमीन की गोपनीय गतिविधियों की जानकारी दी जिसमें उनका पश्चिम की ओर झुकाव तथा अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट शासन को संभावित खतरा शामिल था। इससे सोवियत प्रभाव को खतरा पैदा हो सकता था। आंद्रोपोव ने बबराक करमाल व उनके साथियों की सहायता के लिए सैनिक सहायता की आवश्यकता पर जोर दिया, हालांकि उन्होंने पूरी तरह सोवियत सैनिक हमले की रूपरेखा नहीं पेश की थी। लेकिन आंद्रोपोव का प्रमुख लक्ष्य अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप की योजना को मूर्त रूप देना था।

इसके बाद आंद्रोपोव, दिमित्री उस्तीनोव, आंद्रे ग्रोम्को तथा खोरिस पोनोमारेव ने ब्रेझनेव के साथ बैठक कर सोवियत सैनिक कार्रवाई सुनिश्चित कर दी। पोलित ब्यूरो ने पूरी गोपनीयता के साथ इन अधिकारियों को हमले के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंप दी। इस योजना के दस्तावेजों को हाथ से पोलित ब्यूरो सदस्यों द्वारा लिखा गया और टाइपिस्टों को भी पूरी प्रक्रिया से बाहर रखा गया। मार्शल अख्रोमायेव और जनरल स्टाफ आपरेशन्स ने अफगान सीमा के निकट अपना अड्डा बनाया, जबकि केजीबी ने काबुल में अमीन को सत्ता से हटा कर 'आपरेशन अगेट' शुरू कर दिया। केजीबी की टीम ने गोपनीय रूप से अमीन के महल में घुसपैठ कर उनको जहर देने की योजना बनाई। लेकिन यह योजना ठीक से कार्यान्वित नहीं हो सकी। हफीजुल्ला अमीन के दामाद और उनकी सुरक्षा के प्रमुख अचानक 'फूड प्वायजनिंग' से गंभीर बीमार हुए और उनको इलाज के लिए मास्को भेजा गया। कहा जाता है कि यह भोजन अमीन के घर, वे ये भोजन के संबंध में अपनी सावधानी से बच गए।

जीवनरक्षा व समुदायों का सशक्तीकरण

देश की पहली महिला स्वास्थ्य पहल होने के कारण चेतना को महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और लिंग के मामले में एक ट्रेंडसेटर बनाने में मदद मिली।

स्वप्ना मजूमदार
(लेखिका वरिष्ठ पत्रकार हैं)

जब जुल्कीबेन, एक दाई या पारंपरिक प्रसव परिचारिका (टीबीए) को एक गर्भवती महिला का फोन आया, तो वह तुरंत हरकत में आ गई। सबसे पहले, उसने राज्य सरकार की आपातकालीन एम्बुलेंस का नंबर 108 डायल किया। गर्भवती महिला के घर पहुंचने के बाद, उसने अस्पताल में इस्तेमाल करने के लिए एक साफ कपड़े के टुकड़े काटे और पानी लाने और स्टोर करने के लिए एक खाली लोटा (पानी का कंटेनर) तैयार रखा। लेकिन जब महिला को प्रसव पीड़ा बढ़ गई और उसके लिए एम्बुलेंस तक पहुंचने के लिए पहाड़ी से नीचे उतरना असंभव हो गया, तो जुल्कीबेन ने पड़ोस के युवकों को बुलाया और एक चादर से गोफन बनाया और गर्भवती महिलाओं को एम्बुलेंस तक पहुंचाया। वे मुश्किल से अस्पताल के लेबर रूम में पहुंचे थे जब महिला ने प्रसव किया। जुल्कीबेन की सूझबूझ और समय पर कार्रवाई ने मां और बच्चे की जान बचाने में मदद की।

यह केवल जुल्कीबेन जैसी टीबीए ही नहीं थीं, बल्कि गुजरात के नवसारी जिले के दो आदिवासी ब्लॉकों, वंसदा और चिखली के 60 गांवों की महिलाओं, उनके परिवारों और समुदाय के सदस्यों ने सीखा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की मातृ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बनाकर मातृ मृत्यु को रोका जा सकता है। वास्तव में, अहमदाबाद स्थित गैर-लाभकारी संस्था सेंटर फॉर हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग न्यूट्रिशन एंड एडोलसेंट्स (चेतना) द्वारा इन दो ब्लॉकों में तीन साल की पहल ने महिलाओं, किशोरों और बच्चों को सशक्त बनाने के लिए उल्लेखनीय बदलाव किए। वंसदा ब्लॉक में संस्थागत प्रसव में 58त्न से 82त्न की वृद्धि हुई। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हस्तक्षेप के अंतिम चरण के दौरान हुए 776 प्रसवों में से, क्षेत्र में एक भी मातृ मृत्यु दर्ज नहीं की गई। यह कैसे हासिल किया गया? ऐसा क्या अलग किया गया जिससे व्यवहार में बदलाव आया? क्या यह सफलता महिलाओं के लिए खराब स्वास्थ्य संकेतकों वाले अन्य जिलों में दोहराई जा सकती है?

इन सभी सवालों और अन्य सवालों के जवाब हाल ही में प्रकाशित कॉफी टेबल बुक में दिए गए हैं, जो उनके चालीसवें वर्ष के मील के पत्थर को चिह्नित करता है। चेतना-40-सपनों को पोषित करना, नियति को सशक्त बनाना शीर्षक वाली यह पुस्तक संगठन के चार दशकों के सामूहिक प्रयासों, इसके विशिष्ट दृष्टिकोणों और इसकी अभिनव संचार रणनीतियों द्वारा किए गए प्रभाव का वर्णन करती है, जिसने सात राज्यों के 78 जिलों, 124 ब्लॉकों और 439 गांवों में अनगिनत लोगों के जीवन और समुदायों को बदल दिया। चेतना की सह-संस्थापक और निदेशक पल्लवी पटेल कहती हैं कि बदलाव लाने की इसकी क्षमता के पीछे सबसे बड़ा कारण इसके सभी कार्यों में लैंगिक दृष्टिकोण को शामिल करने पर इसका ध्यान केंद्रित करना है। देश की पहली महिला स्वास्थ्य पहल होने के कारण चेतना को महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और लिंग के मामले में एक ट्रेंडसेटर बनाने में मदद मिली।

इसके अद्वितीय दृष्टिकोण और प्रभावशाली संचार सामग्री ने इसे दूसरों पर बढ़त दिलाई। उनके संसाधनों की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अकेले 2022-2023 में, 11 राज्यों में स्थित विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा चेतना की सामग्री की 2,77,981 से अधिक प्रतियां मांगी गईं।

यह पुस्तक राजस्थान और गुजरात में न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधाओं वाले दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों में प्रसव संबंधी जटिलताओं से निपटने की चुनौतियों से निपटने के लिए लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई रणनीतियों के बारे में बताती है, साथ ही गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में व्यापक पोषण संबंधी एनीमिया से निपटने के लिए भी। यह इस बात का भी खुलासा करती है कि चेतना ने अहमदाबाद में 70 स्कूलों को तंबाकू मुक्त प्रमाणित करने के लिए व्यवहार में बदलाव लाने के साथ-साथ गुजरात के मेहसाणा में मानसिकता में भी बदलाव लाया, जो अस्सी और नब्बे के दशक में सबसे खराब बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) वाले जिलों में से एक था। सास-बहू बैठकों, जाति पंचायत नेताओं के साथ बातचीत और बच्चे के लिंग निर्धारण में एक्स और वाई गुणसूत्रों की भूमिका समझाने के लिए अभिनव दाल-चावल खेलों के माध्यम से बेटे को प्राथमिकता देने की मानसिकता और लड़की के जन्म पर महिला को दोष देने की प्रथा को संबोधित किया गया।

इन प्रयासों के केंद्र में चेतना की अनुकूलनशील, लचीली और रचनात्मक होने की क्षमता रही है। बॉक्स से बाहर सोचने के अलावा, स्थानीय जरूरतों, परंपराओं और प्रथाओं के अनुसार स्वास्थ्य संदेशों को भी बदला गया है। उनके अभिनव एनीमिया किट में कई बदलाव किए गए हैं, जैसे कि उनके अनूठे और बेहद लोकप्रिय कपड़े के एप्रन, जिनमें कई फ्लैप हैं, जिन्हें पुरुष और महिला प्रशिक्षक दोनों लिंगों के प्रजनन अंगों को दिखाने के लिए पहनते हैं। बच्चों की देखभाल, पोषण, यौवन, मासिक धर्म, किशोर स्वास्थ्य, एनीमिया और गर्भनिरोधक पर ज्ञान साझा करने के लिए गाने, खेल और एनीमेशन फिल्में बनाई गई हैं।

पुस्तक में विस्तार से बताया गया है कि कैसे चेतना, जो 1966 में प्रख्यात वैज्ञानिक विक्रम साराभाई द्वारा स्थापित नेहरू फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट के सहजीवी छत्र के तहत काम करती है, ने स्थायी प्रभाव डालने के लिए अपने वैज्ञानिक और आविष्कारशील स्वास्थ्य संचार का रणनीतिक रूप से उपयोग किया। चाहे मासिक धर्म पर चुप्पी तोड़ना हो या लड़कियों के लिए सक्षम वातावरण बनाना हो, चेतना ने दिखाया है कि 40 साल पहले महिलाओं को अपने भाग्य की मालकिन बनाने का जो सपना उसने शुरू किया था, वह असंभव नहीं था।

आप की बात

राष्ट्रपति की पीड़ा

राष्ट्रपति के रूप में देश की प्रथम महिला द्रोपदी मुर्मु भी कोलकाता की दर्दभरी घटना और उस पर देश भर में पैदा आक्रोश से चिंतित हैं। वे कोलकाता के साथ ही देश भर में छोटी-छोटी बच्चियों तक से होने वाले अत्याचारों से आहत भी हैं। राष्ट्रपति ने व्यापक रूप से पुरुषों में महिलाओं को दोयम दर्जे का समझने की सोच पर सवाल उठाते हुए स्थिति में सुधार की आवश्यकता बताई है। राष्ट्रपति ने भले ही कोलकाता का नाम लिया हो, पर उनका संकेत पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे चौंन अपराधों की ओर है। विडंबना है कि संकुचित राजनीतिक नजरिये से चीजों को देखने की आदत के कारण तृणमूल कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति की पीड़ा को भी बहुत गलत व विकृत ढंग से देखा है। राष्ट्रपति का पद आज विशेष रूप से इसलिए भी सबके लिए सम्माननीय है कि वहां पर गरीब व वंचित आदिवासी समाज की एक महिला पहुंची है। द्रोपदी मुर्मु ने गरीब व वंचित समाज की महिलाओं का उनकी गरीबी और महिला होने के नाते शोषण बहुत निकट से देखा है। इसलिए उनके शब्दों में महिलाओं के प्रति पुरुषों की वर्चस्ववादी भावना के प्रति जो पीड़ा और आक्रोश है, उसे गहराई से समझा जाना चाहिए। राष्ट्रपति के कथन को राजनीतिक चश्मे से देखना किसी प्रकार भी उचित नहीं कहा जा सकता है।

– **महेश नेनावा**, इंदौर

योगी आदित्यनाथ का आह्वान

योगी आदित्यनाथ की बात आज हर भारतीय, खासकर हिंदुओं को समझने की जरूरत है कि अगर हम एक होकर मिलजुल कर रहेंगे तो हम सब हर मुसीबत से बचकर सुरक्षित रह सकते हैं। सभी जानते हैं कि संगठन में शक्ति होती है अत: हम सबको संगठन बनाकर एकजुट होकर रहना बेहद जरूरी है। आज की परिस्थितियों में जो एकजुट नहीं है उसके खंडित होने की संभावनाएं ज्यादा है। यदि हम जातियों में बंट कर रहेंगे तो हम पर खतरा हमेशा बना रहेगा। अत: राष्ट्र में हमारी एकता से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। अगर इस राष्ट्र को बचाना है तो एकता बनाकर रखना बेहद जरूरी है। पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में भी संभवत: हिंदू इतने एकजुट व आक्रामक नहीं थे, जिसकी आवश्यकता थी। शायद इसके पीछे 2014 से पहले भारत की अधिकांश सरकारों की नीति भी थी जो विदेशों में रहने वाले हिंदुओं को भारत से जोड़ने और उनके साथ जुड़ने में शर्म का अनुभव करती थीं। पंथनिरपेक्षता की गलत और संकुचित समझ के कारण जहां देश में हिंदुओं को जातियों में बांट कर एक दूसरे के खिलाफ लड़ाया गया, वहीं विदेशों में हिंदुओं की पीड़ा और उत्पीड़न पर सरकारें मौन रहीं। अब मोदी और योगी के बाद स्थिति पूरी तरह बदली है।

– **मनमोहन राजावत**, शाजापुर

झोलाछाप डाक्टर

झोलाछाप डॉक्टरों द्वारा मरीजों का अवैध उपचार किए जाने के मामले बढ़ते जा रहे हैं जिससे मरीजों की जान को भी खतरा रहता है। यह डॉक्टर बिना किसी मेडिकल डिग्री या प्रमाणपत्र के गंभीर बीमारियों तक का इलाज कर रहे हैं। झोलाछाप डॉक्टरों के विरुद्ध मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा सख्त कार्रवाई के निर्देश के बावजूद इनकी गतिविधियां जारी है। इसका कारण यह है कि अधिकांश एमबीबीएस डाक्टर गांवों में रहना पसंद नहीं करते और शहरों में महंगे डॉक्टर से इलाज करवाने की क्षमता ग्रामीण मरीजों में नहीं है। आयुष्मान कार्ड धारक भी छोटी-मोटी बीमारियों के इलाज के लिए इन्हीं झोलाछाप डॉक्टरों पर निर्भर है। देश में बनी पहली गैर-कांग्रेस सरकार के स्वास्थ्यमंत्री स्वर्गीय राजनारायण ने गांव-गांव में थोड़े प्रशिक्षण के बाद स्वास्थ्य स्वयंसेवकों की आदर्श व्यवस्था की थी। चीन के बेयरफूट डाक्टर्स के पैटर्न वाली ऐसी व्यवस्था भारत में दूरदराज ग्रामीण लोगों के लिए लाभदायक हो सकती है। इसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, नर्सों, आशा बहनों व अन्य सेवर्गों को भी छोटी-मोटी बीमारियों के इलाज का समुचित प्रशिक्षण देने के साथ समय-समय पर अल्पकालीन कोर्सों से उनका उच्चीकरण किया जा सकता है।

– **विभूति चुपक्या**, खाचरोद

महिला आर्थिक सशक्तीकरण

पुरुषों के मुकाबले कामकाजी महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। श्रमबल के बारे में सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कुछ मामलों में कामकाजी महिलाएं पुरुषों से आगे हैं। अब कामकाजी महिलाओं की संख्या 49 प्रतिशत तक पहुंच गई है। इसी तरह वेतनभोगी पुरुषों की संख्या में कमी आई है। खासकर सेवा क्षेत्र में वेतनभोगी महिलाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यह 64.2 प्रतिशत तक पहुंच गई है। हालांकि, महिलाओं की बेरोजगारी दर भी 8.5 से बढ़कर 9 प्रतिशत हो गई है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए उनमें बेरोजगारी घटाना जरूरी है। भारत सरकार तथा राज्य सरकारों की लखपती दीदी व ड्रोन दीदी जैसी अनेक नीतियों से ग्रामीण व अर्धशुशल महिलाओं की आर्थिक सशक्तीकरण देश और समाज को बदलने की दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के साथ उनके प्रति पुरुषों की वर्चस्व वाली सोच में भी बदलाव लाना जरूरी है।

– **दत्तप्रसाद शिरोडकर**, मुंबई

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

अमर उजाला

प्रवाह

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

नई दिल्ली ■ शुक्रवार, 30 अगस्त 2024

मधुमेह और मोटापे जैसे राक्षसों को हराने के लिए जरूरी है कि हर दिन इनसे लड़ा जाए। -स्टीफन फर्स्ट

पीडब्ल्यूसी इंडिया की हाल ही में जारी रिपोर्ट भारतीय यूपीआई की कामयाबी और स्वागतयोग्य संभावनाओं की कहानी सुनाती है, जो न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था, बल्कि आम लोगों की जिंदगियों में आ रहे बदलावों को भी इंगित कर रही है।

अर्थव्यवस्था में यूपीआई

पीडब्ल्यूसी इंडिया की हाल ही में जारी रिपोर्ट का यह कहना कि अगले चार वर्षों में देश में डिजिटल लेन-देन तीन गुना बढ़ जाएगा, जिसमें यूपीआई का हिस्सा 91 फीसदी होगा, न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था, बल्कि आम नागरिकों के जीवन में आ रहे बदलावों का भी संकेत देता है। दरअसल देश में इंटरनेट की बढ़ती पहुंच और स्मार्टफोन के प्रसार ने डिजिटल लेन-देन को आम जन तक पहुंचाया है। छोटे कस्बों और गांवों में भी अब डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। डिजिटल इंडिया पहल और यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) जैसे सरल व सुलभ साधनों ने इस क्रांति को गति दी है। क्यूआर कोड का चलन इस कदर बढ़ा है कि आम सब्जी विक्रेता से लेकर मोची तक आपको डिजिटल भुगतान की सुविधा देते दिखेंगे, जिसका अर्थ है कि वे भी बैंक में अपने खाते को संचालित कर रहे हैं। जाहिर है कि यूपीआई का उपयोग वित्तीय समावेशन को भी मजबूती दे रहा है, जिससे देश के प्रत्येक नागरिक को वित्तीय प्रणाली का हिस्सा बनने का अवसर मिल रहा है। इसके अतिरिक्त देश की अर्थव्यवस्था का नकदी-मुक्त समाज की ओर अग्रसर होना न केवल पारदर्शिता को बढ़ावा देगा, बल्कि भ्रष्टाचार व काले धन के चलन को भी कम करेगा। उल्लेखनीय है कि भारत की 1.4 अरब की आबादी में, करीब 90 करोड़ बैंक खाते हैं, जो देश में यूपीआई क्रांति का आधार बन रहे हैं और जिससे प्रभावित होकर ही भूटान, नेपाल, श्रीलंका, सिंगापुर, यूएई, मॉरीशस, फ्रांस, पेरू इत्यादि देशों ने भी भारतीय यूपीआई को स्वीकारा है। हाल में रिजर्व बैंक के गवर्नर का यह कहना कि भारत यूपीआई को वैश्विक बनाने पर ध्यान दे रहा है, दर्शाता है कि देश की अर्थव्यवस्था में यूपीआई को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2024 में यूपीआई के जरिये लेन-देन 131 अरब तक पहुंचा, जबकि 2023 में यह करीब 84 अरब था।

2029 तक यूपीआई के जरिये 439 अरब लेन-देन हो जाने की उम्मीद की जा रही है। हाल ही में किसानों व छोटे उद्यमियों की सहूलियत का ध्यान रखते हुए केंद्रीय बैंक ने जल्द ही यूएलआई यानी यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस लाने की भी बात की है, जो वाकई स्वागतयोग्य है और जिससे यूपीआई के लक्ष्यों को पाने में भी मदद मिल सकेगी। डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में अब तक की उपलब्धियां निस्संदेह भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दे रही हैं, लेकिन साइबर सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता का अभाव, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच और डिजिटल भुगतान के प्रति आविश्वास जैसी समस्याएं हैं, जिनका समाधान देश के डिजिटल महाशक्ति बनने के लिए जरूरी है।

जीवन धारा

विलियम जेम्स

जीवन से घबराने की जरूरत नहीं है। हमें ऐसा मजबूत विश्वास रखना है कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, ताकि जब भी कोई कठिन समय आए, तो घबराए बिना हम मजबूत मीनार की तरह खड़े रह सकें।

जिंदगी धागों से बुना एक भव्य और सुंदर स्वेटर है

जिंदगी खुशी, दुख और अनिश्चितता के धागों से बुने हुए एक भव्य और सुंदर स्वेटर की तरह है, जो अक्सर हमें इसकी जटिलताओं से जूझने के लिए प्रेरित करती है। हमारे अस्तित्व की गहराई में आशा की एक किरण है, जो हमारे अस्तित्व के सबसे अंधेरे कोनों को भी रोशन कर सकती है। मनुष्य अपने मन के आंतरिक दृष्टिकोण को बदलकर जीवन के बाहरी पहलुओं को बदल सकता है। इसलिए हर दिन थोड़ा-बहुत व्यायाम करके अपनी आंतरिक क्षमता को बरकरार रखें। यानी, छोटे-छोटे अनावश्यक कामों में व्यवस्थित रूप से तपस्वी या वीर बनें, कुछ ऐसा करें, जिसका कोई और कारण न हो, ताकि जब कठिन समय आए, तो आप घबराए हुए न हों और परीक्षा में खरे उतरने के लिए अप्रशिक्षित न हों। ऐसा ही उस व्यक्ति के साथ होता है, जिसने प्रतिदिन खुद को ध्यान एकाग्र करने, और गैर-जरूरी चीजों के त्याग का संकल्प ले लिया है। जब उसके चारों ओर सब कुछ उगमगाता है, और जब उसके साथी भूसे की तरह फट जाते हैं, तब भी वह एक मीनार की तरह खड़ा रहता है। इसलिए जीवन से डरें नहीं। भरोसा रखें कि जीवन जीने लायक है। आपका भरोसा इस तथ्य को दृढ़ होने में मदद करेगा। अपने जीवन में बदलाव की शुरुआत अभी से कर दें। साहसी बनें। नए तथ्य पुराने नियमों को तोड़ देते हैं, फिर नई दिव्य अवधारणाएं पुराने और नए को एक साथ जोड़कर एक सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था बनाती हैं। हम जानते हैं कि बिना आग के कमरे में ठंडी सुबह बिस्तर से उठना कैसा होता है, और हमारे भीतर का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत इस कठिन परीक्षा के खिलाफ कैसे विरोध करता है। संभवतः अधिकांश लोग सुबह देर तक लेटे रहते हैं और खुद को संकल्प के लिए तैयार नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि हमें कितनी देर हो जाएगी, दिन के काम कैसे प्रभावित होंगे। हम कहते हैं, 'मुझे उठना चाहिए, यह अपमानजनक है,' आदि। लेकिन गर्म बिस्तर बहुत अच्छा लगता है, बाहर की ठंड बहुत क्रूर है, और संकल्प फीका पड़ जाता है और बार-बार खुद को स्थगित कर देता है। अब हम ऐसी परिस्थितियों में कैसे उठते हैं? अगर हम अपने अनुभव से सामान्यीकरण कर सकते हैं, तो अक्सर बिना किसी संघर्ष या निर्णय के उठ जाते हैं। हम अचानक पाते हैं कि हम उठ गए हैं। चेतना की एक भाग्यशाली चूक होती है, जिसके बाद हम गर्मी और ठंड, दोनों को भूल जाते हैं। दरअसल, प्रत्येक पीढ़ी की सबसे महान खोज यह है कि इन्सान ही एकमात्र ऐसा प्राणी है, जो अपने दृष्टिकोण में बदलाव कर अपना जीवन बदल सकता है।

संकल्प पूर्ति के तीन सूत्र

सूत्र

आप वाकई अपने जीवन को उन्नत करना चाहते हैं या उसमें कोई बदलाव लाने के लिए लालायित हैं, तो आपको सबसे पहले ये तीन काम करने होंगे। पहला काम है, आप जो संकल्प ले रहे हो, उस पर तत्काल अमल करना शुरू कर दें। दूसरा इसे पूरे मनोयोग और आकर्षक ढंग से करें और तीसरा इसे बीच में ही न छोड़ें।

छिपकर इंसुलिन लेते बच्चे और हम

चिकित्सा जगत को उस दिन का इंतजार है, जब मधुमेह के शिकार बच्चे और किशोर-किशोरियां सार्वजनिक स्थलों पर बिना किसी शर्म के इंसुलिन पंप का इस्तेमाल करेंगे। यह एलान करते हुए कि-हां, हमें टाइप वन डायबिटीज है और हम एक सामान्य जीवन जी रहे हैं।

संजय अभिज्ञान
वरिष्ठ पत्रकार

कभी फुर्सत निकालकर गूगल सर्च पर दो शब्द टाइप करें-'टाइप वन डायबिटीज' और 'सुसाइड'। सर्च रिजल्ट की जो लंबी सूची स्क्रीन पर उभरेगी, वह आपको चौंका देगी। पता लगेगा कि एक अदद बीमारी भी इन्सान को इतने अवसाद और भय से भर सकती है कि वह मौत को ही गले लगा ले। पहेली मगर यह है कि जिस बीमारी का पुख्ता इलाज दशकों पहले खोजा जा चुका, वह आज भी इस कदर डरावनी और मारक क्यों है?

बचपन में होने वाला मधुमेह रोग, जिसे टाइप वन डायबिटीज या 'टीवनडी' भी कहा जाता है, उन असंक्रामक बीमारियों की सूची में शामिल है, जो अब संक्रामक महामारियों से ज्यादा जानलेवा हो गई है। खेलने की उम्र में नीनिहाल इंसुलिन की सुइयां झेलें, यह तकलीफदेह है। मगर उससे भी त्रासद है कि ये सुइयां उन्हें घर या स्कूल में, बाथरूम में या किसी कोने में छिपकर लगानी पड़ती हैं। उन्हें यह आशंका रहती है कि कहीं कोई देख न ले। बच्चे फिर भी अपनी पीड़ा भूल जाएं, मगर मां-बाप लगातार इस अंदेशे को जीते हैं।

अमूमन क्लीनिकों में काम करने वाले कर्मचारी जिस तरह से बीमारी के बारे में बताते हैं, उससे परिवार और डर जाता है। ऊपर से, इंसुलिन की कीमत और उसे सही तापमान में रखने की चुनौती। नतीजा यह कि टीवनडी मरीजों के लिए काम करने वाली संस्थाएं आए दिन अपने कार्यालय की दहलीज पर छोड़े गए बच्चे देखती हैं। मजबूर अभिभावकों की चिट्ठियां मिलती हैं। कितने ही लोग अपने बीमार बच्चे समेत खुदकुशी कर लेते हैं, जिनमें से कुछ की ही दास्तान मीडिया तक पहुंचती है।

टीवनडी के साथ जीने की दवा बहुत पहले बनी थी। मगर इससे जुड़े कलंक भाव को मिटाने की दवा अभी तक नहीं बनी। इसी विरोधाभास पर विचार करने के लिए यूनिसेफ और टीवनडी मरीजों के लिए काम करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की एक उच्चस्तरीय बैठक पिछले पखवाड़े उदयपुर में हुई। इसमें यूनिसेफ के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय और यूनिसेफ इंडिया के शीर्ष अधिकारी, टीवनडी मरीजों के लिए कार्यरत

दुनिया की सबसे बड़ी संस्था ब्रेकथ्रू टीवनडी के प्रतिनिधि, उदयपुर राजघराने की परोपकारी संस्था- फ्रेंड्स ऑफ मेवाड़ और मरीजों की संस्थाओं-आईएमपेशेंट नेटवर्क और दक्षिण भारतीय इम्यूनोलॉजी ट्रस्ट के अधिकारी शामिल हुए। इस महत्वपूर्ण जमावड़े में तीन समस्याएं और उनके समाधान रेखांकित हुईं।

पहली समस्या है, इलाज का भारी खर्च। मधुमेह पीड़ित एक आम बच्चे के इंसुलिन, ग्लूकोमीटर, इंजेक्शन, इंसुलिन को ठीक रखने की खातिर खास तापमान पर रखने के लिए फ्रिज, उसकी बिजली और अन्य दवाओं की खरीदारी पर औसतन 3,500 रुपये प्रतिमाह का न्यूनतम खर्च आता है। इसी कारण खजन घटते जाने या थकान जैसे लक्षण होने पर भी मरीज जांच टालते रहते हैं। इसीलिए यूनिसेफ की अपील है कि देश भर में ऐसा स्वास्थ्य ढांचा विकसित किया जाए, जो सस्ता और सुलभ हो और जिससे बच्चों में जल्द से जल्द बीमारी की पहचान की जा सके। राइट टू हेल्थ की अवधारणा के तहत सरकारों को बच्चों के हित में यह खर्च वहन करना चाहिए। याद रहे, इंसुलिन की नियमित खुराक मिले, तो टाइप वन के रोगी भी सत्तर साल या उससे अधिक जीते हैं।

दूसरी समस्या है, मरीजों से भेदभाव। स्कूल-कॉलेजों में और खासतौर पर परीक्षा भवनों में मधुमेह पीड़ित छात्र-छात्राओं को भोजन या इंसुलिन लेने के अवकाश नहीं दिए जाते। पूरे देश के शिक्षा संस्थानों में टीवनडी ग्रस्त बच्चों के लिए ऐसी रियायतें अनिवार्य बनाना ही इसका समाधान है। तीसरी समस्या है-बीमारी के मानसिक और सामाजिक कुप्रभाव-वह कलंक भाव, जो शारीरिक कुप्रभावों से भी ज्यादा मारक है। इसका समाधान है, अस्पतालों में टाइप वन मरीजों से बातचीत में सही आश्वस्तकारी भाषा का प्रयोग। इसके लिए 'जीवन भर का अभिशाप', 'इंसुलिन के मोहताज', 'जटिल लाइलाज बीमारी' जैसे जुमलों से परहेज करना होगा। साथ ही, ऐसी हस्तियों और मिसालों पर जोर देना होगा, जिन्होंने बचपन के मधुमेह को समाज के सामने कबूला और अनुशासित इलाज से सामान्य जीवन जीकर दिखाया।

टीवनडी के कलंक भाव से यह जंग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लड़ी जा रही है। अच्छी बात है कि इस वैश्विक जंग में दो भारतीय रोल मॉडल बनकर उभर रहे हैं। एक है, उदयपुर राजघराने की प्रिंसेज पद्मजा कुमारी परमार, जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर घोषणा की कि वह बचपन से टाइप वन डायबिटीज के साथ जी रही हैं। साथ ही उन्होंने असहाय मरीजों के लिए अंतरराष्ट्रीय परोपकारी संगठन, फ्रेंड्स ऑफ मेवाड़ की स्थापना की। इसीलिए प्रतिष्ठित संस्था, ब्रेकथ्रू टीवनडी ने उन्हें अपना ब्रांड एंबेसडर बनाया। दूसरे रोल मॉडल हैं, कोलकाता के सुविख्यात एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉ. सुजॉय घोष, जो टीवनडी संस्थाओं के बीच पोस्टरबॉय बनकर उभरे हैं। वह लंबे समय से टीवनडीग्रस्त बच्चों के हित में नीति परिवर्तन के लिए प्रयासरत हैं। उनके जैसे चिकित्सक-अधिकारियों की बदौलत ही हाल में पश्चिम बंगाल के जिला अस्पतालों में टाइप वन डायबिटीज मरीजों के लिए मुफ्त क्लिनिक शुरू हुए हैं।

विज्ञान पत्रिका *लांसेट* के मुताबिक, 2021 में भारत में लगभग साढ़े आठ लाख लोग टाइप वन डायबिटीज के शिकार थे। टाइप 2 के आंकड़े मिलाकर देखें, तो मधुमेह रोगियों का आंकड़ा कुल आबादी का दस फीसदी यानी लगभग 15 करोड़ के करीब है। यूनिसेफ के मुताबिक, टाइप वन डायबिटीज उन गैर-संचारी बीमारियों में से एक है, जो हर साल दुनिया में एक करोड़ 70 लाख लोगों की जिंदगी लील जाती है। हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कैंसर, डायबिटीज और अस्थमा इनमें प्रमुख हैं। भारत में हर साल होने वाली कुल मौतों में से 66 प्रतिशत इन्हीं गैर-संचारी रोगों का परिणाम हैं और इनमें भी 22 फीसदी मौतें कम उम्र के मरीजों की जान ले रही हैं। भीड़ भरे शहरों का प्रदूषण, व्यायाम वंचित गलत जीवनशैली, नौकरी-कारोबार के तनाव और गरीबी-कुपोषण के आघात-इनके प्रमुख कारण हैं। अब यह धारणा गलत साबित हो चुकी है कि बीपी-शुगर अमीरों के रोग हैं। भारत में भी गरीब आबादी ही इनकी मार ज्यादा झेल रही है। पैसे और जागरूकता, दोनों के अभाव में ये जांच तक नहीं कराते। दुखद ही है कि भारत में टीवनडी से मरने वाले हर छह में से एक व्यक्ति को अंत तक पता नहीं होता कि उसे बीमारी क्या है।

edit@amarujala.com

दूसरा पहलू

हाल में दिखंगत हुए समुद्री जीवविज्ञानी निकोलस ने पानी के साथ हमारी परस्पर निर्भरता की पहचान की थी।

किताब जो समुद्र होने का अर्थ समझाती है

प्राचीन गीत 'द सॉन्ग ऑफ अमेरगिन' की पंक्तियों का शुरुआती अनुवाद इस प्रकार है, 'मैं समुद्र पर हवा हूं, मैं उफनती लहर हूं, मैं समुद्र की दहाड़ हूं।' माना जाता है कि यह आयरिश भाषा की पहली कविता है। यह याद दिलाती है कि कैसे समुद्र ने हमारा निर्माण किया व आकार दिया। अपनी समुद्री जीवविज्ञानी वालेस जे. निकोल्स, जिनका हाल में 56 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ने इस भावना को मूर्त रूप दिया था।

ईस्की ब्रिटन

उनके दोस्त और सहकर्मी उन्हें प्यार से 'जे' कहकर बुलाते थे। जे ने समुद्र के जीर्णोद्धार में रुचि रखने के कारण पानी के साथ हमारी परस्पर निर्भरता को पहचाना था। वह जानते थे कि समुद्र के संरक्षण के लिए हमें बेहतर ढंग से इसके महत्व को समझने की जरूरत है। विशेष रूप से यह हमारे मनोवैज्ञानिक कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 1967 में न्यूयॉर्क में पैदा हुए जे ने पीएचडी करने से पहले 1990 के दशक में समुद्री जीवविज्ञान का अध्ययन किया था। एक बार तो उन्होंने और उनके साथियों ने कैलिफोर्निया से जापान तक तैरते हुए लॉगरहेड कछुए एडेलिटा को उपग्रह के माध्यम से ट्रैक किया था। यह पहला समुद्री जीव था, जिसे पूरे महासागर बेसिन को पार करते हुए रिकॉर्ड किया गया था।

उन्होंने अंतरराष्ट्रीय तटीय बहाली चैरिटी 'वाइल्डकोस्ट' की स्थापना की। जे को वैज्ञानिक उपलब्धियों से ज्यादा, उनकी उदारता की वजह से लोग अधिक प्यार करते थे। उनकी सबसे ज्यादा बिकने वाली 'ब्लू माइंड' पुस्तक में उन्होंने वर्षों के शोध और अंतर्दृष्टि को एक साथ पिरोया। उन्होंने बताया कि कैसे पानी में या उसके पास रहने से हमारी जागरूकता, रचनात्मकता और स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। यह पुस्तक हमारे मनोवैज्ञानिक कल्याण पर पड़ने वाले पानी के प्रभाव को समझाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। पानी से उपचार की विधि सदियों से हर प्राचीन परंपरा में विद्यमान थी। 'ब्लू माइंड' ने उसी चेतना को जागृत किया है, जिसे कभी पश्चिमी विज्ञान ने काफी हद तक नजर अंदाज किया था। जे की खोज ने 'मुझे उस चीज को सहजता से समझने की भाषा प्रदान की, जिसे मैंने अपने पूरे जीवन में महसूस किया यानी पानी से उपचार की शक्ति।' खेद जे के सम्मान में हर किसी को पानी से जुड़ने और उसकी रक्षा करने का एक तरीका मिल सकता है। जैसा कि वह लोगों से विदाई लेते वक्त हमेशा कहते थे, 'मैं आपके लिए पानी की कामना करता हूं।' *(द कन्वर्सेशन से)*

वालेस जे. निकोल्स जानते थे कि समुद्र के संरक्षण के लिए हमें बेहतर ढंग से इसके महत्व को समझने की जरूरत है।

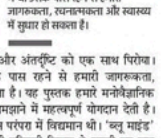

'ब्लू माइंड' पुस्तक में जे ने वर्षों के शोध और अंतर्दृष्टि को एक साथ पिरोया।

आंकड़े

इंटरनेट उपयोगकर्ता

बीते कुछ वर्षों से प्रत्येक देश में इंटरनेट उपयोगकर्ता बढ़ते जा रहे हैं। भारत में ही अब आधी आबादी इंटरनेट का उपयोग कर रही है।

दक्षिण कोरिया	99%
मलयेशिया	94%
सिंगापुर	94%
जापान	88%
भारत	56%

आंकड़े वर्ष 2023 तक इंटरनेट उपयोग करने वाली आबादी के।

चेत : Pew Research

भीम अपने बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर का बहुत सम्मान करते थे। मान्यता है कि भीम की भ्रातृभक्ति से खुश होकर ही भगवान श्रीकृष्ण ने हर बार उनकी मदद की।

पाप नाशक है भीम का कीर्तन

माता कुंती के गर्भ से वायु के अंश से महापराक्रमी भीम का जन्म हुआ। बताया जाता है कि भीम पैदा होते ही माता की गोद से एक चट्टान पर गिर पड़े, जिससे चट्टान टूट गई, लेकिन उनको चोट नहीं लगी। भीम पांडवों में सबसे बलशाली थे, लेकिन वह अपने बड़े भाई युधिष्ठिर का बहुत सम्मान करते थे। युधिष्ठिर जब जुए में द्रौपदी को भी हार गए, तब बाहर आकर भीम ने क्रोध वश अर्जुन से कहा, 'मैं आज बड़े भैया के दोनों हाथ जला दूंगा।' अर्जुन ने जब उन्हें भ्रातृभक्ति का स्मरण कराया, तो वह काफी लज्जित हुए और धर्मराज युधिष्ठिर से माफी मांगी।

भीम ने अकेले ही 100 कौरवों को मारा था। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव धृतराष्ट्र से मिलने पहुंचे। धृतराष्ट्र ने भीम से कहा, 'आओ मेरे गले लग जाओ।' लेकिन भगवान श्रीकृष्ण धृतराष्ट्र की मंशा को जानते थे। इसलिए भीम के शरीर के आकार का लोहे का पुतला बनवाया, जिससे भीम के प्राण बच गए। मान्यता है कि भीम के अंदर बड़े भाई के प्रति जो आदर भाव था, उसी की वजह से भगवान भी उनसे खूब स्नेह करते थे। तभी तो जरासंध और दुर्योधन के वध का तरीका बताना हो या फिर धृतराष्ट्र से रखा करना, हर बार भगवान ने भीम की सहायता की। इसलिए कहते हैं कि 'पापं प्रणश्यति वृकोदरकीर्तनेन' यानी भीम का कीर्तन करने से पापों का नाश होता है।

अंतर्यात्रा
संकलित

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 14 अगस्त 1958

असम और पूर्वी पाकिस्तान की सीमा बंद, सेनाओं का जमावड़ा

असम-पूर्व पाकिस्तान सीमा बंद-पाक सेना ओं का जमाव
सिलहट में हिंदू बों के घर व मिलकियतें जलाये जाने के समाचार

पूर्वी पाकिस्तान सरकार ने असम व पूर्वी पाकिस्तान सीमा को कल आधी रात से बंद कर दिया है और त्रिपुरा की सीमा पर टैंक, तोपों व भारी हथियारों का जमावड़ा शुरू कर दिया है। सिल्हट में हिंदू नेताओं को नजरबंद किया गया है।

खेत अब कम क्यों दिखने लगे हैं

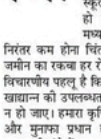

सरकारें किसानों के प्रति उदासीन हैं। कृषि योग्य जमीन पर अतिक्रमण जारी है। यह भविष्य में खाद्यान्न संकट को जन्म देगा।

सुधीर विद्यार्थी — मुद्दा

कि सी भी सड़क या राजमार्ग के दोनों तरफ अब खेत कम दिखाई पड़ते हैं। यहां बनतीं नई इमारतों, कॉलोनियों, स्कूल-कालेजों, प्रतिष्ठानों के तेजी से हो रहे अनियोजित नवनिर्माण के मध्य लहलहाती फसलों के दृश्यों का निरंतर कम होना चिंता का विषय है। कृषि के लिए जमीन का रकबा हर रोज घटता जा रहा है। ऐसे में यह विचारणीय पहलू है कि बढ़ती आबादी के लिए आखिर खाद्यान्न की उपलब्धता का संकट भविष्य में विकराल न हो जाए। हमारा कृषि प्रधान देश धीरे-धीरे व्यवसाय और मुनाफा प्रधान होता जा रहा है। खेती पहले लाभकारी धंधे में शुमार नहीं थी। वह गांवों में रहने वालों के लिए जीविका और जीवन का साधन थी, जिससे नगरों और महानगरों का भी भरण-पोषण होता था।

धीरे-धीरे कृषि लाभ के बजाय घाटे के धंधे में तब्दील होती चली गई। इसके लिए सरकार की नीतियां अधिक जिम्मेदार हैं, जिनके चलते फसलों के बीज, रासायनिक उर्वरकों और कृषि यंत्रों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई, जबकि पैदावार के लागत मूल्य को हासिल करना भी किसान के लिए मुश्किल होता चला गया। उसे सरकार की ओर से निर्धारित फसल का न्यूनतम मूल्य भी न मिलना किसी मारक प्रहार से कम नहीं। इसके चलते किसान को घर-परिवार चलाना, बच्चों की शिक्षा और उनके शादी-विवाह का प्रबंध, अपनी अल्प चिकित्सकीय जरूरतों के साथ न्यूनतम अत्यावश्यक सुविधाओं को हासिल करना हर रोज कठिनतर होता चला गया। रोजगार के लिए गांवों से पलायन के चलते 'उत्तम खेती' की अवधारणा समय के साथ अर्थहीन होती गई। खेती का बंटवारा होने के कारण छोटे और कमोबेश मध्यम किसान अपनी जमीन बेचने के लिए विवश हुए। इससे उनके सम्मुख रोजी-रोटी की समस्या आ खड़ी हुई। ऐसे में मजदूर बनते चले जाने की उनकी विवशता को हुक्मरानों ने कभी महसूस नहीं किया। सरकारें इस ओर से निरंतर मुंह फेर लेती रहीं कि आखिर तेजी से भूमिहीन होते जा रहे किसानों को गांवों में कैसे रोका और काम दिया जाए? 'मनरेगा' के अंतर्गत रोजगार दिए जाने का कुछ लाभ हुआ, लेकिन ऐसी योजना की भी एक सीमा है।

एक समय था, जब गांव आत्मनिर्भर इकाई हुआ करते थे। वहां जरूरत की हर चीज पैदा की जाती थी। गांव तब कस्बे या शहर के मुखापेक्षी नहीं थे। गांव के मजदूर वर्ग को वहीं काम मिल जाता था। जब तक कृषि कार्य में मशीनों का इस कदर प्रयोग नहीं हुआ था, मनुष्य और पशुओं के साहचर्य का सौहार्दपूर्ण खातावरण ग्रामीण जीवन को अनोखा सौंदर्य और विशिष्टता प्रदान करता था, लेकिन सड़कों और मशीनों की पहुंच ने गांवों से उनकी सांसों की आवाजाही छीन ली। हमारा ऐसा मानना कोई प्रगतिविरोधी नजरिया नहीं है, पर आज छोटी और मध्यम जोत के किसानों के सम्मुख अपने जीवन को चलाए रखने का जो संकट विद्यमान है, उस पर सोचने-विचारने के लिए आखिर कौन आगे आएगा? राजनीतिक दल इस ओर उदासीन हैं। उन्होंने कृषक वर्ग को वोट के लिए लुभावनी घोषणाओं की गुंजलक में फंसा रखा है। किसानों का अब अपना कोई मोर्चा नहीं रहा। विभिन्न राजनीतिक दलों ने उन्हें स्वार्थ और जाति के खांचों में फंसा रखा है। कृषि भूमि के घटते क्षेत्रफल को बचाने और उसे संरक्षित रखने की चिंता इन दिनों किसी को नहीं है। किसानों के तथाकथित मसीहाओं के पास भी इस मामले में कोई दृष्टिसंपन्न परिकल्पना का अभाव है। एक समय ग्रामवासी खेत को अपनी मां मानते थे। वे उसे बेचने की सोच भी नहीं सकते थे, जबकि किसान की नई पीढ़ी को अपनी मिट्टी से वैसा लगाव अब नहीं रहा। वह उसे धन के बदले बेचने में तनिक भी संकोच नहीं करती।

बाईपास बनने पर किसानों की कृषि भूमि को सरकार जबरन हथिया लेती है और जमीन के मालिक किसानों को उसका उचित मुआवजा भी नहीं मिलता। नई कॉलोनियां खड़ी करने वाले व्यवसायियों को मिली-भगत के चलते पहले ही इस बात का पता होता है कि किस जगह नई सड़क निर्माण के लिए जमीन चिन्हित होनी है। ऐसे में बड़े-बड़े कॉलोनाइजर षड्यंत्रपूर्वक सर्वे होने से पहले ही किसानों को जमीन के दाम बढ़ाने का लालच देकर इकट्ठा सौदा कर लेते हैं। सड़कों और राजमार्गों के किनारे आधुनिकतम ढाबों का निर्माण मुझे कृषि जमीन का उपहास उड़ाते प्रतीत होते हैं। एक्सप्रेस-वे की जमीनें किसानों की हैं, लेकिन उन पर बड़ी और महंगी कारों के काफिले दौड़ते हैं, उन्हीं के लिए वहां सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जबकि किसानों के लिए उन राजमार्गों पर 'प्रवेश वर्जित' है। यदि कृषि योग्य जमीन पर अतिक्रमण और लूट का सिलसिला इसी तरह तेजी से चलता रहेगा, तो यह संकट भविष्य के लिए बड़ा खतरा है, जिस पर गहन विमर्श की जरूरत हमारे आज के एजेंडे में होनी चाहिए। लेकिन हम किस तरह मुतमइन हों कि इस दिशा में कोई पहल हो सकेगी।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 167

औद्योगिक पार्कों की राह में चुनौतियां

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस सप्ताह मंजूर की गई सरकार की औद्योगिक पार्क नीति, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) अधिनियम 2005 के बाद कारोबार के अनुकूल क्षेत्र तैयार करने की सबसे महत्त्वाकांक्षी पहल है। 28,600 करोड़ रुपये की लागत से 12 ऐसे एन्क्लेव विकसित करने की योजना है जिसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने औद्योगिक पार्कों के 'स्वर्णिम चतुर्भुज' का नाम दिया है। याद रहे कि यह अटल बिहारी वाजपेयी की सफल सड़क निर्माण परियोजना का नाम था। योजना के मुताबिक राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के साथ मिलकर एकीकृत स्मार्ट औद्योगिक शहर बसाए जाने हैं जिनमें आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्र होंगे। इसके जरिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य है। राज्यों का योगदान जमीन के रूप में होगा और केंद्र सरकार इक्विटी या डेट मुहैया कराएगी। कुछ औद्योगिक टाउनशिप अन्य देशों के साथ मिलकर विकसित की जाएंगी जिन्होंने ऐसी व्यवस्था में अभिरुचि दिखाई है। इस विषय में सरकार की मंशा कहीं से गड़बड़ नहीं लग रही।

बहरहाल एक सवाल यह है कि इसका क्रियान्वयन कैसे होगा? ऐसा इसलिए क्योंकि अतीत में औद्योगिक गतिविधियों को देश की कारोबारी सुगमता क्षेत्र की मानक अकुशलताओं से अलग-थलग रखने के प्रयासों को बहुत सीमित सफलता मिली है। सरकारी आंकड़े बताते हैं देश में करीब 4,420 औद्योगिक पार्क और 270 एसईजेड हैं। इनमें से अधिकांश को निवेश बढ़ाने में कोई उल्लेखनीय कामयाबी नहीं मिली है। एसईजेड नीति में भी इसी प्रकार इलाके चिह्नित किए गए थे जहां कर राहत प्रदान करके चीन की शैली में निर्यात क्षेत्र विकसित किए गए। शुरुआती रुचि के बाद जब कर रियायत समाप्त हुई तो ये क्षेत्र अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे और इन्हें लेकर उत्साह समाप्त हो गया। देश के कुल निर्यात में एसईजेड की हिस्सेदारी केवल एक तिहाई रह गई। विनिर्माण में निवेश आकर्षित करने की सरकार की नीतिगत मंशा सफल नहीं हुई। एसईजेड में आए निवेश का करीब 60 फीसदी आईटी और आईटीईएस में आया।

उसके बाद आया डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज ऐंड सर्विस हब्स (देश), विधेयक 2023। इसके माध्यम से एसईजेड कानून की कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया। इस विधेयक की स्थिति अस्पष्ट है। खबरों के अनुसार तो शायद इसे खारिज भी कर दिया गया है। ताजातरीन नीति में देश में निवेश से जुड़ी शाश्वत बाधाओं को दूर करने का प्रयास दिखता है। उदाहरण के लिए भूमि अधिग्रहण हमेशा से एक चुनौती रहा है। यहां तक कि एसईजेड भी निजी क्षेत्र के अचल संपत्ति कारोबार में बदलकर रह गए। औद्योगिक पार्कों में वे जमीनें शामिल होंगी जो सरकार द्वारा पहले ही अधिग्रहीत हैं और जिनके लिए पर्यावरण मंजूरी मिल चुकी है। दूसरा, एकल खिड़की मंजूरी के लिए स्पेशल परपज व्हीकल बनाने का प्रस्ताव भी है। तीसरा, पार्कों की लोकेशन को समर्पित माल ढुलाई गलियारे से लगे औद्योगिक गलियारे से जोड़ा गया है जिससे लॉजिस्टिक्स की एक अहम समस्या दूर हो सके। इनमें से पांच अमृतसर-कोलकाता बेल्ट पर, दो दिल्ली-मुंबई बेल्ट पर और पांच दक्षिणी एवं मध्य मार्गों पर स्थित हैं।

इस लिहाज से देखें तो कई व्यापक मुद्दे हैं जिन्हें हल करना होगा, तभी हमारे पार्क चीन जैसा प्रभाव उत्पन्न कर सकेंगे। उनमें से एक है आकार ताकि विनिर्माताओं के पास वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं जैसी पहुंच हो सके और वे सही मायनों में प्रतिस्पर्धी बन सकें। यह एक चुनौती हो सकती है। देश में एसईजेड का औसत आकार 0.25 वर्ग किमी से 14 वर्ग किमी तक का है। इसके विपरीत चीन के सबसे पुराने और बड़े एसईजेड में से एक शेनझेन का आकार 316 वर्ग किमी का है। इन शहरों के इर्दगिर्द जीवंत सामाजिक ढांचे की उपलब्धता भी अहम है। गुरुग्राम और बेंगलूरु इस मामले में मिसाल हैं क्योंकि उन्होंने नए दौर के श्रमिकों के समायोजन के लिए ढांचा विकसित किया है। यहां तक कि केरल जैसी अंकुश वाली मंदिरा नीति या बिहार जैसी पूर्ण शराबबंदी भी पार्कों में विदेशी निवेश के निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं। नवीनतम नीति यकीनन निवेश जुटाने की एक नई कोशिश है। देखना होगा कि इसे कामयाबी मिलती है या नहीं।

कारोबार में अनुपालन नहीं विश्वास बहाली बेहतर

नागरिक एवं कारोबारी जगत पर सरकार का विश्वास कम होने से परिणाम के बजाय शर्तों के अनुपालन पर जोर दिया जाने लगता है। बता रहे हैं अजय कुमार

कोई समाज कितना विकसित है उसका पता इस बात से चलता है कि सरकार अपने नागरिकों, कारोबार और संस्थाओं में कितना भरोसा करती है। यह भरोसा या उसकी कमी सरकार के तंत्र और प्रक्रियाओं में भी दिखाई देती है। विकसित देशों की सरकारों के भीतर विकासशील देशों की तुलना में विश्वास का स्तर प्रायः अधिक दिखता है। किंतु इस बात का अध्ययन यदा-कदा ही किया जाता है।

किसी भी कागजी कामकाज के लिए दस्तावेजों का सत्यापन अनिवार्य किया जाना विश्वास की इसी कमी की ओर इशारा करता है। कागजों से काम करने वाले किसी भी अफसरशाही तंत्र में सत्यापन की यह अनिवार्यता खर्च और ताम्झाम दोनों बढ़ा देती है। छोटे और गरीब वर्ग के लिए यह पूरी प्रक्रिया खास तौर पर जटिल हो जाती है। सरकार और जनता सहित विभिन्न समूहों के बीच अविश्वास का दूसरा उदाहरण तब सामने आता है जब कोई आवेदन करने पर अक्सर अनावश्यक जानकारी मांगी जाती है। यह जानकारी वही मानकर मांगी जाती है कि आवेदन करने वाला कुछ न कुछ छिपा रहा होगा। विभिन्न स्तरों पर सख्त निगरानी से यह भी लगता है कि कर्मचारियों की ईमानदारी और उनकी कुशलता पर संदेह या अविश्वास है। अपेक्षित परिणामों पर अधिक ध्यान देने के बजाय प्रक्रिया पर जोर इस पूर्वग्रह का संकेत है कि कोई व्यक्ति बिना सख्त निर्देश और निगरानी के पूरी ईमानदारी और नैतिकता के साथ काम नहीं कर सकता।

विश्वास स्वस्थ परंपरा ही नहीं है बल्कि इसके पीछे आर्थिक तर्क भी काम करता है। यहां हर किसी को नैतिक रूप से खरा मानने की बात नहीं है बल्कि यह समझने और स्वीकार करने की बात है कि पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने पर आने वाला खर्च कुछ उल्लेखनीय की तुलना में अधिक है। विश्वास से क्षमता बढ़ती है, नियामकीय दबाव कम होता है और सामाजिक स्तर पर परिस्थितियां सबल होती हैं। विश्वास पर आधारित तंत्र में कागजी ताम्झाम, निगरानी के विभिन्न स्तर और लालफीताशाही कम हो जाती है, जिससे प्रशासनिक व्यय भी कम हो सकता है। इससे सरकार को वृद्धि को गति देने तथा नवाचार में निवेश करने के अधिक अवसर मिलेंगे। भरोसा दिखाया जाए तो निष्पक्ष तथा पारदर्शी तंत्र के जरिये लोग खुद ही अनुपालन करते हैं, सोच समझकर जोखिम लेते हैं, नवाचार बढ़ता है और नियम-कायदों का पालन किया जाता है।

अंग्रेजी हुकूमत के कई तौर-तरीके अभी तक चले आ रहे हैं। उनमें एक था प्रशासनिक और प्रशासन तंत्र में अविश्वास की भावना। अंग्रेजी हुकूमत स्थानीय विरोध को दबाने और अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए सबको संदेह की निगाह से देखती थी और उन पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए नए हथकंडे अपनाती थी। यह अविश्वास उनके शासन, उनकी कार्य प्रणाली में भी दिखता था, जैसे राजपत्रित अधिकारी (जो अक्सर अंग्रेज होते थे) से सत्यापन की शर्त। आजादी के बाद भी भारत के कानून एवं प्रक्रियाएं अंग्रेजी तंत्र पर ही आधारित रहे और अविश्वास की मानसिकता हर स्तर पर बढ़ती गई।

दो शताब्दियों की अंग्रेजी हुकूमत के दौरान हम स्वयं अविश्वास के आदी हो चुके थे, जो नए निजाम में और भी बढ़ता गया। नतीजतन पेचीदा नियामकीय व्यवस्था, कागजी औपचारिकताओं का झमेला और कई स्तरों पर नजर रखने का सिलसिला शुरू हो गया। इनमें आंतरिक एवं बाहरी ऑडिट, निगरानी प्रकोष्ठ, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, संसदीय समितियां, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो, लोकपाल, लोकायुक्त, न्यायिक इकाइयां, क्षेत्रवार नियामक, सूचना का अधिकार कानून और न जाने क्या क्या शामिल है। इनका उद्देश्य जवाबदेही पक्की करना है मगर असल में ये कर्मचारियों पर और निगरानी तंत्र पर भी गहरे अविश्वास की तरफ इशारा करते हैं। इसी अविश्वास ने परिणामों के बजाय अनावश्यक औचारिकताओं को प्राथमिकता देने की सोच गहरी कर दी है।

भरोसे के साथ प्रशासन की दिशा में आमूल कदम 1992 में उठाया गया, जब संविधान में हुए 73वें और 74वां संशोधन हुए। इन संशोधनों के बाद सत्ता के विकेंद्रीकरण का रास्ता साफ हो गया और पंचायत एवं नगर निकायों जैसी स्थानीय संस्थाओं को अधिकार दिए गए। विकेंद्रीकरण दिखाता है कि संसाधन संभालने और स्वतंत्र फैसले लेने की स्थानीय अधिकारियों की क्षमता में विश्वास है। मगर स्थानीय निकायों में केंद्र और राज्य की तरह अविश्वास की सोच हावी रही।

नरेंद्र मोदी के शासन में सरकार ने नागरिकों में विश्वास बहाल करने के लिए कई महत्त्वपूर्ण सुधार शुरू किए। शपथ पत्र की जगह स्व-अभिप्रमाणन की शुरुआत हुई और राजपत्रित अधिकारियों से सत्यापन की जरूरत खत्म कर दी गई। आवेदन एक पृष्ठ में सिमट गया और फालतू प्रश्नों से निजात मिल गई। पिछले कुछ वर्षों में 3,400 प्रावधान गैर-आपराधिक हो गए और 39,000 से अधिक अनुपालनों की जरूरत खत्म कर दी गई। ये बदलाव प्रगतिवादी लग रहे हैं मगर कुछ समस्याएं अभी बनी हुई हैं, जिनके लिए मौजूदा सुधार जारी रखने तथा कानूनी स्तर पर उपाय करने की जरूरत है।

नागरिकों का भरोसा जीतने में प्रगति के बाद भी सरकार और कारोबार के बीच विश्वास बहाल करना लगातार चुनौती बनी हुई है। कुछ बड़े कारोबारों में बड़े फर्जीवाड़े ने अविश्वास और बढ़ा दिया है, जिसके नतीजे में पेचीदा और भारी भरकम नियामकीय तंत्र सामने आया है। लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) सहित भारतीय कारोबारों को कंपनी अधिनियम 2013, आयकर अधिनियम 1961, भारतीय रिजर्व बैंक दिशानिर्देश, बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1999, सेबी अधिनियम 1992, प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम 2002, वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, कर्मचारी भविष्य निधि कोष एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952, बोनस भुगतान अधिनियम 1972, फैक्ट्री कानून 1948, ठेका अनुबंध अधिनियम 1970, बाल श्रम अधिनियम 1986, परिपक्वता लाभ अधिनियम 1961, ग्रैच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 और कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ यौन अत्याचार रोकथाम अधिनियम 2013 सहित विभिन्न कानूनों के अंतर्गत अनुपालन संबंधी शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। भारत के नियामकीय ढांचे में 1,563 कानून हैं और इनके अंतर्गत 69,233 शर्तों का पालन करना पड़ता है। इनमें नई शर्तें जुड़ती रहती हैं।

नागरिकों के साथ आपसी विश्वास को बढ़ावा देने की तुलना में कारोबार के साथ विश्वास बहाल करना अधिक मुश्किल काम है। इसके कई कारण हैं। भ्रष्टाचार होने की आशंका से विश्वास बहाली और मुश्किल होती जाती है। दूसरा कारण यह है कि कारोबार में कई पक्ष शामिल होते हैं जिनकी आवश्यकताएं अलग-अलग होती हैं। इससे समान स्तर पर विश्वास बहाल करना और मुश्किल हो जाता है। तीसरी बात, सभी शर्तें नहीं हटाई जा सकतीं। कुछ नियामकीय शर्तें समाज कल्याण के लिए जरूरी होती हैं और इस परिप्रेक्ष्य में महत्त्वपूर्ण और कुछ कम जरूरी शर्तों के बीच अंतर करने की जरूरत महसूस होने लगी है।

सरकार और कारोबार के बीच अविश्वास दूर करने के लिए पारदर्शिता बुनियादी शर्त है। तकनीक आधारित सरकारी तंत्र की तरफ कदम बढ़ाने से विश्वास बहाली की प्रक्रिया में तेजी आ सकती है। डिजिटल लेन-देन से ऑडिट आसान हो जाता है जिससे अनैतिक व्यवहारों पर रोक लगती है और कदाचार तुरंत पकड़ में आता है। इससे लंबी नियामकीय प्रक्रिया की जरूरत समाप्त हो जाती है। इसके अलावा विश्वास आधारित दृष्टिकोण तैयार करने के लिए अनुपालन से जुड़ी जरूरतों की व्यापक समीक्षा जरूरी है। यह समीक्षा जरूरी और गैर-जरूरी आवश्यकताओं में अंतर की पहचान करने, स्व-अभिप्रमाणन को बढ़ावा देने, प्रक्रिया सरल करने और डिजिटलीकरण का लाभ उठाने पर केंद्रित होनी चाहिए। निरीक्षण और तीसरे पक्ष से प्रमाणन (थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन) की शर्तें, जहां भी संभव हो, समाप्त की जानी चाहिए। गैर-जरूरी और अस्पष्ट शर्तें दूर की जानी चाहिए और जो सूचनाएं पहले से सरकारी एजेंसियों के पास मौजूद हैं वे दोबारा नहीं मांगी जानी चाहिए। आर्टिफिशल इंटेलिजेंस की मदद से ऑनलाइन सुविधा शुरू करने से कारोबार समुदाय स्वयं जरूरी शर्तों का अनुपालन कर सकते हैं। भारत ने विश्वास आधारित सरकारी तंत्र तैयार करने में काफी प्रगति की है, विशेषकर नागरिकों के साथ विश्वास बहाली की प्रक्रिया मजबूत हुई है परंतु कारोबार के साथ भी इसे बढ़ावा देने का समय आ गया है।

(लेखक आईआईटी कानपुर में अतिथि प्राध्यापक हैं और रक्षा सचिव रह चुके हैं)

चुनाव में क्या नीतियां मायने रखती हैं?

वर्ष 2024 को परिभाषित करने वाले राष्ट्रीय चुनावों का अंतिम चरण तेजी से निकट आ रहा है। चुनावों में रुचि रखने वालों के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण वर्ष है। अमेरिकी नागरिकों को भी जल्द ही अपनी नई सरकार चुननी है। अब्राहम लिंकन भले ही रिपब्लिकन थे, लेकिन इस समय 'लोगों के लिए' नारे के साथ डेमोक्रेट उनके चोले में नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल बनता है कि क्या चुनाव नीतियों पर लड़े जा रहे हैं?

डेमोक्रेटिक पार्टी को हालिया ओपिनियन पोल्स में बढ़त मिली है भले ही वह जीतने के लिए पर्याप्त नहीं हो। निवर्तमान बुजुर्ग राष्ट्रपति की जगह युवा उप राष्ट्रपति को उम्मीदवार बनाना पार्टी की संभावनाओं में पर्याप्त इजाफा करने वाला माना गया। आंकड़े बताते हैं कि कमला हैरिस के अभियान में दानदाताओं की माध्य आयु 56 वर्ष है जबकि जो बाइडन के लिए यह आंकड़ा 66 वर्ष था।

यह तब हुआ जबकि नीतियों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। आखिरकार उपराष्ट्रपति स्वयं को राष्ट्रपति की नीतियों से अलग तो बता नहीं सकतीं। कुछ हद तक हैरिस की बातें बाइडन से अलग जरूर हैं। उदाहरण के लिए पश्चिम एशिया में शांति की बात। उन्होंने इजरायल के बचाव पर भी ध्यान दिया और फिलिस्तीनियों के अधिकारों की भी बात की। उनके अभियान को व्यापक नीतिगत पहल के मोर्चे पर शिथिल बताकर जो आलोचना की जा रही है वह भी उचित प्रतीत होती है। परंतु माहौल बन चुका है तो नीतिगत प्रस्ताव की कोई अहमियत बचती भी है? शायद कुछ खास हालात में ऐसा हो।

उदाहरण के लिए वे आपको नकारात्मक दर्शा सकते हैं। पिछले हफ्ते डेमोक्रेटिक नैशनल कन्वेंशन में एक के बाद एक वक्ताओं ने उन योजनाओं और पहलों का जिक्र किया, जिन्हें वॉशिंगटन डीसी के दक्षिणपंथी थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन ने रेखांकित किया था। उन्होंने इसे 'प्रोजेक्ट 2025' नाम के प्रकाशन में सामने रखा था। इसके तहत ऐसी नीतियां पेश की गईं, जिन्हें डॉनल्ड ट्रंप के संभावित दूसरे प्रशासन में तत्काल लागू किया जा सकता है। ट्रंप ने खुद को इससे अलग कर लिया है मगर रिपोर्ट लिखने वालों का ट्रंप का प्रचार करने वालों के साथ करीबी रिश्ता देखते हुए यह इनकार बहुत मायने नहीं रखता। ट्रंप के लिए यह हर तरह से गड़बड़ है। एक ऐसी व्यक्ति जो आमतौर पर नीतिगत ब्योरों में नहीं पड़ता है या बड़ी किताबें नहीं पढ़ता है, उसे 920 पन्नों के नीतिगत दस्तावेज से बचाना पड़ रहा है। उन्हें 2016 में बिना किसी नीतिगत ब्योरे के जीत मिली थी। वह अब भी ऐसे ब्योरों में जाने से बचना चाहेंगे। इसके बजाय उनके अभियान को गर्भपात और शिक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान देना होगा, जिन्हें वह अनसुलझा छोड़ना चाहेंगे। डेमोक्रेट राजनेता पीट बटीगीग ने कहा कि वर्ष का सबसे बड़ा स्कैंडल दरअसल एक नीतिगत स्कैंडल है और वह वह तथ्य है कि उन्होंने अपनी नीतियां खुद लिख लीं।

नीति नियम
मिहिर शर्मा

यहां भारतीय जनता पार्टी के सामने आई उस समस्या की झलक दिखती है, जब उसे चुनावों में संवैधानिक गारंटी वाले आरक्षण से जूझना पड़ा था। नीतिगत प्रस्ताव महत्त्वपूर्ण होते हैं और यदि जरूरी हो तो आपको या आपकी पार्टी को परिभाषित भी कर सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम में लेबर पार्टी ने इस वर्ष के आरंभ में संसदीय चुनाव में अपने घोषणापत्र को जिस प्रकार से पेश किया गया था, वह इसका उदाहरण हो सकता है। उनके दावों का सबसे अहम पहलू यह था कि सबकी कीमत बताई गई थी। दूसरे शब्दों में उनके घोषणापत्र में हर चीज के बारे में साफ और पारदर्शी तरीके से बताया गया था कि उससे राजकोष पर कितना बोझ पड़ेगा। इससे पार्टी का वाम धड़ा नाराज हो गया। परंतु यह कियर स्टार्मर की लेबर पार्टी को उनके पूर्ववर्ती जेरेमी कॉर्बीन की लेबर पार्टी से अलग दिखाने का एक उपयोगी तरीका था, जिनके 2019 के अभियान में सभी प्रकार के खर्च के वादे शामिल थे। इनमें से कुछ वादे तो अंतिम दिनों में बिना किसी खास सोच विचार के जोड़े गए थे।

इस बात ने लेबर पार्टी को कंजरवेटिव पार्टी से भी अलग किया जिसने लिज ट्रस्ट के अल्पकालिक प्रशासन में अप्राप्त कर कटौती प्रस्तावों के बाद गैर जवाबदेही से ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था। किसी चुनाव में नीतिगत दलीलें तब टिककर कर सकती हैं, जब आने वाले समय में आपको शासन करना हो। लेबर पार्टी ने प्रायसियों के साथ कठोरता बरतने की नीतियों का वादा किया था, लेकिन उसने इस सवाल को हल नहीं किया कि एकीकरण और आत्मसात करने के सवालों से घरेलू स्तर पर कैसे निपटा जाए। परंतु अब इनमें से बाद वाला बिंदु आम प्राथमिकता है क्योंकि इस महीने देश के अलग-अलग हिस्सों में दंगे देखने को मिले। सरकार पहले किए गए वादे के बजाय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में व्यय बढ़ाने के बहाने तलाश रही है।

अगर हैरिस चुनाव जीतती हैं तो उन्हें खुद को उस कदर नहीं रोकना होगा। आखिर में अमेरिकी चुनाव में जो मुद्दे आहम होंगे वे हैं- गर्भपात, मुद्रास्फीति और अमेरिकी लोकतंत्र की स्थिति। ये सभी ऐसे मुद्दे नहीं हैं, जिन पर राष्ट्रपति पहले दिन या पहले साल नीतिगत घोषणा करके नियंत्रण हासिल कर लें। यहां उनका तर्क अनिवार्य रूप से नकारात्मक है कि नीति और प्रशासन को लेकर दूसरे प्रत्याशी का रुख गलत है और उनका सही। अनुभूतियों और नीतियों के बीच की सीमा संकीर्ण है। भारत में यह आम रुख है। कुछ चुनावों के नतीजे घोषणा पत्रों से तय हुए हैं लेकिन अक्सर घोषणा पत्रों को ऐसे निर्देश के रूप में देखा गया है कि प्रतिद्वंद्वी दल किस प्रकार शासन करेंगे। कम से कम एक प्रमुख दल यानी बहुजन समाज पार्टी ने दशकों पहले घोषणापत्र की परंपरा को ही बंद कर दिया। उसके नेताओं ने उचित ही दावा किया कि अतीत से चली आ रही प्रतिकूलताओं और विभाजनों से परिभाषित देश में जहां नीति की दिशा पर उचित आम सहमति है, वह अहम है कि प्रशासन कितना प्रभावी और समावेशी हो सकता है।

यह ध्यान देना होगा कि अतीत में बहुजन समाज पार्टी को इसमें उल्लेखनीय सफलता भी मिली है। यह राह दिखा सकता है कि विपक्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किस प्रकार निपटना चाहिए। मोदी का लंबे समय से चला आ रहा सत्ता प्रतिष्ठान लक्ष्य तय करना पसंद करता है, लेकिन वह हमेशा उन सुधारों पर आगे नहीं बढ़ता जो उन लक्ष्यों की प्राप्ति को संभव बना सकते हैं। यहां कहा जा सकता है कि मतदान करने वाले मोदी और उनकी पार्टी पर भरोसा करते हैं कि वे किसी अन्य विकल्प की तुलना में बेहतर ढंग से लक्ष्य प्राप्त करेंगे। विपक्ष किसी भी नीति या सुधार के अंतिम तौर पर घोषित होने पर उसकी आलोचना कर रहा है चाहे मामला कृषि का हो, जमीन का या लैटरल एंट्री अर्थात सीधी भर्ती का। उन्हें जनता को यह विश्वास दिलाना होगा कि जो भी नीतियां चुनी जाती हैं उन्हें लागू करने के लिए मौजूदा लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह ज्यादा कठिन है।

आपका पक्ष

भारत के परिप्रेक्ष्य में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव

लेख 'अमेरिकी चुनाव के बीच भारत की रणनीति' एक सम्यक विश्लेषण है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों में मुख्य निर्णयात्मक विषय हैं- इजरायल-गाजा युद्ध, रूस-यूक्रेन युद्ध, आव्रजन, घरेलू आर्थिक स्थिति और सामरिक दृष्टि से हिंद महासागर में चीन की वर्चस्ववादी एवं आक्रामक नीतियां। यह महत्त्वपूर्ण नहीं है कि चुनाव सर्वेक्षण में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस आगे हैं या रिपब्लिकन उम्मीदवार डॉनल्ड ट्रंप क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप की संभावनाएं और नैरेटिव रहते हैं। अमेरिकी जनमानस बहुत सजग और प्रबुद्ध है और निश्चित रूप से अमेरिका विश्व की राजनीति को प्रभावित करता है। इजरायल -गाजा और रूस-यूक्रेन की परिणति निश्चित रूप से अमेरिकी चुनावों को प्रभावित कर सकती है परंतु उलट-फेर नहीं कर सकती। चीन की भी वर्चस्ववादी, विस्तारवादी, आक्रामक नीतियों और डराने वाले व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता इसलिए दक्षिण पूर्व एशिया और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नीति को सुदृढ़ता से आगे बढ़ाने वाला राष्ट्रपति ही वैश्विक संतुलन स्थापित कर सकता है। भारत को नए अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ व्यापारिक एवं रक्षा समझौतों के साथ चलना होगा। भारत और अमेरिका के संबंधों में कोई परिवर्तन की संभावना नहीं है।

विनोद जौहरी, दिल्ली

डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार टिम वॉल्ज एक कार्यक्रम में

देश में स्थायी विस्थापन एक बड़ा मुद्दा

देश में आवासीय समस्या एक बड़ा मुद्दा है। जीवनयापन की बुनियादी सुविधाओं से महरूम लोग अक्सर झोपड़ियों, सड़कों नदी आदि के किनारे बसते हैं। दोनों ही क्षेत्र दुर्घटना संभावित हैं ऐसे में जानमाल की हानि का बड़ा अंदेशा रहता है। सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिये गरीबों को पक्के मकान आवंटित कर रही है इससे निश्चित रूप से लोगों का जीवन स्तर सुधरा है। बावजूद इसके अभी जरूरतमंदों की लंबी लाइन है जिन्हें प्राथमिकता के साथ पूरा करना होगा। ऐसे आवासहीन लोगों को सबसे पहले इस योजना का लाभ मिले ऐसी व्यवस्था जरूरी है। रोटी, कपड़ा और मकान मानव जीवन की पहली जरूरत है। रोटी, कपड़े की पूर्ति तो व्यक्ति अपनी दैनिक मेहनत से कर ही लेता है लेकिन खुद का मकान एक बड़ा सपना होता है जो कड़ी मेहनत के बाद ही संभव है। जमीनों के बढ़ते दाम में किसी गरीब का मकान खरीदना सहज नहीं होता है। ऐसे में जरूरी यह हो जाता है कि सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना में सबसे पहले ऐसे लोगों को स्थानांतरित करें।

अमृतलाल मारू, इंदौर

ग्रामीण अंचल में खेल प्रतिभाओं पर ध्यान दें

खेल प्रतिभाओं की पहचान और पोषण के लिए हमारा कैचमेंट एरिया केवल शहरी क्षेत्र तक ही सीमित है। ग्रामीण क्षेत्र में भी खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। जरूरत सही समय पर उनकी प्रतिभा की पहचान करने की है। इसके लिए एक सुनियोजित योजना बनाकर चरणबद्ध रूप से उन्हें प्रशिक्षण एवं सुविधाएं दी जानी चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा खेलों के स्तर में सुधार हेतु पर्याप्त धन आवंटन करने पर ही ओलिंपिक में हमारा प्रदर्शन सुधर सकता है।

कृतिका अग्रवाल, मुंबई

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने गोवा में गुरुवार को भारतीय तटरक्षक बल के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत 'जीएसएल यार्ड 1267' का जलावतरण किया। इसकी लागत करीब 2,500 करोड़ रुपये है।